



# जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

## मुशरफ को देशद्रोह के मामले में मौत की सजा

इस्लामाबाद, 17 दिसंबर (भाषा)।

पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशरफ को यहां की एक विशेष अदालत ने संविधान बदलने के लिए देशद्रोह के मामले में मंगलवार को मौत की सजा सुनाई। वह पहले ऐसे सैन्य शासक हैं जिन्हें देश के अब तक के इतिहास में मौत की सजा सुनाई गई है। वहीं, पाकिस्तान की सेना ने कहा कि मुशरफ कभी भी देशद्रोही नहीं हो सकते।

पेशावर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ की अध्यक्षता में विशेष अदालत के तीन सदस्यीय पीठ ने 76 वर्षीय मुशरफ को लंबे समय से चल रहे देशद्रोह के मामले में मौत की सजा सुनाई। अदालत के फैसले पर सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा, 'पूर्व सैन्य प्रमुख, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी के पूर्व अध्यक्ष और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति (परवेज मुशरफ) ने 40 वर्षों से ज्यादा समय तक देश की सेवा की। देश की रक्षा के लिए युद्ध लड़ने वाला निश्चित तौर पर देशद्रोही



पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार किसी पूर्व सैन्य प्रमुख को देशद्रोही करार देकर मौत की सजा सुनाई गई है। बाकी पेज 8 पर

जनसत्ता संवाददाता/भाषा नई दिल्ली, 17 दिसंबर।

दिल्ली के जामिया इलाके में स्थिति शांत भी नहीं हुई कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन में हिंसा भड़क उठी। उग्र प्रदर्शनकारियों ने दो पुलिस चौकियों में आगजनी की। तीन बसों और कई मोटरसाइकिलों में आग लगा दी गई। इस घटना में सात स्थानीय निवासी और 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में दो थानों में मामला दर्ज किया है। पांच लोग गिरफ्तार किए गए हैं।

मंगलवार रात में ब्रिजपुरी में भी प्रदर्शन हुए और लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना रात करीब साढ़े आठ बजे हुई। हालांकि, अब स्थिति नियंत्रण में कर ली गई है। उधर, दिल्ली के पुलिस आयुक्त अमृत्यु पटनायक ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान जामिया और सीलमपुर में हुई हिंसा और राष्ट्रीय राजधानी की मौजूदा स्थिति के बारे में मंगलवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि माना जाता है कि गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने तीन दिन के भीतर हुई इन दोनों घटनाओं पर अप्रसन्नता व्यक्त की है।

दो पुलिस चौकियों में आगजनी, पांच हिरासत में सात स्थानीय लोग, 11 पुलिसकर्मी जख्मी ब्रिजपुरी में भी प्रदर्शन और पुलिसकर्मियों पर पथराव

## नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन

# सीलमपुर में हिंसा, आगजनी



सीलमपुर में मंगलवार को नागरिकता कानून के खिलाफ आगजनी और पथराव करते प्रदर्शनकारी।

### 'हाई कोर्ट जाएं याचिकाकर्ता'

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 17 दिसंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसक विरोध की घटनाओं की जांच के लिए शीघ्र अदालत के पूर्व न्यायाधीश

### पुलिस को इजाजत नहीं दी : प्रशासन

नई दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा)।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया प्रशासन ने इनकार किया कि चीफ प्रॉक्टर ने पुलिस को विविध परिसर में घुसने की इजाजत दी थी। जैसे बिना इजाजत के पुलिस के परिसर में घुसने की सबसे पहले प्रॉक्टर ने ही निंदा की थी।

### राष्ट्रपति से मिले विपक्षी नेता

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 17 दिसंबर।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुआई में एक दर्जन विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर उन्हें

## नागरिकता कानून में कुछ भी अल्पसंख्यक विरोधी नहीं : शाह

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 17 दिसंबर।

गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि नागरिकता कानून में कुछ भी अल्पसंख्यक विरोधी नहीं है। नागरिकता कानून पर विपक्ष दुष्प्रचार में शामिल है। उन्होंने कहा कि चाहे

सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुसलिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता हासिल हो और वे देश में सम्मान के साथ जी सकें। शाह ने नए कानून का विरोध करने वालों को चुनौती देते हुए कहा कि वे जितना चाहें कानून का विरोध कर सकते हैं। उन्होंने नई दिल्ली और मुंबई में के प्रावधानों के मुताबिक, केंद्र अलग-अलग बाकी पेज 8 पर



## हिंसक प्रदर्शनों पर रेल राज्य मंत्री ने दिया विवादित बयान

बेंगलुरु : नागरिकता कानून के विरोध में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के बीच केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है।

## ठंड से ठिठुरे दिल्लीवासी

देश के अन्य हिस्सों में भी सर्दी का सितम जारी

नई दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा)।

राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को लोगों को सुबह ठंड के कहर का सामना करना पड़ा। इससे पहले सोमवार को दिल्ली में पिछले 16 साल में सबसे अधिक ठंडा दिन रहा। वहीं देश के अन्य कई हिस्सों में भी सर्दी का सितम जारी है। मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के अधिकतर हिस्सों में मंगलवार को कड़ाके की ठंड रही। अधिकारी ने बुधवार को दिन में आसमान साफ रहने और अधिकतम तापमान लगभग 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान व्यक्त किया है। अधिकारी ने बताया कि मंगलवार सुबह साढ़े आठ बजे हवा में सापेक्ष आर्द्रता 85 प्रतिशत रही। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 162 रहा।



लद्दाख, जम्मू-कश्मीर में ताजा बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड

सोमवार को दिल्ली में पिछले 16 साल में सबसे अधिक ठंडा दिन रहा था, जब अधिकतम तापमान सामान्य से 10 डिग्री कम 12.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देश के अन्य कई हिस्सों में भी सर्दी

## प्रधानमंत्री ने भोगनाडीह की रैली में कहा

# शहरी नक्सली भड़का रहे हैं युवाओं को

रांची/भोगनाडीह, 17 दिसंबर (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संशोधित नागरिकता कानून से किसी भारतीय को कोई नुकसान नहीं होने का दावा दोहराते हुए कहा कि शहरी नक्सली देश में समस्या पैदा करने के लिए युवाओं को भड़का रहे हैं। साथ ही कांग्रेस समेत विपक्ष को यह सार्वजनिक ऐलान करने की चुनौती दी कि वे सभी पाकिस्तानियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए तैयार रहें।

मोदी ने झारखंड के भोगनाडीह में एक चुनावी रैली में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून ना तो किसी भारतीय के अधिकार लेता है, ना ही उसे किसी भी तरह नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने नागरिकता कानून को लेकर कांग्रेस पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी



पार्टी भारत में मुसलमानों के लिए डर का माहौल बना रही है। भोगनाडीह में उन्होंने कांग्रेस पर संशोधित नागरिकता कानून को लेकर झूठ फैलाने व मुसलमानों के बीच डर का माहौल बनाने का

भोगनाडीह में प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस नागरिकता कानून को लेकर मुसलमानों के बीच डर का माहौल बना रही है। उन्होंने कहा कि मैं आश्वासन देता हूँ कि देश का कोई भी नागरिक इस कानून से प्रभावित नहीं होगा। उन्होंने छात्रों से लोकतांत्रिक तरीकों से अपने विषय उठाने की अपील की।

आरोप लगाते हुए छात्रों से लोकतांत्रिक तरीकों से अपने विषय उठाने की अपील की। मोदी ने यहां चुनावी रैली में संशोधित कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों से अपील की

## अभिनेता और रंगकर्मी श्रीराम लागू का निधन

पुणे, 17 दिसंबर (भाषा)।

मशहूर अभिनेता डॉ. श्रीराम लागू का वृद्धावस्था से संबंधित बीमारियों के चलते मंगलवार शाम पुणे स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वह 92 वर्ष के थे। उनके परिवार के सूत्रों ने यह जानकारी दी। नाटककार सतीश आलेकर ने बताया, 'मैंने उनके दामाद से बात की। वृद्धावस्था संबंधित बीमारियों के कारण उनका निधन हुआ।' प्रशिक्षित ईएनटी सर्जन लागू ने विजय तेंदुलकर, विजय मेहता और अरविंद देशपांडे के साथ आजादी के बाद वाले काल में महाराष्ट्र में रंगमंच को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थी।



## सेना ने तीन घुसपैठिए और दो पाकिस्तानी कमांडो किए ढेर

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 17 दिसंबर।

घुसपैठ की कोशिश के दौरान भारतीय सैनिकों की कार्रवाई में पाकिस्तानी कमांडो दस्ते का हमला सोमवार रात को नाकाम कर दिया गया। भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी फौज के दो कमांडो ढेर कर दिए। उनके साथ आने वाले तीन घुसपैठिए भी मार गिराए गए।

इस कार्रवाई में सेना का एक हवलदार और एक राइफलमैन शहीद हो गए। एक जवान की पहचान हवलदार सीजे गणपति और दूसरे की राइफलमैन सुखविंदर सिंह के रूप में की गई है। भारतीय सैनिकों की कार्रवाई में सीमा से लगे पाकिस्तान की सैन्य चौकियों को भी बहुत नुकसान पहुंचा है।

पाकिस्तान की ओर से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागी गई। साथ ही, मोर्टार और तोपखाने से भी गोलाबारी

सेना के हवलदार और एक राइफलमैन शहीद सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से दागे गए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मोर्टार व तोपखाने



बाकी पेज 8 पर

## समुद्री लुटेरों ने गिनी की खाड़ी में 20 भारतीयों को अगवा किया

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 17 दिसंबर।

पश्चिमी अफ्रीका स्थित गिनी की खाड़ी में समुद्री लुटेरों ने तेल 'एमटी ड्यूक' पर हमला कर 20 भारतीयों को अगवा कर लिया। यह जहाज अंगोला के लुंडा से लुम (टोगो) जा रहा था। लुटेरों ने जहाज पर मौजूद नाइजीरियाई नागरिकों को छोड़ दिया।

चालक दल के भारतीय सदस्यों को लुडाने के लिए विदेश मंत्रालय ने कार्रवाई शुरू

की है। अबुजा स्थित भारतीय मिशन नाइजीरियाई अधिकारियों के जरिए बातचीत में जुट गया है। इस साल इस क्षेत्र में अपहरण की यह तीसरी घटना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार के मुताबिक, यह घटना 16 दिसंबर सुबह की है। जहाज एमटी ड्यूक के चालक दल के 20 सदस्यों का अपहरण चिंता का विषय है।

अबुजा स्थित हमारे अधिकारियों ने इस विषय को नाइजीरिया और पड़ोसी देशों के सामने उठाया है। जहाज

बाकी पेज 8 पर

## आउटगोइंग कॉल पर शुल्क एक साल के लिए बढ़ाया

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 17 दिसंबर।



ट्राई का निर्णय, जारी रहेगा कॉल पर छह पैसे प्रति मिनट का शुल्क

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने किसी ऑपरटर के नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर की जाने वाली मोबाइल कॉल पर छह पैसे प्रति मिनट के शुल्क को एक साल के लिए बढ़ा दिया है। अब यह शुल्क 31 दिसंबर, 2020 तक जारी रहेगा। ट्राई के सचिव एसके गुप्ता की ओर से मंगलवार को जारी सूचना के मुताबिक वायरलेस से वायरलेस धरेलु कॉल पर छह पैसे प्रति मिनट का टर्मिनेशन शुल्क 31 दिसंबर, 2020 तक जारी रहेगा। पहले यह शुल्क 14 पैसे प्रति मिनट था। एक अक्टूबर, 2017 को इसे घटा कर छह पैसे प्रति मिनट किया गया था। एक जनवरी, 2020 से इस शुल्क को समाप्त किया जाना था। नियामक ने कहा कि

## पंद्रह फरवरी से होंगी सीबीएसई की परीक्षाएं

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 17 दिसंबर।

सीबीएसई ने बारहवीं और दसवीं कक्षा का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके मुताबिक दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 15 फरवरी 2020 से शुरू होंगी। दसवीं की परीक्षाएं 20 मार्च और बारहवीं की परीक्षाएं 30 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज के मुताबिक दोनों कक्षाओं के वोकेशनल विषयों की परीक्षाएं पहले और मुख्य विषयों की परीक्षाएं बाद शुरू होंगी। दसवीं के मुख्य विषयों की परीक्षाएं 27 फरवरी और बारहवीं के मुख्य विषयों की परीक्षाएं दो मार्च से शुरू होंगी। परिणाम मई में जारी किया जाएगा।

बंगलुरु, 17 दिसंबर (भाषा)।

कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के बंतवाल के पास एक विद्यालय प्रबंधन के पांच सदस्यों के खिलाफ छात्रों द्वारा संस्था के वार्षिक खेल दिवस के दौरान कथित रूप से चाबरी ढांचा विध्वंस का नाट्य रूपांतरण दिखाने पर मामला दर्ज किया गया है। पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी और केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा समेत कई गणमान्य लोग रविवार को हुए इस कार्यक्रम में मौजूद थे।

तृतीय शहर मंगलुरु से करीब 30 किलोमीटर दूर कल्लाडका में श्री राम विद्या मंदिर का संचालन करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता कल्लाडका प्रभाकर भट (ए) और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295 (ए) और 298 (धार्मिक भावनाएं आहत करने) के तहत मामला



दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई इसी इलाके में रहने वाले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेता अनुबकर सिद्दीकी की शिकायत पर की है।

## आधे मिनट का वीडियो

दक्षिण कन्नड़ जिले के पुलिस अधीक्षक बीएम लक्ष्मी प्रसाद ने बताया, 'पीएफआइ कार्यकर्ता से शिकायत मिलने के बाद हमने विद्यालय प्रबंधन से जुड़े पांच लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। जांच जारी होने की वजह से हमने अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। करीब आधे मिनट का एक वीडियो है जिसके आधार पर शिकायत दर्ज की गई है। हम साक्ष्य जुटा रहे हैं।'

दक्षिण कन्नड़ जिले के पुलिस अधीक्षक बीएम लक्ष्मी प्रसाद ने बताया, 'पीएफआइ कार्यकर्ता से शिकायत मिलने के बाद हमने विद्यालय प्रबंधन से जुड़े पांच लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। जांच जारी होने की वजह से हमने अभी किसी

को गिरफ्तार नहीं किया है। करीब आधे मिनट का एक वीडियो है जिसके आधार पर शिकायत दर्ज की गई है। हम साक्ष्य जुटा रहे हैं।'

किरण बेदी ने ट्वीट कर इस कार्यक्रम की ओर छात्रों के प्रदर्शन की सराहना की थी। उन्होंने कहा कि इन बच्चों को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलना चाहिए। सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम को लेकर तीखी प्रतिक्रिया होने पर भट ने कार्यक्रम का बचाव करते हुए कहा कि यह इतिहास के प्रकरण के बारे में जागरूकता और देशभक्ति की भावना के प्रसार का प्रयास था।

उन्होंने कहा कि छात्र हर साल वार्षिक समारोह के लिए एक प्रासंगिक विषय चुनते हैं और इस बार उच्चतम न्यायालय के फैसले के मद्देनजर उन्होंने अयोध्या का मुद्दा चुना।





केंद्रीय गृह मंत्री ने किया शिलान्यास, 524 करोड़ होंगे खर्च

## 200 एकड़ में बनेगा पहला भारत वंदना पार्क

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 17 दिसंबर। 200 एकड़ क्षेत्र में दिल्ली में पहला भारत वंदना पार्क तैयार होगा। मंगलवार को गृहमंत्री अमित शाह ने इस पार्क का शिलान्यास किया। पार्क को मिनी भारत की थीम पर तैयार किया जाएगा और इस पर करीब 524 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस मौके पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उपराज्यपाल अनिल बैजल व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, सांसद प्रवेश वर्मा भी उपस्थित थे। यह पार्क द्वारका में तैयार किया

जाएगा और मार्च 2022 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पार्क में आसानी से जनता पहुंच सके इनको भी शहरी विकास मंत्रालय ने ध्यान में रखा है। यह पार्क डीडीए तैयार करेगा। यह पार्क आइजीआई एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर, द्वारका मेट्रो स्टेशन 9 से 300 मीटर और तैयार हो रहे इंटर नेशनल एक्सप्रेस केंद्र से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर तैयार किया जा रहा है। मंत्रालय का मानना है कि इस पहल ने पार्क को



न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश व दुनिया से आने वाले लोगों को भी यहां तक लाया जा सकेगा। इस केंद्र सरकार को डीडीए बतौर एक पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित करेगा। दावा किया जा रहा है कि इस प्लान के लागू होने से हरित क्षेत्र में 58 फीसद व जलाशय को 11 फीसद तक विकसित करने में मदद मिलेगी। इस पार्क को मास्टर प्लान के प्रावधानों के तहत विकसित किया जाएगा। इस पार्क का 11

फीसद क्षेत्र जलाशय के आसपास विकसित किया जाएगा, जिसका प्रयोग बोटिंग के लिए किया जा सकेगा। इन जलाशय के लिए नजदीक के जल स्रोतों से 200 किलोलीटर प्रतिदिन पानी उपलब्ध कराया जाएगा। यहां आम जनता के लिए बड़ा हरित क्षेत्र होगा जिसका प्रयोग सांस्कृतिक व अन्य गतिविधियों के लिए किया जा सकेगा। यहां सांस्कृतिक केंद्र, लेन रेस्तरां, पेवेलियन व खानपान के केंद्र तैयार किए जाएंगे। इस पार्क को एक हर्बल वाटिका के तौर पर स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र में आने वाले पर्यटकों के लिए पार्किंग की व्यवस्था रहेगी।

## '40 लाख लोगों के सिर से छत छिनने की चिंता दूर की'

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 17 दिसंबर। मंगलवार भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने कहा कि केंद्र सरकार ने कच्ची कॉलोनी में रहने वालों के सिर से छत छिन जाने का डर खत्म किया है। उन्होंने कहा कि इन कॉलोनीयों में रहने वाले लोग लंबे समय से यह मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना रोककर दिल्ली के गरीबों को आवास से वंचित रखा है। वे दिल्ली की 70 विधानसभाओं में आयोजित बाइक रैली के दौरान आम जनता को सम्बोधित कर रहे थे। बाइक रैली कार्यक्रम की अगुआई भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष सुनील यादव ने की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले से इन कॉलोनीयों में खुशी की लहर है। 58 महीनों तक दिल्ली सरकार इस योजना को लागू होने से रोकने के लिए पूर्ण कोशिश की लेकिन वे इसमें कामयाब नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि इन कॉलोनीयों के रहने वाले लाखों लोगों को पहले कांग्रेस और फिर आम आदमी पार्टी ने टगा है। उन्होंने बताया कि अब डीडीए दिल्ली के विभिन्न जगहों पर 50 कैम्प लगाकर रजिस्ट्रेशन का काम कर रही है ताकि लोगों को असुविधा न हो। रजिस्ट्रेशन के काम करने के लिये दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ता भी अलग-अलग टोली बनाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि लोक-लुभावने वादे करने वाली केजरीवाल सरकार के पास अब दिल्ली के लोगों के सवाल का जवाब नहीं है।

## जेएनयू कुलपति के घेराव के आरोप में दो विद्यार्थी को किया गया निलंबित

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 17 दिसंबर। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) कुलपति का घेराव मामले में जेएनयू प्रशासन ने दो विद्यार्थियों पर कार्रवाई की है। दोनों विद्यार्थियों को मामले की जांच पूरी होने तक अकादमिक गतिविधियों से निलंबित करने, छात्रवास से निष्कासित करने और जेएनयू परिसर से बाहर रहने की सजा सुनाई गई है। जेएनयू के प्रॉक्टर की ओर से सोमवार को दोनों विद्यार्थियों का निलंबन जारी किया गया। निर्देश के मुताबिक दोनों विद्यार्थियों के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। विद्यार्थियों के खिलाफ कुलपति और विश्वविद्यालय के अधिकारियों का घेराव करने, कुलपति की कार को क्षतिग्रस्त करने के साथ ही अभद्रता व धक्का-मुक्की करने के साक्ष्य हैं। प्रॉक्टर की ओर से कहा गया है कि इन दोनों विद्यार्थियों को परिसर में किसी ने भी जगह दी, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जेएनयू कुलपति की कार के घेराव का मामला शनिवार को सामने आया था। इस संबंध में कुलपति की ओर से कहा गया था कि जब वह स्कूल ऑफ आर्ट्स

**परिसर में बना पुलिस कैंप**  
 जेएनयू के विद्यार्थियों के मुताबिक परिसर में प्रशासनिक खंड के पास मौजूद एक पार्क में पुलिस कैंप बनाया गया है। टैंट में बने इस कैंप में कुर्सियां भी डाली गई हैं। वहीं, एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक जेएनयू परिसर में कोई कैंप या चौकी नहीं बनाई गई है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद परिसर में कुछ पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इनमें से कुछ पुलिसकर्मी सादा वर्दी में जबकि कुछ पुलिस की वर्दी में रहेंगे।

एंड एग्जिटिक्स गए थे, तो वहां 10 से 15 विद्यार्थियों ने उनका घेराव किया था और विद्यार्थियों ने उन्हें कार से बाहर खींचने की कोशिश की थी। सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें सुरक्षित बचाया। कुलपति के इस आरोप के बाद विद्यार्थियों ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें कुलपति की कार की बोनट में एक विद्यार्थी लटका हुआ नजर आ रहा था और कार तेजी से पीछे की ओर जाती दिख रही थी। वहीं, छात्र संघ ने कुलपति पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब विद्यार्थियों ने कुलपति से शूलक बढ़ाती की लेकर सवाल पूछे थे तो कुलपति सवालों से बचते हुए वहां से भाग गए।

**HDFC MUTUAL FUND SIP KA PEELA KADAM**

**सही अवसरों का लाभ उठाइए**

निवेश कीजिए एचडीएफसी इक्विटी फंड में - मल्टी-कैप फंड

अपने फायनांशियल एडवाइजर से संपर्क करें या 73974 12345 पर मिस्ड कॉल दें.

एचडीएफसी इक्विटी फंड (एक ओपन-एंडेड इन्वेंचरी स्कीम जो मुख्यतः स्टॉक-केप, मिड-केप और स्मॉल-केप स्टॉक्स में निवेश करती है) उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है, जो चाहते हैं:

- दीर्घ अवधि में लंबी वृद्धि/आयों को प्राप्त करना
- मुंबई, इक्विटी और इन्वेंचरी-आधारित इन्वेंचर में निवेश

एचडीएफसी इक्विटी फंड (एचडीएफसी इक्विटी फंड) एक ओपन-एंडेड इन्वेंचरी स्कीम है जो मुख्यतः स्टॉक-केप, मिड-केप और स्मॉल-केप स्टॉक्स में निवेश करती है।

एचडीएफसी इक्विटी फंड (एचडीएफसी इक्विटी फंड) एक ओपन-एंडेड इन्वेंचरी स्कीम है जो मुख्यतः स्टॉक-केप, मिड-केप और स्मॉल-केप स्टॉक्स में निवेश करती है।

एचडीएफसी इक्विटी फंड (एचडीएफसी इक्विटी फंड) एक ओपन-एंडेड इन्वेंचरी स्कीम है जो मुख्यतः स्टॉक-केप, मिड-केप और स्मॉल-केप स्टॉक्स में निवेश करती है।

## 'आप' और कांग्रेस के कई पदाधिकारियों ने ली भाजपा की सदस्यता

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 17 दिसंबर। आम आदमी पार्टी व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। भाजपा में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं में जिला उपाध्यक्ष आदर्श नगर जिला कांग्रेस पार्टी ललित रोहिल्ला, त्रिनगर विधानसभा के प्रभारी आम आदमी पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ पवन कुमार गर्ग, यूथ विंग 'आप' (शक्रपुर मंडल) विशाल मलिक, पूर्व उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी (त्रिनगर) रामधारी शर्मा पंपू पंडित, अध्यक्ष कांग्रेस जेजे सेल (वजीरपुर) डॉक्टर विनोद कुमार, आप संयोजक बंगाली समिती (शक्रपुर) डॉक्टर विकास मलिक सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा नेताओं ने इन्हें पार्टी का पटका पहनाकर सदस्यता दिलाई। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू, प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय समेत अन्य नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे।

## सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं का परीक्षा कार्यक्रम

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 17 दिसंबर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं की तारीख जारी कर दी है। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 15 फरवरी 2020 से शुरू होंगी।

**दसवीं कक्षा की परीक्षा तिथियां**

15 फरवरी को मीडिया, हेल्थ केअर, सुरक्षा, रिटेलिंग, कृषि, ब्यूटी एंड वेलेनेस, फूड प्रोडक्शन, बैंकिंग एंव इंश्योरेंस आदि, 17 फरवरी को गृह विज्ञान, एनसीसी, ई प्रकाशन एवं ई दफ्तर, 20 फरवरी को सूचना प्रौद्योगिकी, मार्केटिंग एंड सेल्स, 24 फरवरी को स्थानीय भाषाएं, 26 फरवरी को अंग्रेजी, 29 फरवरी को हिंदी, 2 मार्च को हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक संगीत, 4 मार्च को विज्ञान, 7 मार्च को संस्कृत, 12 मार्च को गणित (बेसिक और स्टैंडर्ड), 14 मार्च को पेंटिंग, 18 मार्च को सामाजिक विज्ञान और 20 मार्च को कम्प्यूटर ऐप्लीकेशंस, आइसीटी की परीक्षा होगी।

**बारहवीं कक्षा की परीक्षा तिथियां**

15, 17 और 20 फरवरी को वोकेशनल विषयों की परीक्षाएं होंगी, 22 फरवरी को शारीरिक शिक्षा, 25 फरवरी को आंत्रप्रन्यारशिप, ऑफिस प्रॉसिजर, टेक्सटाइल डिजाइन व पारंपरिक भारतीय टेक्सटाइल, 26 फरवरी को वेब ऐप्लीकेशन, 27 फरवरी को अंग्रेजी, 28 फरवरी को संस्कृत, उर्दू, एनसीसी, इंजीनियरिंग साइंस व एअरकंडिशनिंग, 29 फरवरी को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, फैशन स्टडीज आदि, 2 मार्च को भौतिक विज्ञान, 3 मार्च को इतिहास, 4 मार्च को मार्केटिंग, 5 मार्च को अकाउंटेंसी, 6 मार्च को राजनीतिक विज्ञान, 7 मार्च को रसायन विज्ञान, 12 मार्च को पर्यटन, 13 मार्च को अर्थशास्त्र, 14 मार्च को जीवविज्ञान, 16 मार्च को हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक संगीत व टेक्सेशन, 17 मार्च को गणित, 18 मार्च को लीगल स्टडीज, 19 मार्च को स्थानीय भाषाएं, 20 मार्च को हिंदी, 21 मार्च को आइपी व कम्प्यूटर साइंस, 23 मार्च को भूगोल, 24 मार्च को बिजनेस स्टडीज, 26 मार्च को गृह विज्ञान 28 मार्च को बायोटेक्नोलॉजी और 30 मार्च को समाजशास्त्र विषय की परीक्षा होगी।

## प्रधानमंत्री की रैली के लिए भाजपा ने किया भूमि पूजन

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 17 दिसंबर। 22 दिसंबर को रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे। कच्ची कॉलेनियों का पक्का करने के फैसले का स्वागत करने के लिए भाजपा ने यह रैली रखी है। मंगलवार को भाजपा नेताओं ने मैदान में भूमि पूजन व हवन किया और इस कार्य की शुरुआत की। इस मौके पर भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू, प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, केन्द्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, राज्यसभा सांसद विजय गोयल, नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता, प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, प्रदेश महामंत्री कुलजीत सिंह चहल, सहित प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी, मोर्चा अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक, निगम पार्थद एवं भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे।

**सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी**

**विज्ञापन-1/2019**

विभिन्न शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय के वेबसाइट [www.ssvv.ac.in](http://www.ssvv.ac.in) पर उपलब्ध है।

कुलसचिव

भारतीय स्टेट बैंक		साब शाखा: सहारनपुर रोड, देहरादून			
STATE BANK OF INDIA		(विषय 8(1) के तहत कब्जा नोटिस (अचल सम्पत्ति हेतु))			
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 की राय पढ़ते हुए अनुच्छेद-13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी के नाम के सामने दर्शाये गये खाते में उनके नाम के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख / उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों में बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया था।					
ऋणी द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर ऋणी और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने खाते के सामने दी गई तारीख को उक्त नियमों के नियम-8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इन सम्पत्तियों से किसी प्रकार का लेन-देन भारतीय स्टेट बैंक, साब शाखा सहारनपुर रोड, देहरादून को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है।					
बंधक सम्पत्तियों को अव्यक्त कराने हेतु उपलब्ध समय सीमा के सम्बन्ध में उच्चारकर्ता को ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की तरफ आमंत्रित किया जाता है।					
क्र. सं.	ऋणी का नाम	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	मांग नोटिस दिनांक	कब्जा लेने की तिथि	बकाया राशि
1.	ऋणी:- मैसर्स सुरेंद्र कुमार एवं कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफिस: 137-बी, नवीन मंडी स्थल, मुजफ्फरनगर (3090)-251001 एवं श्री सुरेंद्र कुमार सिंघल एवं (संव-यूएफ (प्रोपराइटर), 844/1 योगेन्द्रपुरी, मुजफ्फरनगर (3090)-251002 एवं श्रीमती मंजू बाला पत्नी श्री सुरेंद्र कुमार सिंघल, 844/1, योगेन्द्रपुरी, मुजफ्फरनगर -251002 (3090)	व्यावसायिक प्लॉट खसरा नं० 1989, ग्राम- सुनडू, मुजफ्फरनगर भूमि क्षेत्र 1695 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामिनी श्रीमती मंजू बाला पत्नी श्री सुरेंद्र कुमार सिंघल (संव-यूएफ (प्रोपराइटर), 844/1 योगेन्द्रपुरी, मुजफ्फरनगर (3090), दरतावेज नं०/बिक्री विलेख नं० 1776 पेज नं० 179 से 194 वॉल्यूम नं० 2820 दिनांक 22.02.2006 पर पंजीकृत है।	29.08.2019	13.12.2019	1,52,47,335.20/- दिनांक 28.08.2019 + प्रभावी ब्याज एवं अन्य व्यय दिनांक 29.08.2019 से
2.	ऋणी:- मैसर्स संगल एवं कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफिस: 201-बी, नवीन मंडी स्थल, मुजफ्फरनगर (3090)-251001, एवं श्री सुरेंद्र कुमार सिंघल एवं (संव-यूएफ (प्रोपराइटर), 844/1 योगेन्द्रपुरी, मुजफ्फरनगर (3090)-251002 एवं श्रीमती मीनिका संगल पत्नी श्री सुरेंद्र कुमार, 844/1, योगेन्द्रपुरी मुजफ्फरनगर-251001 (3090)।	व्यावसायिक प्लॉट खसरा नं० 693, ग्राम- सिसौना, मुजफ्फरनगर भूमि क्षेत्र 2412.86 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामिनी श्री सुरेंद्र कुमार सिंघल पुत्र श्री दत्तात्रय (संव-रजिस्ट्रार ऑफिस में दर्तावेज नं०/बिक्री विलेख नं० 9375 पेज नं० 325 पेज नं० 551 से 558 वॉल्यूम नं० 2868/2909 एबी दिनांक 29.07.2019 पर पंजीकृत है। एवं संव-रजिस्ट्रार ऑफिस- मुजफ्फरनगर (3090) पर दर्तावेज नं०/बिक्री विलेख नं० 9393 पेज नं० 374/675 से 682 वॉल्यूम नं० 2849/2909 एबी दिनांक 05.09.1986 पर पंजीकृत है।	29.07.2019	13.12.2019	1,51,61,832.77 दिनांक 28.07.2019 + प्रभावी ब्याज एवं अन्य व्यय दिनांक 29.07.2019 से
3.	ऋणी:- मैसर्स कुमार इन्द्रजी, रजिस्ट्रार ऑफिस: प्लॉट नं० 1, बंजरन इंडस्ट्रीयल एस्टेट, मुजफ्फरनगर (3090)-251001 एवं श्री सुरेंद्र कुमार सिंघल एवं (संव-यूएफ (प्रोपराइटर), 844/1 रामपुर तत्सोनी-सदर, मुजफ्फरनगर (3090)-251002 एवं श्रीमती मीनिका संगल पत्नी श्री सुरेंद्र कुमार, 844/1, योगेन्द्रपुरी मुजफ्फरनगर-251001 (3090)।	औद्योगिक सम्पत्ति खसरा नं० 1965, ग्राम- सिसौना, मुजफ्फरनगर भूमि क्षेत्र 1100 वर्ग गज एवं 919.60 मीटर सम्पत्ति स्वामिनी श्री सुरेंद्र कुमार पुत्र श्री सुरेंद्र कुमार एवं श्रीमती मीनिका सिंघल पत्नी श्री सुरेंद्र कुमार (संव-रजिस्ट्रार ऑफिस- मुजफ्फरनगर (3090) में दर्तावेज नं०/बिक्री विलेख नं० 8627 पेज नं० 115 से 120 वॉल्यूम नं० 3937 दिनांक 03.12.1999 पर पंजीकृत है।	29.08.2019	13.12.2019	1,64,31,602.28 दिनांक 28.08.2019 + प्रभावी ब्याज एवं अन्य व्यय दिनांक 29.08.2019 से
दिनांक: 13.12.2019		स्थान: मुजफ्फरनगर	प्राधिकृत अधिकारी		

**indianexpress.com**

**For me stories don't end with coverage.**

**Inform your opinion with comprehensive analysis.**

**The Indian Express. For the Indian Intelligent.**

**The Indian EXPRESS**  
 JOURNALISM OF COURAGE



## हर बच्चे को मिल रहा शिक्षा का अधिकार

## शिक्षा की मशाल से जीवन उजियारा



योगी आदित्यनाथ की सरकार ने स्कूल चलो अभियान, छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मध्याह्न भोजन, मिशन टॉपर, ऑपरेशन कायाकल्प, मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान जैसी अनेक योजनाएं चलाकर उत्तर प्रदेश में शिक्षा को हर विद्यार्थी की पहुंच में ला दिया है।

वर्तमान सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता पर फोकस किया है। उच्च शिक्षा में सत्र नियमित किया गया है। अवस्थापना सुविधाएं बढ़ायी जा रही हैं। 48 नये राजकीय कॉलेजों तथा 2 नये राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की नकलविहीन परीक्षा कराने में सफलता मिली। मात्र एक महीने के रिकॉर्ड समय में परीक्षा कराकर परिणाम घोषित किया गया। एनसीईआरटी की तर्ज पर पाठ्यक्रम अपनाया गया, जिससे अखिल भारतीय सेवाओं में यूपी बोर्ड के विद्यार्थी सफल हो सकें।

- योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

# योगी आदित्यनाथ ने जगाई शिक्षा की अलख, रोशन हुआ उत्तर प्रदेश

**3** उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में नयी अलख जगायी है। 32 महीने के कार्यकाल में प्रदेश में स्कूलों शिक्षा का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की पहुंच सार्वभौमिक हो गई है। आज प्रदेश के हर हिस्से में सरकारी स्कूलों का जाल बिछ चुका है। सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में भी सरकारी स्कूलों ने उपस्थिति दर्ज करा दी है। कई स्कूल तो गुणवत्ता में निजी स्कूलों को भी मात दे रहे हैं।

माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में भी इस सरकार ने उपलब्धियों के कई नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं। 'स्कूल चलो अभियान' में इस वर्ष 1.80 करोड़ बच्चों का नामांकन कराया गया। 15,000 प्राथमिक विद्यालयों और 1000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किया गया। प्रदेश के स्कूलों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किया गया। इन स्कूलों में मदरसे भी शामिल हैं। कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, ड्रेस, स्कूल बैग, स्वेटर, जूता और मोजा का वितरण कराया गया। उन्हें मध्याह्न भोजन योजना से भी लाभान्वित कराया गया। निजी विद्यालयों में ली जाने वाली फीस को विनियमित करने के लिए उत्तर प्रदेश स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2018 लागू किया गया।

स्कूल न आने वाले बच्चों के चिह्नानकन, पंजीकरण और नामांकन के लिए प्रदेश सरकार ने एक नवीन कार्यक्रम 'शारदा-स्कूल हर दिन आये' शुरू किया। इसके तहत 80,836 बच्चों को प्रवेश दिलाया गया।

शिक्षा के महायज्ञ में जाति, लिंग या धर्म पर ध्यान दिये बिना सभी को शामिल करने पर जोर दिया गया है। इसका नतीजा यह हुआ कि आज प्रदेश के ज्यादातर परिवार सार्वजनिक शिक्षा की पहुंच के दायरे में आ चुके हैं। आज सही मायनों में प्रदेश में स्कूलों शिक्षा का सार्वभौमिकरण हुआ है। एक प्रदेश के रूप में 'सभी तक शिक्षा की पहुंच' का लक्ष्य करीब-करीब हासिल कर लिया गया है। इसके सबसे बड़े लाभार्थी ऐसे समुदाय हैं जिनकी पहली पीढ़ी तक शिक्षा की पहुंच बनी है।

**15,000 प्राथमिक विद्यालय और 1,000 उच्च माध्यमिक विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित**



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षक दिवस के अवसर पर 'अध्यापक पुरस्कार समारोह' में शिक्षिका को सम्मानित करते हुए।

### बालिका शिक्षा ग्रेजुएट स्तर तक निःशुल्क

बालिकाओं को ग्रेजुएट स्तर तक निःशुल्क शिक्षा और राजकीय इंटर कॉलेजों में सह शिक्षा की व्यवस्था की गयी। दूरस्थ शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने जाने से बालिकाओं को होने वाली दिक्कतें दूर करने के लिए शैक्षिक दृष्टि से सबसे पिछड़े 25 ब्लॉकों में बालिका छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। 107 ब्लॉकों में बालिका छात्रावास का निर्माण प्रगति पर है।

**45,383 शिक्षकों की भर्ती**  
शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वर्ष 2018 में प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 45,383 अध्यापकों की भर्ती की गयी। ये पद पिछली सरकारों के वक्त से खाली थे।

**69000 शिक्षकों की भर्ती**  
अनिम्न चरण में है।

### माध्यमिक शिक्षा की तस्वीर बदली

माध्यमिक शिक्षा का भी कायाकल्प हुआ है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 149 पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इण्टर कॉलेजों का संचालन शुरू किया। इनमें शिक्षक/शिक्षणेत्र कर्मचारियों के 4,150 पदों का मुजान किया गया। 7 नवीन राजकीय इण्टर कॉलेज एवं एक राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय का लोकार्पण किया गया। 193 नये इण्टर कॉलेज शुरू किये गये और 55 नये इण्टर कॉलेजों की स्वीकृति प्रदान की गयी। हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाएं नकलविहीन हुईं।

### मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान, पुरस्कार

पहली बार, मेधावी विद्यार्थियों को एक लाख रुपये की धनराशि, टैबलेट, मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। 'बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ योजना' के तहत 100 टॉपर छात्राओं, 100 टॉपर एससी/एसटी छात्र-छात्राओं तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा के 300 टॉपर विद्यार्थियों को लैपटॉप दिया गया।

**1.80 करोड़ बच्चों का नामांकन**  
स्कूल चलो अभियान में

**उच्च शिक्षा में इस लिहाज से देशभर में अब्वल है उत्तर प्रदेश**

योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के रूप में अब तक के 32 माह के कार्यकाल में शिक्षा क्षेत्र को जो दृष्टि प्रदान की है। उसका असर दिखने लगा है। आज उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा के कुछ क्षेत्रों में पूरे देश में अब्वल है। ये बातें ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2018-19 में सामने आई हैं। यह एक आधिकारिक सर्वे है, जिसमें देश के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को शामिल किया गया। इसमें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दो बिंदुओं पर यूपी का प्रदर्शन सर्वोत्तम है।

### विद्यार्थियों की संख्या में

इस सर्वे के अनुसार, देश में उच्च शिक्षा के लगभग हर क्षेत्र में छात्रों की संख्या छात्राओं से ज्यादा है। लेकिन दो ऐसे राज्य हैं, जहां यह आंकड़ा उल्टा है। ये दो राज्य हैं उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। यहां उच्च शिक्षा ग्रहण करने के मामले में छात्राओं की संख्या छात्रों से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थानों में पंजीकृत छात्रों की संख्या जहां 49.30 फीसदी है, वहीं छात्राएं 50.70 फीसदी हैं। यह राज्य उच्च शिक्षा में छात्र-छात्राओं की कुल संख्या के मामले में देशभर में पहले स्थान पर है। यानि यहां उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा है।

### शैक्षिक संस्थाओं की संख्या में

छात्र-छात्राओं के बाद शैक्षणिक संस्थाओं की संख्या के मामले में भी उत्तर प्रदेश देश के अन्य सभी राज्यों से आगे है। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा 8077 संस्थान हैं। इसके बाद शीर्ष राज्य हैं - महाराष्ट्र (6662 संस्थान), कर्नाटक (5028), राजस्थान (3723), आंध्र प्रदेश (3540) और तमिलनाडु (3443)।



### शैक्षिक संस्थाओं की संख्या के लिहाज से अग्रणी राज्य

### एक माह पहले ही वितरित होगी छात्रवृत्ति और प्रतिपूर्ति की राशि

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की सरकारी मदद के भुगतान में अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में बदलाव किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर समाज कल्याण निदेशालय उन विद्यार्थियों के खातों में फीस प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की राशि दिसम्बर में ही भेजने की तैयारी में तेजी से जुटा हुआ है। पहले यह मदद 26 जनवरी को मिलती थी।

छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति और फीस प्रतिपूर्ति को पिछले सालों में जो प्रक्रिया अपनायी जाती थी, उसके मुताबिक, जिन छात्र-छात्राओं के आवेदन की प्रक्रिया प्रथम चरण में पूरी हो जाती थी, उन्हें 2 अक्टूबर को और शेष बचे छात्र-छात्राओं को 26 जनवरी को भुगतान किया जाता रहा है। इस बार 2 अक्टूबर को दलित, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के 3 लाख 33 हजार 974 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की रकम जारी कर दी गयी थी। चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के 3 लाख 76 हजार 198 छात्र-छात्राओं के छात्रवृत्ति आवेदन शिक्षण संस्थाओं से अप्रसारित किये गये थे।

### प्रदेश के 2019-20 के बजट में शिक्षा के लिए आवंटन



## चतुर्दिक बदलाव के प्रयासों से उत्तर प्रदेश में बुनियादी शिक्षा का हो रहा कायाकल्प

- ऑपरेशन कायाकल्प से प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के सीखने का स्तर ऊपर उठेगा
- विद्यालयों का स्तर भी बेहतर होगा



'ऑपरेशन कायाकल्प' के अंतर्गत नवीन सुविधाओं से सज्जित विद्यालय।

### 'ऑपरेशन कायाकल्प'

मुख्यमंत्री की परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए संचालित किया जा रहा 'ऑपरेशन कायाकल्प' शिक्षा के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के साथ ही एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण के लिए चलाया गया अभियान है। इसका मकसद यह है कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के पठन-पाठन के स्तर में सुधार किया जाये। विद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाना जाये। स्तर के अनुरूप शिक्षण की व्यवस्था को प्रभावी-डंग से लागू किया जाये। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि किसी भी बच्चे के लिए पठन-पाठन की व्यवस्था उसके वास्तविक शैक्षिक स्तर को चिन्हित करते हुए की जायेगी।

स्वकेन्द्र परीक्षा प्रणाली, सपुस्तक परीक्षा प्रणाली और कक्षा आठवीं तक किसी विद्यार्थी को फेल न करने की नीतियों ने प्रदेश में शिक्षा का स्तर बहुत नीचे गिरा दिया था। कक्षा 3 का बच्चा हिन्दी की एक लाइन नहीं पढ़ पाता था। कक्षा 5 का बच्चा दो अंकों की संख्या जोड़ नहीं पाता था। समय-समय पर होने वाले सर्वे में यह तथ्य सामने आते रहे हैं। शिक्षा को गत से निकाल कर फिर से पटरी पर लाने के लिए प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से 'ऑपरेशन कायाकल्प' संचालित कर रही है।

यह अभियान कक्षा 1 से 5 तक के लिए चलाया जा रहा है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और नेशनल अचीवमेंट सर्वे में सामने आता रहा कि जो लर्निंग इंटीकेटर निर्धारित किये गये हैं, वहां तक बच्चे पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए बच्चों को लर्निंग इंटीकेटर तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाया जाएगा।

इस अभियान में प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को दो समूहों में बांट कर पढ़ाया जायेगा। कक्षा 1 व 2 के बच्चे एक समूह में होंगे और कक्षा 3, 4, 5 के बच्चे दूसरे समूह में। इसके लिए कक्षा आधारित स्तर नहीं, बल्कि बच्चों के स्तर के मुताबिक सीखने-सिखाने की प्रक्रिया शुरू की गयी। इस कार्यक्रम का बेसलाइन, छमाही व वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा। छमाही सितम्बर में और वार्षिक मूल्यांकन फरवरी में किया जाता है। कक्षा 1 व 2 में सरल वाक्यों को पढ़ना, 1 से 20 अंकों को पहचानना, 20 तक के अंकों के साथ जोड़-घटाव आना चाहिए। वहीं कक्षा 3 से 5 में सरल अनुच्छेद पढ़ना, मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति और 100 तक के अंकों को पहचानना शामिल है।

इसके तहत 91,236 स्कूलों में अतिरिक्त क्लास रूम, बाउण्ड्री वाल, गेट, शौचालय, पेयजल व विद्युतीकरण कार्य कराये गये।

### उत्तर प्रदेश के छात्रों को मेधावी बनाएगा सीएम का 'मिशन टॉपर'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'मिशन टॉपर' के मद्देनजर शिक्षा विभाग बोर्ड परीक्षा देने जा रहे विद्यार्थियों को मेधावी बनाएगा। यूपी, सीबीएसई और आइसीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों, उनके विद्यालयों एवं अभिभावकों के लिए गाइडलाइन जारी की गयी है।

- बोर्ड परीक्षा के समय विद्यार्थी **ये हैं निर्देश**
- प्री-बोर्ड परीक्षा के प्रश्नपत्र से काफी तनाव में होते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को काउंसिलिंग कराई जाए।
- प्री-बोर्ड परीक्षा के परिणाम के आधार पर जनपद की वेबसाइट पर अपलोड करें। चिन्हित कर निवारण करें।
- मॉडल पेपर से अभ्यास कराया जाए।
- प्री-बोर्ड परीक्षा में सर्वोच्च अंक पाने वाले विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका कॉलेज और जनपद की वेबसाइट पर अपलोड करें।
- कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त शिक्षण कक्षाओं की व्यवस्था की जाए।



### टॉपर्स के नाम से बनेगी सड़क

माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, सीबीएसई, आइसीएसई की 10वीं व 12वीं की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री अमल सत्र में भी एक लाख रुपये, टैबलेट, मेडल और प्रमाणपत्र तो देगे ही टॉपर के नाम से उसके घर में पक्की लिक रोड का निर्माण किया जाएगा।

### स्कूलों पर नजर रखेंगे रिसोर्स टीचर

बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से कुछ माह पूर्व मानीटरिंग व्यवस्था को टुकटुक करने के लिए 'प्रेरणा एप' की शुरुआत की गयी है। इस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए अब विभाग इंटीनेट और रिसोर्स टीचरों के जरिये प्रदेश के सभी परिषदीय स्कूलों को मॉनिटरिंग करायेंगे। 'प्रेरणा एप' से इन सबको जोड़ा जायेगा। इसके लिए विभाग की ओर उनके प्रशिक्षण की तैयारी की जा रही है। इससे कायाकल्प योजना के जरिये संवारे जा रहे परिषदीय स्कूलों की भौतिक स्थिति और उनका वास्तविक डाटा भी विभाग को त्वरित गति से मिल पायेगा।

### राज्य अध्यापक पुरस्कार की धनराशि ढाई गुना बढ़ायी गयी

अध्यापक भी नये-नये और प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए प्रेरित हों, इस उद्देश्य से राज्य अध्यापक पुरस्कार की धनराशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये की गयी। इसी तरह, मान्यता प्राप्त वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अध्यापकों को मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार देने का निर्णय किया गया है।

## सूचना की सीमा

करीब डेढ़ दशक पहले जब सूचना का अधिकार कानून यानी आरटीआइ एक्ट लागू हुआ, तब उम्मीद की गई थी कि सत्ता और प्रशासन के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए यह एक बड़ा और कारगर औजार बनेगा। काफी हद तक इसका असर इसी रूप में सामने आया है और आज भी इस कानून के सहारे अलग-अलग महकमों से जुड़ी जनहित की जानकारीयां सामने लाई जा रही हैं। यह जनकल्याण के कार्यक्रमों पर कारगर अमल और लोकतंत्र को मजबूत करने के मामले में एक ठोस कानून साबित हुआ है। लेकिन इसके समांतर यह भी सच है कि इस कानून को कुछ लोगों ने कई बार हथियार बना कर भी इस्तेमाल किया। यह भी देखा गया कि आरटीआइ के जरिए निकाली गई किसी सूचना की धौंस देकर संबंधित व्यक्ति के सामने मनमानी मांगें रखी गईं, किसी गोपनीय जानकारी को सार्वजनिक कर देने की आपराधिक धमकी दी गई और एक ब्लैकमेल किया। हालांकि इस तरह के मामले आम नहीं रहे, फिर भी अगर किसी शकल में आरटीआइ एक्ट को कोई व्यक्ति अपना स्वार्थ साधने का जरिया बनाता है तो यह न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि इस कानून के बुनियादी स्वरूप का भी बेजा इस्तेमाल है।

शायद यही वजह है कि सुप्रिम कोर्ट ने आरटीआइ का दुरुपयोग रोकने और इसके माध्यम से ‘आपराधिक धमकी’ पर रोक लगाने के लिए एक मुकम्मल दिशानिर्देश बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। इस मसले पर दायर एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि कुछ लोग आरटीआइ दाखिल करने के विषय से किसी तरह संबंधित नहीं होते; यह कई बार आपराधिक धमकी की तरह होता है, जिसे ब्लैकमेल करना भी कहा जा सकता है। ऐसी खबरें भी आई कि आरटीआइ के तहत सवालों का जवाब देने की वजह से किसी विभाग के सामान्य कामकाज में बाधा आई। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से अदालत की चिंता वाजिब है और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एक प्रभावी प्रणाली बनाई जानी चाहिए। एक बेहद उपयोगी कानून का गलत मंशा से किया गया इस्तेमाल आखिरकार इसके बुनियादी मूल्यों को खत्म कर देगा। अगर यह प्रवृत्ति सामने आती है तो इस पर रोक के लिए ठोस दिशानिर्देश बनाए जाने चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ यह भी ध्यान रखे जाने की जरूरत है कि अपने लागू होने के बाद से ही इस कानून ने शासकीय कामकाज में पारदर्शिता लाने में जितने बड़े मददगार की भूमिका निभाई है, उसकी वह अहमियत बरकरार रहे।

यह किसी से छिपा नहीं है कि आरटीआइ कानून के लागू होने के पहले समूचा सत्ता-तंत्र जनता की सामान्य पहुंच से एक तरह से बाहर था और किसी काम के बारे में जानकारी प्राप्त करना लगभग असंभव था। इसका नतीजा यह हुआ कि सरकारी तंत्र में पारदर्शिता का अभाव एक चरित्र बन गया और इसका नुकसान लगभग हर स्तर पर देश की जनता और जनहित के व्यापक सरोकार को हुआ। लेकिन इस कानून के आने के बाद लोगों को एक सीमित सहारा मिला और इसके जरिए वे संबंधित जानकारी पाने के अधिकार से लैस हुए। इससे इस कानून की अहमियत ही साबित होती है। ऐसे में अगर सूचनाधिकार कानून के दुरुपयोग पर रोक लगाने का एक तंत्र बन जाए तो इसकी उपयोगिता एक साबित हकीकत है। हालांकि यह भी सच है कि इसके दुरुपयोग के कुछ मामले सामने आए, जो अक्सर चिंता की वजह बने। इसके बरक्स इसके उपयोग से जरूरी जानकारीयां जनता के सामने लाने वाले कई आरटीआइ कार्यकर्ताओं की हत्या भी हुई। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि जानकारी से लैस समाज ही जागरूक हो सकता है और आखिरकार यह देश को मजबूत करने का जरिया बनता है।

## मुशर्रफ को सजा

लंबे समय से देशद्रोह के मुकदमे का सामना कर रहे पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को मौत की सजा सुना कर विशेष अदालत ने यह संदेश दिया है कि पाकिस्तान में न्याय अभी जिंदा है और कानून से ऊपर कोई नहीं है। अदालत का यह फैसला बता रहा है कि तमाम दबावों और संकटों के बावजूद पाकिस्तान की न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करती है। फांसी की सजा तो दूर, मुशर्रफ को सजा मिलेगी भी या नहीं, इसे लेकर ही पाकिस्तान में संशय बना हुआ था। मुशर्रफ सिर्फ देश के राष्ट्रपति ही नहीं रहे, वे पाकिस्तान के सैन्य शासक, देश के सेना प्रमुख, करगिल युद्ध के नायक जैसे रूपों में मील के पत्थर गाड़ते रहे। इसलिए मुशर्रफ को मौत की सजा की खबर चौंकाने वाली है। पाकिस्तान के इतिहास में वे पहले ऐसे सैन्य शासक और राष्ट्रपति हैं, जिसे मौत की सुनाई गई हो। जिस मुल्क में राजनीति से लेकर हर जगह सेना का दबदबा रहता हो और बिना सेना की मर्जी के पता भी नहीं हिल सकता हो, वहां एक पूर्व सैन्य शासक और राष्ट्रपति को फांसी की सजा दिया जाना स्पष्ट रूप से इस बात का संदेश है कि सेना की न्यायपालिका से ऊपर नहीं है। यह उन पूर्व और मौजूदा सैन्य अधिकारियों और राजनीतिकों के लिए भी कड़ा संदेश है कि जो अपने को कानून से ऊपर मान कर चलते हैं।

मुशर्रफ चाहे सेना में रहे हों या राजनीति में, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वे हमेशा ही चतुराई से भरी चालें चलते रहे। 1998 में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सत्ता का तख्तापलट कर देश का सैन्य बनना इस दिशा में पहला कदम था। इसके बाद उन्होंने अपने को पाकिस्तान का सीईओ घोषित कर डाला था। जैसे-जैसे मुशर्रफ की ताकत बढ़ती गई, वे देश के निर्वाचित राष्ट्रपति तक हो गए। 2001 से 2008 तक के राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल में उन्होंने न्यायपालिका, कानून, संविधान को कुछ नहीं समझा। हद तो तब हो गई जब तीन नवंबर 2007 में अपनी शक्तियों के अहंकार में उन्होंने देश के संविधान को निलंबित कर देश में आपातकाल लगा दिया था और पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश सहित साठ से ज्यादा जजों को नजरबंद कर दिया था। यह पाकिस्तान की न्यायपालिका पर सबसे बड़ा संकट था। तब शायद ही उन्हें इस बात का अंदाजा रहा होगा कि सत्ता के दंभ में जो फैसला उन्होंने किया है, वही किसी दिन उनकी मौत का फरमान भी बन सकता है। आज मुशर्रफ को इसी काल की सजा मिली है।

मुशर्रफ के खिलाफ पाकिस्तान की अदालतों में पूर्व प्रधानमंत्री बेनजिर भुट्टो की हत्या, पद के दुरुपयोग जैसे मामले भी चल रहे हैं। वे लंबे समय से दुबई में रह रहे हैं और इन दिनों गंभीर रूप से बीमार हैं। जब 2013 में नवाज शरीफ फिर से सत्ता में लौटे तो 2014 में मुशर्रफ के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा शुरू हुआ। मुशर्रफ खुद इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके थे कि वे अब बच नहीं पाएंगे, इसीलिए उन्होंने लंबे समय तक कानूनी-दांवपेचों का सहारा लिया और विशेष अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। हालांकि विशेष अदालत का यह फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के बावजूद आया है जिसमें विशेष अदालत को फैसला देने से रोक दिया गया था, जबकि उसने 19 नवंबर को यह फैसला सुरक्षित रख लिया था और 28 नवंबर को फैसला सुनाया जाना था। आज मुशर्रफ और नवाज शरीफ दोनों ही एक जैसी हालत में हैं, बीमार और सजायापत्ता। मुशर्रफ को सजा और वह भी फांसी की सजा, देश के सैन्य प्रतिष्ठान को कहीं न कहीं विचलित तो जरूर कर रही होगी!

## कल्पमेधा

**जो दूसरों को जानता है, वह विद्वान है और जो खुद को जानता है, वह ज्ञानी है।**

– लाओत्से

# जनसत्ता

## शोभना जैन

# शोभना जैन

**बांग्लादेश भारत का न सिर्फ पड़ोसी है, बल्कि उसके साथ हमारे प्रगाढ़ रिश्ते हैं। ऐसे में अगर नागरिकता कानून को लेकर मचे बवाल से दोनों के बीच कोई विवाद खड़ा होता भी है तो उसका समाधान कोई जटिल नहीं है। रही बात अमेरिका की, तो भारत सरकार इस बारे में पहले ही साफ कह चुकी है कि इस कानून के बारे में वह अमेरिका में सभी संबद्ध पक्षों को अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर चुकी है।**

# शोभना जैन

चर्चित नागरिकता कानून को लेकर पश्चिम बंगाल, असम और पूर्वोत्तर सहित देश के अनेक भागों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग सड़कों पर हैं। कहीं असंतोष अब कुछ धीमा पड़ रहा है, तो कहीं अभी भी चरम पर है। चिंता की बात यह है कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय किए जाने की तरह ही इस कानून का भी कूटनीति पर प्रतिकूल असर नजर आने लगा है। ऐसे में इसे कूटनीतिक तौर पर भी संवेदनशीलता, अत्यंत सावधानी और दूरदर्शी से काम लेने की जरूरत है। नागरिकता कानून के बाद भारत में बिगड़े हालात के मद्देनजर बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मौमिन ने अपना प्रस्तावित भारत दौरा रद्द कर दिया, वहां के गृह मंत्री असदुज्जामा खान ने पूर्वोत्तर की अपनी निजी यात्रा स्थगित कर दी। गुवाहाटी में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के बाद भारत जापान के बीच गुवाहाटी में होने वाला भारत जापान शिखर सम्मेलन टल गया और जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे की भारत

# शोभना जैन

### आलोक रंजन

तोश के उस छात्रावास में ‘कैंप-फायर’ चल रहा था। आग के चारों ओर बैठे लड़के-लड़कियों में से एक लड़की ने मेरा परिचय पूछा तो मैंने कहा- ‘बिहार का हूं, मैंने दिल्ली में पढ़ाई की, केरल में नौकरी करता हूं। अध्यापक हूं, यात्राएं करता हूं और लिखता भी हूं!’ उसके मुंह से निकला- ‘वाट ए वियर्ड कॉम्बिनेशन!’ इंटरनेट मिल रहा था वहां इसलिए एह सब मैंने फेसबुक पर डाल दिया। ज्यादातर मित्रों ने इसे बिहार की अस्मिता से जोड़ दिया और उस लड़की के विरोध में कुछ बातें कही। फिर एक संवाद आया- ‘एक बिहारी सब पर भारी’। मेरे एक वरिष्ठ मित्र ने इस संवाद पर आपत्ति उठाई कि ‘बिहारी अस्मिता’ के प्रकटन के लिए अक्सर यह मुहावरा ही क्यों कहा जाता है और कैसे एक बिहारी सब पर भारी हो सकता है! जबकि कोई भी मानक उठा लीजिए तो बिहार उसमें नीचे से पहले या दूसरे स्थान पर ही रहता है। बिहारी या बिहार भारी कैसे है सब पर? मित्र की बात बिल्कुल ठीक थी। यात्राओं में जब लोग मिलते हैं तो अक्सर ऐसे संवाद होते हैं। इस पर भड़कना ठीक नहीं है। इधर

### नारा बनाम हकीकत

गांव-कस्बे से लेकर महानगर तक में चढ़ रहे यौन अपराध में यौन शोषण या सामूहिक बलात्कार और हत्या की वादात आम बात जैसी होती जा रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ऐसा समाज ही आज की उत्तर आधुनिक समाज की विशेषता बनती जा रही है। यह सब मानव समुदाय को सोचने के लिए विवश कर रहा है, क्योंकि ऐसा शायद ही किसी दिन रहता होगा कि बलात्कार की खबरें समाचार पत्रों की सुर्खियां न बनते हों। जब इस स्थिति पर कोई नेता टिप्पणी करता है तो उनके विरोधियों में आक्रोश छलकता है, लेकिन इस सच्चाई से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि बलात्कार की घटनाएं सभ्य मानव समुदाय को न केवल चिढ़ा रही हैं, बल्कि सता भी रही हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मसले पर अपनी राजनीति नहीं ही करें तो ही अच्छा है, क्योंकि इस कुकृत्य के शिकार आम आदमी होते हैं। आम लोगों को सुरक्षा की जरूरत है, न कि राजनीतिक नेताओं के दावे और प्रतिदावे की।

आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से देश को बहुत आगे जाने की जरूरत है और बेटियों को सुरक्षा देने की जरूरत है। आज की तारीख में बेटियों की सुरक्षा सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। कहा जाता है कि बेटियों को पढ़ाने से वे अपने बलबूते आगे बढ़ेंगी, जिससे परिवार और समाज का भला होगा, उसे आगे बढ़ने दो। लेकिन निर्भया पढ़ी-लिखी थी, वह यात्रा कर रही थी। फिर भी समाज के दरिदों ने क्या किया, यह दुनिया से छिपा नहीं है। हाल में आंध्र प्रदेश में दिशा के साथ क्या हुआ, वह भी दुनिया ने देखा। वह भी न केवल पढ़ी लिखी थी, बल्कि पढ़-लिख कर अपने पैर पर भी खड़ी थी। डॉक्टर थी। इसके बावजूद वह भी बलात्कार का शिकार हुई और जला कर मार डाली गई। उसके बाद आरोपियों का एनकाउंटर करने की बात को

# शोभना जैन

## कूटनीतिक चुनौतियां और भारत

# कूटनीतिक चुनौतियां और भारत

यात्रा अंतिम समय में स्थगित करनी पड़ी। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया जैसी सोची गई थी, वैसी ही रही। मौका पाते ही उसने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया, जिसका भारत ने करारा जबाव यह कहते हुए दिया कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले पाकिस्तान अपने देश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा पर ध्यान दे, उन्हें संरक्षण दे। अमेरिकी संसद और विदेशी मामलों की संसदीय समिति ने भी इस कानून में मुसलिम समुदाय के प्रति इस भेदभाव किए जाने की बात कहते हुए इस पर तीव्र विरोध जताया है। संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा कि वह इस कानून के संभावित परिणामों का विश्लेषण कर रहा है। बहरहाल यहां इस मुद्दे के कूटनीतिक पहलू की बात करें, तो यह तय है कि विदेश नीति घरेलू नीतियों से एकदम अलग हट कर नहीं रखी जा सकती हैं, लेकिन ऐसे जटिल मुद्दे जो निकट पड़ोस से भी जुड़े होते हैं, उनका जितना जल्द और तर्कसंगत तरीके से सही समाधान हो जाए तो देश की स्थिति के साथ-साथ उनका विदेश नीति पर भी सकारात्मक असर पड़ता है, खासतौर पर ऐसे में जब कि मुद्दा ‘पड़ोसी सबसे पहले’ की नीति से जुड़ा हो। एनआरसी, कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और अब नागरिकता कानून पर पाकिस्तान को छोड़ दें, लेकिन हमारा ऐसा पड़ोसी है जिसने इस बाबत कोई आधिकारिक विरोध या प्रतिक्रिया दर्ज नहीं कराई है।

नागरिकता संशोधन विधेयक अब कानून बन चुका है। इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आए गैर-मुसलिम शरणार्थियों- हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। इसके प्रावधानों में इन देशों में धर्म के आधार पर प्रताड़ित इन छह धर्मों के अनुयायियों में मुसलिम समुदाय के लोगों की भी ऐसी स्थिति में भारत में शरण लेने की पात्रता सूची में नहीं रखे जाने पर नागरिक समाज में असंतोहें हैं और उन्होंने इस कानून को मुसलिम विरोधी करार दिया गया है। लेकिन जैसा कि पहले कहा गया कि इस कानून के जो कूटनीतिक पहलू हैं, उन पर खास ध्यान देने की जरूरत हैं। इस कानून को लेकर पड़ोसी बांग्लादेश ने वैसे तो अभी तक अनौपचारिक प्रतिक्रिया ही जाहिर की है और औपचारिक विरोध व्यक्त नहीं किया है, जिसे भारत और बांग्लादेश मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है। लेकिन भारत में

# शोभना जैन

कोई जटिल नहीं है। रही बात अमेरिका की, तो भारत सरकार इस बारे में पहले ही साफ कह चुकी है कि इस कानून के बारे में वह अमेरिका में सभी संबद्ध पक्षों को अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर चुकी है। भारत का कहना है कि अमेरिका में कांग्रेस और सभी संबद्ध पक्षों से जिस सक्रियता से हम जुड़े हुए हैं, उसके मद्देनजर उम्मीद हैं कि इस कानून पर कोई रुख अख्तियार करने से पहले अमेरिका भारत के पक्ष को समझेगा। दरअसल अमेरिकी संसद अंद्रे कार्सन ने नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर भारत पर हमला करते हुए कहा था कि यह बिल मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश है।

जहां तक सवाल है जापान के प्रधानमंत्री शिंजो

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

# शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन

शोभना जैन



हाल में आए एक विज्ञापन में दिखाया गया है कि जंक फूड केबो संतुलित भोजन की जरूरत पूरा कर सकता है। विज्ञानों में इसे धीमा तरीके विकल्प के तौर पर परोसा जा रहा है। इसे स्वास्थ्यवर्धक खाना की तरह दिखाया जा रहा है। विज्ञानों से बच्चों के जेहन में बिटाया जा रहा है कि इससे स्वास्थ्य को नुकसान नहीं है। जबकि ब्रांड चिकन में 4.6ग्राम नमक व 31.9 ग्राम वसा पाया गया। यानी आरडीए का 92.1 फीसद नमक व 53.2 फीसद वसा पाया गया।

## कुंभ मेले से पहले अखाड़ों में ठनी

सुनील दत्त पांडेय  
देहरादून।

हरिद्वार तीर्थ नगरी में 2021 में लगने वाले कुंभ मेले से पहले ही साधु बाबाओं के अखाड़ों में चहल कदमी शुरू हो गई है। जहां अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेद सिंह रावत से मिलकर कुंभ कार्यों के धीमी गति से होने पर नाराजगी जताई है और मेले के कार्यों को तेजी से करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने अखाड़ा परिषद को उनके कार्य तेजी से शुरू करने और समय पर पूर्ण करने का भरोसा दिया है। अखाड़ा परिषद ने चार धामों और 51 मंदिरों के प्रबंधन के लिए बनाए गए श्राइन बोर्ड के गठन का भी विरोध किया, इस मांग को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है।

वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद पर कुछ साधु संतों ने आरोप-प्रत्यारोप भी लगाए हैं। बैरागी संप्रदाय के दिग्गज अनी अखाड़ा के बाबा हटयोगी ने अखाड़ा परिषद पर कई आरोप जड़े। उन्होंने अखाड़ा परिषद को 'फर्जी' और माफिया की संस्था कहा और हरिद्वार कुंभ मेले के नाम पर पैसों की बंदरबांट का आरोप लगाया।

हटयोगी ने आरोप लगाया कि परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री जैसे अहम पदों पर दशनामी संन्यासी परंपरा के एक ही संप्रदाय के दो अखाड़ों के महंत काबिज हैं और इनकी निगाह सिर्फ कुंभ में आने वाले करोड़ों रूपयों पर ही है। उनका कहना है कि अखाड़ा परिषद के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि संन्यासी अखाड़ों का ही अध्यक्ष और उसी का महामंत्री रहा हो। ऐसा पहली बार हुआ है कि दोनों महत्वपूर्ण पदों पर एक ही संप्रदाय कब्जा करके बैठ गया हो। इसमें दोष उन अन्य संप्रदायों के अखाड़ों का भी है, जो चुप्पी साधे बैठे हैं। इन संप्रदायों की चुप्पी में भी कुंभ मेले के बजट को लेकर बंदरबांट की बू आ रही है।

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का गठन प्रयागराज में 1954 के कुंभ मेले में श्री पंचायती महानिवाणी अखाड़ा में अखाड़े के श्री महंत अनंत नारायण पुरी महाराज ने किया था और परिषद का काम कुंभ मेले में साधु संन्यासियों के शाही स्नानों तथा अन्य व्यवस्थाओं के लिए कुंभ मेला

### उत्तराखंड



अब अखाड़ा परिषद दोबारा अतिरिक्त जमीन की मांग कुंभ के लिए कर रही है जबकि कई अखाड़ों ने अपनी छावनियों की जमीनों पर फ्लैट बनाकर किराए पर चढ़ा दिए गए हैं। बैरागी कैंप की एक इंच भूमि भी दशनामी अखाड़ा को नहीं लेने दी जाएगी और बैरागी कैंप में जो कब्जे हुए हैं उन्हें हटाने के लिए दबाव डाला जाएगा।  
-बैरागी संप्रदाय के महंत बाबा हटयोगी



प्रशासन का सहयोग करना होता था और कुंभ में शाही स्नान में अखाड़ों के स्नान करने के क्रम भी अखाड़ा परिषद प्राचीन काल से चले आ रही परंपरा के अनुसार तय करती थी। 1954 से पहले कुंभ मेला प्रशासन अखाड़ा और स्थानिक धार्मिक संस्थाओं की प्रबंध समिति बनाकर कुंभ की व्यवस्थाएं करता था। 1945 तक दशनामी संन्यासी परंपरा के सभी सात अखाड़े एक साथ कुंभ में शाही स्नान करते थे। 1954 में अखाड़ा परिषद का गठन होने के बाद कुंभ मेले में शाही स्नान में अखाड़ों का क्रम तय कर दिया गया।

बाद में अखाड़ा परिषद 13 अखाड़ों का एक प्रभावशाली संगठन बन गया और कुंभ मेला प्रशासन और राज्य सरकार अखाड़ा परिषद के प्रभाव में आकर काम करने लगे। विभिन्न कुंभ मेलों में अखाड़े से जुड़े विभिन्न साधुओं में कई बार विवाद भी पैदा हुए। 1998 के कुंभ मेले में दशनामी नागा संन्यासियों के दो अखाड़ों के बीच जमकर विवाद भी हुआ था और शाही स्नान के दौरान हर की पौड़ी पर इन दो अखाड़ों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। बाद में कुछ

अन्य अखाड़ों के दखलंदारी के बाद इन तीनों अखाड़ों को फिर से अखाड़ा परिषद में शामिल किया गया। 2010 के हरिद्वार कुंभ के बाद अखाड़ा परिषद फिर दो फाड़ हुई और अखाड़ा परिषद का मामला प्रयागराज के हाईकोर्ट में जा पहुंचा और अखाड़ों के एक गुट के अध्यक्ष महंत ज्ञानदास बने रहें। उनके महामंत्री महंत हरि गिरि ने उनका साथ छोड़ दिया और महंत ज्ञानदास अलग-थलग पड़ गए और दशनामी संन्यासी परंपरा के श्री निरंजनी पंचायती अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरि अध्यक्ष और श्री पंच दशनाम

जुना अखाड़ा के महंत हरि गिरि महामंत्री बनाए गए। मौजूदा अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों ने उज्जैन, नासिक और प्रयागराज के कुंभ और अर्ध कुंभ मेले संपन्न कराए। मौजूदा अखाड़ा परिषद का कार्यकाल जनवरी 2020 तक था। परंतु कुछ महीने पहले हरिद्वार स्थित श्री उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा राजघाट, कनखल में अखाड़ा परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर महंत नरेंद्र गिरि और महामंत्री पद पर महंत हरि गिरि और उनकी कार्यकारिणी कार्यकाल बढ़ा दिया गया।



-त्रिवेद सिंह रावत, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री



मौजूदा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि और महामंत्री महंत हरि गिरि अनुभवी पदाधिकारी हैं और उन्हें तीन-तीन कुंभ मेलों में व्यवस्थाएं कराने का अनुभव है उनके अनुभव का लाभ हरिद्वार में 2021 में होने वाले महाकुंभ मेले में भी साधु संतों को उठाना चाहिए और पुणे विश्वास है कि उन्हीं के नेतृत्व में यह कुंभ मेला संपन्न होगा।  
- श्री पंच दशनाम अर्चन अखाड़ा के प्रमुख और दक्षिण काली पीठाधीश्वर महंत कैलाशानंद ब्रह्मचारी



1954 से पहले कुंभ के कार्यों को कुंभ मेला प्रशासन और स्थानीय स्तर पर बनाई गई साधु संन्यासियों की एक समिति अंजाम देती थी। अखाड़ा परिषद का गठन 1954 में हुआ, इसके बाद अखाड़ों का कुंभ मेला प्रशासन पर दखल बढ़ा। अखाड़ा परिषद के कुछ पदाधिकारी कुंभ मेले में अधिक जमीन की मांग कर रहे हैं, जो गलत है। दरअसल कुंभ मेला चंद संतों का नहीं बल्कि समूचे सनातनी हिंदू समाज का है। उसी के हिसाब से प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए। किसी के दबाव में आकर नहीं।  
-भूमा पीठाधीश्वर स्वामी अच्युतानंद तीर्थ महाराज

## फास्ट फूड : वसा और नमक मानक से ज्यादा

प्रतिभा शुक्ल  
नई दिल्ली।

विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की ओर से जारी अध्ययन में पता चलता है कि जंक फूड सेहत के लिए बहुत घातक है। तमाम बड़ रही गैर संक्रामक बीमारियों के पीछे यही है। 33 बड़े ब्रांड पर किया गया यह अध्ययन बताता है कि किस तरह से हम जाने अनजाने रोज ही तय मात्रा से अधिक नमक वसा व कार्बोहाइड्रेट का उपयोग कर रहे हैं। नियामक की कमी व निगरानी के अभाव में हालात खतरनाक बन चुके हैं। भारतीय नियामक लागू तक नहीं किए गए हैं जिससे 33 में से कोई भी ब्रांड खरा नहीं पाया गया। मसलन एक छोटे से नमकीन के पैकेट में ही हमें एक बार में पूरे दिन के वसा व नमक की जरूरत का बड़ा हिस्सा एक बार में परोस दिया जाता है। एक दो को छोड़ कर सभी में सभी ट्रांस फैट बहुत अधिक है।



**क्या है वजह**  
नमक, वसा और शर्करा सहित अन्य तत्वों की मात्रा निर्धारित मानकों का पालन स्वाद पर भारी पड़ता है, इसलिए कंपनियां स्वाद के साथ कोई समझौता करने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में सरकार संभवतः दुनिया की इन नामी कंपनियों के दबाव में है और कानून बनाकर एफएसएसआई के मानकों का पालन करने से बच रही है। जबकि नमक, शर्करा और वसा सहित अन्य तत्वों की तय मात्रा व इस्तेमाल की मात्रा साफ तौर से इन उत्पादों के पैकेट पर छापने की जरूरत है। इसके लिए कानून बना कर लागू करने की जरूरत है।

कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने जो नियामक इस साल जारी उसका भी पालन नहीं किया जा रहा। पोषक तत्वों का उल्लेख नहीं होता। प्राधिकरण ने तय किया था कि वसा 100 ग्राम के नश्ते के पैकेट में सोडियम की मात्रा .25 ग्राम सोडियम ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो पैकेट पर लाल निशान लगा होना चाहिए। लेकिन व्यवहारिक तौर पर दोनों नहीं हैं।

### क्या कहते हैं विशेषज्ञ

सुनीता नारायण ने बताया कि भारतीय बाजार में उपलब्ध अधिकतर पैकेट बंद खाना और फास्ट फूड में भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) के मानकों से बहुत ज्यादा है। एफएसएसआई ने फास्ट फूड कंपनियों को इन उत्पादों में इस्तेमाल किए गए खाद्य पदार्थों की मात्रा पैकेट पर दर्शाने के लिए इस साल जुलाई में दिशानिर्देश तैयार किए थे, लेकिन सरकार ने इन्हें अब तक अधिसूचित कर लागू नहीं किया है। इतना ही नहीं सरकार ने 2013 दिशानिर्देश बनाने के लिए एफएसएसआई के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी। छह साल में तीन समितियां गठित हो चुकी हैं लेकिन अब तक कोई ठोस कानूनी पहल नहीं हुई। सीएसई की महानिदेशक नारायण ने कहा कि सरकार को चाहिए कि जनस्वास्थ्य पर कंपनियों का हित भारी नहीं पड़े। इसके लिए रेटोरेट पर पैक फूड के उत्पादों में नमक, शर्करा और वसा का निर्धारित मात्रा से अधिक इस्तेमाल होने पर तंबाकू उत्पादों की तरह चेतावनी (रेड वार्निंग) पैकेट पर दर्ज करने को अनिवार्य बनाया जाए। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि जंक फूड में न्यूट्रिशन की मात्रा न के बराबर होती है, इसलिए ये जंक फूड कहे जाते हैं।

चीली में फास्ट फूड पर रेड मार्क हुआ है जिससे लोग समझने लगे हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। इसका लोगों पर असर पड़ा है।

## कन्याश्री योजना बच्चियों के लिए है वरदान

शंकर जालान  
कोलकाता।

पश्चिम बंगाल में महत्वाकांक्षी कन्याश्री योजना, कहने को तो एक योजना है लेकिन इसमें कई तरह से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जा रही है। मसलन कोख में कन्या भ्रूण हत्या में कमी, बाल तस्करी दर में गिरावट और स्कूल जाने वाली छात्राओं की संख्या में खासा इजाफा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कन्याश्री योजना की लोकप्रियता का डंका विदेश तक बजा और 2017 में इसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने सम्मानित किया। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सुबे की बालाओं के लिए कन्याश्री योजना वरदान साबित हो रही है। राज्य के महिला व बाल विकास विभाग के मुताबिक 2013 में इस परियोजना की शुरुआत की गई थी और 2017 तक इस मद में 7,588.90 करोड़ रूपए आबंटित किए गए और 7,237.28 करोड़ खर्च कर दिए गए। संबंधित विभाग की मंत्री शशि पांजा ने बताया कि कन्याश्री परियोजना के लिए अब तक 57 लाख से ज्यादा को नामांकित किया गया और इनमें से 56 लाख से ज्यादा को इस परियोजना का लाभ सीधे-सीधे मिलने लगा। महिला व बाल विकास विभाग के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर चौबीस परगना में कन्याश्री में सबसे अधिक नामांकन 5,49,415 हुए। वहीं इस सूची में दूसरे स्थान पर दक्षिण चौबीस परगना जिला रहा, जहां से कुल 5,28,156 लड़कियों को नामांकित किया गया है। तीसरे व चौथे स्थान पर क्रमशः मुर्शिदाबाद और कोलकाता रहा। मुर्शिदाबाद में 5,26,482 और कोलकाता में

1,46,592 लड़कियों के नाम इस सूची में शामिल किए गए हैं। मालूम हो कि 2013 में शुरू हुई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इस महत्वाकांक्षी सशर्त नकद हस्तांतरण परियोजना का मकसद राज्य में बेटियों की स्थिति में सुधार व सभी किशोरियों की स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ ही बाल विवाह जैसी विकट समस्या की रोकथाम को अप्रसर होना है। उक्त परियोजना के तहत लड़कियों को वार्षिक छात्रवृत्ति के रूप में एक हजार रूपए के साथ ही एकमुश्त 25 हजार रूपए अनुदान के तौर पर मुहैया कराए जाते हैं। वार्षिक छात्रवृत्ति 13 से 18 वर्ष की अविवाहित लड़कियों के लिए है, जिन्हें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त

### बंगाल



एक निगाह, योजना पर बजट राशि : 7,588.90 करोड़  
बाटी गई राशि : 7,237.28 करोड़

नियमित या समकक्ष ओपन स्कूल या समकक्ष व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में आठवीं से बारहवीं कक्षा में पढ़ाई के दौरान प्रदान की जाती है। हालांकि, एकमुश्त अनुदान उन लड़कियों के लिए है, जो आवेदन के समय 18 वर्ष की गई हों और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित या ओपन स्कूल, कॉलेज, व्यावसायिक व तकनीकी प्रशिक्षण या फिर खेल गतिविधि में सक्रिय हों। इसके तहत विश्वविद्यालय की कला की छात्राओं को दो हजार और विज्ञान की छात्राओं को ढाई हजार रूपए की छात्रवृत्ति जा रही है। विशेषज्ञों की मानें तो कन्याश्री परियोजना के कारण ही प्रदेश में बाल तस्करी की घटनाओं में गिरावट आई है। जल्द ही प्रदेश के हर जिले में कन्याश्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी।

## नियमित सरकारी भर्तियां नहीं होने से युवा परेशान

राजीव जैन  
जयपुर।

राजस्थान में पांच साल में नियमित सरकारी नौकरियों की भर्तियां नहीं होने से शिक्षित बेरोजगारों की भीड़ जमा हो गई है। इन पदों पर प्रदेश के ग्रामीण युवाओं की विशेष नजर रहती है और लाखों की संख्या में बेरोजगार इसमें आवेदन करते हैं। राज्य में सरकार की लापरवाही के कारण सरकारी विभागों, निगम, बोर्ड और अन्य स्वायत्त संस्थानों में किसी तरह की भर्तियां नहीं होने से युवाओं में गहरी

### राजस्थान

**प्रदेश** में बेरोजगारों की लंबी कतार है। इसके मुकाबले भर्तियों की संख्या नागण्य है। सरकार जो भर्तियां निकालती है वो पूरी हो ही नहीं पाती है। ज्यादातर भर्तियां अदालतों में अटकी रहती हैं। सरकार लगातार भर्ती प्रक्रिया अपनाती तो प्रदेश में ऐसे हालात नहीं होते। लगातार भर्तियां नहीं होने से ही अब प्रतिस्पर्धा का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है।  
-उपेन यादव, संघ के प्रदेश अध्यक्ष

**नियमित** भर्तियां नहीं होने से कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। सेवारत कर्मचारी तो नियमित रिटायर हो रहे हैं पर नए लोग नहीं आने से परेशानी होती है। भर्तियां नहीं होने से ही बेरोजगारों को तादाद बढ़ती जा रही है। सरकार की तरफ से ये बड़ी लापरवाही है। सरकार ने इस बार बजट में भर्तियों की कई घोषणाएं की हैं जिसे पूरा करना उसके लिए एक बड़ी चुनौती है। सरकार नियमित भर्तियां निकालती तो आज जैसे हालात नहीं होते।  
-रामकिशोर वर्मा, राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी संघ के महासचिव

नाराजगी का माहौल है। मौजूदा सरकार ने तो अपने वादे के मुताबिक अब बेरोजगारों को भत्ता देने का भी फैसला किया है। इसके लिए रोजगार दफ्तरों में बेरोजगारों के पंजीयन में बेतहाशा बढ़ोतरी भी हो रही है। दूसरी तरफ सरकार की भर्ती परीक्षाएं भी मजाक बन कर रह गई हैं। प्रदेश में कुछ सालों में हुई परीक्षाओं में जब नकल के बड़े मामले पकड़े गए तो उन्हें बीच में ही निरस्त कर दिया गया। प्रदेश में अब होने वाली पुलिस कांस्टेबल और पटवारी की भर्ती में करीब एक साल का समय लगेगा। प्रदेश में सबसे ज्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में पद खाली है। सरकार ने शिक्षकों और नर्सिंग स्टाफ की भर्ती के लिए अब गंभीरता दिखाई है। शिक्षकों, डॉक्टरों और नर्स की भर्ती प्रक्रिया बड़ी मुश्किल से अब शुरू की

लगे तो उन्हें बीच में ही निरस्त कर दिया गया। प्रदेश में अब होने वाली पुलिस कांस्टेबल और पटवारी की भर्ती में करीब एक साल का समय लगेगा। प्रदेश में सबसे ज्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में पद खाली है। सरकार ने शिक्षकों और नर्सिंग स्टाफ की भर्ती के लिए अब गंभीरता दिखाई है। शिक्षकों, डॉक्टरों और नर्स की भर्ती प्रक्रिया बड़ी मुश्किल से अब शुरू की

## विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आज

जनसता संवाददाता देहरादून, 17 दिसंबर।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बुधवार को देहरादून में विधानसभा अध्यक्षों और विधान परिषद सभापतियों के दो दिवसीय 79वें सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसमें देश के 26 राज्यों के विधानमंडलों के अध्यक्ष और सभापति भाग लेंगे और अनुभव साझा करेंगे। यह जानकारी उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष और इस सम्मेलन के मेजबान प्रेमचंद अग्रवाल ने पत्रकारों को दी।

उन्होंने बताया कि लोकसभा के महासचिव और विधानसभाओं के सचिवों की मंगलवार को विशेष बैठक हुई। इसमें बुधवार से शुरू होने वाले दो दिवसीय सम्मेलन के बारे में गहन विचार-विमर्श हुआ। दो दिवसीय सम्मेलन में राज्यसभा के उपसभापति भी भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत में ‘संविधान की दसवीं अनुसूची और अध्यक्ष की भूमिका’ और ‘शून्यकाल सहित सभा के अन्य सार्धनों के माध्यम से संसदीय लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण तथा क्षमता निर्माण’ विषयों पर चर्चा की जाएगी। दो दिनों तक चलने वाली परिचर्चाओं के दौरान पीठासीन अधिकारी कायर्सूची में ‘संविधान की दसवीं अनुसूची और अध्यक्ष की भूमिका’ पर चर्चा करेंगे।

# राष्ट्रपति से मिले विपक्षी नेता

पेज 1 का बाकी

एक ज्ञापन सौंपा और नागरिकता कानून को असंवैधानिक करार देते हुए उनसे यह मांग की कि वह सरकार को इस कानून को वापस लेने की सलाह दें। विपक्षी नेताओं ने इस कानून की मुखाफलत करने वाले जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों के खिलाफ रिविचर को विश्वविद्यालय परिसर में घुसकर की गई दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की न्यायिक जांच कराने की मांग भी राष्ट्रपति के समक्ष रखी।

राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संवाददाताओं से कहा कि पूर्वोत्तर में जो हालात हैं वह अब पूरे देश में फैल रहे हैं। यह विरोधी अब दिल्ली के जामिया विश्वविद्यालय तक भी आ गया है। यह काफी गंभीर हालात हैं। उन्होंने कहा कि हमें डर है कि हालात और बिगड़ सकते हैं। दूसरी ओर पुलिस इस हालात से निपटने में विफल रही है।

राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले विपक्षी नेताओं में शामिल सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने

# समुद्री लुटेरों ने गिनी की खाड़ी में 20 भारतीयों को अगवा किया

पेज 1 का बाकी

और चालक दल का पता लगाने के लिए स्थानीय अधिकारियों से बातचीत जारी है। विदेश मंत्रालय ने ड्यूक मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के हवाले से बताया कि सोमवार तड़के जहाज से संपर्क टूट गया। हम जहाज और चालक दल का पता लगाने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पायरेसी रिपोर्टिंग सेंटर ने जानकारी दी कि 16 दिसंबर को स्थानीय समयानुसार सुबह 7-8 बजे के बीच समुद्री लुटेरों का हमला हुआ था। इसके पहले नाइजीरिया के समुद्र तटीय इलाके के पास से दो दिसंबर को स्थानीय समयानुसार शाम 7:20 बजे हांगकांग का झंडा लगा एक मालवाही जहाज अगवा कर लिया गया था, जिस पर एक तुर्की और 18 भारतीय सवार थे। बाद में जहाज को नाइजीरियाई नौसेना ने अपने कब्जे में लिया, लेकिन अगवा व्यक्तियों का अब तक पता नहीं चल सका है। इस कांड के बारे में भी विदेश मंत्रालय ने प्रयास जारी कर रखा है। इसके बाद पांच दिसंबर को एक फ्रांसीसी कंपनी का तेल टैंकर नाइजीरियाई इलाके से ही अगवा कर लिया गया। उस जहाज पर भी 19 चालक दल के सदस्य थे, लेकिन उसमें कोई भारतीय नहीं था।

## आउटगोइंग कॉल पर शुल्क एक साल के लिए बढ़ाया

पेज 1 का बाकी

अब वायरलेस से वायरलेस थ्रूल् कॉल पर छह पैसे प्रति मिनट का शुल्क एक जनवरी, 2021 से खत्म होगा। न्यायमक की ओर से 18 सितंबर 2019 को इंटरकनेक्शन उपयोग शुल्क की समीक्षा के लिए परामर्श पत्र जारी किया गया था। इस पर सभी हितधारकों से 18 अगस्त 2019 तक उनकी लिखित टिप्पणियां मांगी गई थीं। इतना ही नहीं एक नवंबर 2019 तक जवाबी टिप्पणियां भी ट्राई ने मांगी थीं। इसके बाद इन सभी टिप्पणियों और जवाबी टिप्पणियों को 15 ट्राई की वेबसाइट पर रखा गया और 15 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में सभी हितधारकों के साथ आयोजित हुए खुले सत्र में इन पर चर्चा की गई।

खुले सत्र में सभी हितधारकों से मिली टिप्पणियों के विश्लेषण के बाद नियामक ने तय किया कि किसी ऑपरेटर के नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर की जाने वाली मोबाइल कॉल पर छह पैसे प्रति मिनट के शुल्क को एक साल के लिए बढ़ाया जाए।

# बंगाल में प्रदर्शन जारी गुवाहाटी में कर्फ्यू हटा

जनसता ब्यूरो

नई दिल्ली, 17 दिसंबर।

नागरिकता कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में मंगलवार को पांचवें दिन भी प्रदर्शन जारी रहा और प्रदर्शनकारियों ने राज्य के कई हिस्सों में सड़क और रेल की पटरियां जाम कर दीं। हालात सामान्य होने पर पड़ोसी राज्य असम के गुवाहाटी में लगा कर्फ्यू मंगलवार को हटा लिया गया। गुवाहाटी में उड़ान परिचालन और रेलवे सेवाएं बहाल कर दी गईं। दूसरी ओर, गुवाहाटी में आल असम स्टूडेंट यूनियन (आसू) द्वारा आयोजित ‘जन सत्याग्रह’ जुलूस में लोगों ने हिस्सा लिया और गिरफ्तारी दी। असम में ब्रॉडबैंड सेवाएं मंगलवार को बहाल हो गईं, लेकिन मोबाइल इंटरनेट बंद है जिससे मोबाइल ऐप और अन्य ऑनलाइन सेवाओं पर निर्भर लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

गुवाहाटी में शहर में दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले हैं। बस, कार और दोपहिया वाहन सड़कों पर नजर आ रहे हैं। कानून व स्या सत्याग्रह की अध्यक्षमंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा सोमवार को बुलाई गई एक बैठक में गुवाहाटी से कर्फ्यू हटाने का निर्णय लिया गया। बयान के अनुसार, ‘गुवाहाटी में कल (मंगलवार को) सुबह छह

बजे से पूरी तरह कर्फ्यू हटाने का निर्णय लिया गया है।’ बयान में हालांकि मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल करने के बारे में कोई जिक्र नहीं है।

अधिकारियों ने बताया कि डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे से भी उड़ानें निर्धारित समय सारिणी से आ-जा रही हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) के प्रवक्ता सुभानन चंदा ने कहा, ‘कुछ इंटरसिटी सेवाओं समेत ग्यारह ट्रेन सेवाएं मंगलवार को बहाल कर दी गईं, क्योंकि राज्य में कानून व्यवस्था में क्रमिक सुधार आया है।’ अन्य ट्रेनों की सेवाएं भी धीरे धीरे बहाल की जा रही हैं। चंदा ने कहा, ‘बहाल ट्रेनों में मानस राइनो पैसेंजर सेवा शामिल है, जो बोंगाईगांव जिले के न्यू बोंगाईगांव को गुवाहाटी से जोड़ती हैं। इन ट्रेनों के बहाल होने से खासकर कार्यालय जाने वालों को फायदा होगा।’

हालांकि, पूर्वोत्तर से कोलकाता की सभी ट्रेनें पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था की मदेनजर रद्द रही। असम में दोनों हवाई अड्डों पर उड़ान परिचालन सामान्य रहा। बस कोलकाता जाने वाली इंडिगो की उड़ान रद्द कर दी गई। बंगाल में अभी तक करीब 354 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। मालदा, उत्तर दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, हावड़ा और उत्तर और दक्षिण 24 परगना के कुछ हिस्सों में लगातार तीसरे दिन इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहीं।

## ‘हाई कोर्ट जाएं याचिकाकर्ता’

पेज 1 का बाकी

की अध्यक्षता में समिति गठित करने से मंगलवार को इनकार कर दिया और कहा कि इस तरह की समितियां संबंधित हाई कोर्ट द्वारा गठित की जा सकती हैं। शीर्ष अदालत ने सभी याचिकाकर्ताओं को राहत और जांच समितियों के गठन के लिए संबंधित राज्यों के हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया, जहां हिंसा की घटनाएं हुई हैं।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत के तीन सदस्यीय पीठ ने अपने आदेश में इस तथ्य का उल्लेख किया कि याचिकाकर्ताओं के हरेक आरोप का केंद्र की ओर से महान्यायवादी तुषार मेहता ने खंडन किया है। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की चिंता दो बातों को लेकर मुख्य रूप से है। पहला तो अंधाधुंध तरीके से छात्रों की गिरफ्तारी और घायल छात्रों का ठीक से इलाज नहीं होना।

पीठ ने कहा कि महान्यायवादी के अनुसार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सिर्फ दो छात्रों को ही अस्पताल में दाखिल किया गया है और उनका विश्वविद्यालय के अस्पताल में इलाज चल रहा है। महान्यायवादी का कहना है कि वे पुलिस कार्रवाई में जखमी नहीं हुए हैं, जैसा कि याचिकाकर्ताओं का दावा है। पीठ ने आरोप-प्रत्यारोपों का उल्लेख करते हुए कहा- इस विवाद के स्वरूप और घटनाओं

# मुशर्रफ को देशद्रोह के मामले में मौत की सजा

पेज 1 का बाकी

नहीं हो सकता है।’ गफूर ने उम्मीद जताई कि इस मामले में पाकिस्तानी इस्लामी गणतंत्र के मुताबिक न्याय किया जाएगा।

पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार किसी सैन्य प्रमुख को देशद्रोही करार देकर मौत की सजा सुनाई गई है। देशद्रोह के मामले में उन्हें दोषी ठहराना उस देश के लिए महत्त्वपूर्ण क़दम है जहां स्वतंत्र इतिहास में अधिकतर समय तक शक्तिशाली सेना काबिज रही है।

मुशर्रफ ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 1999 में रक्तहीन तख्ता पलट में सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था। वे 2001 से 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी रहे। यह मामला 2007 में संविधान को निलंबित करने और देश में आपातकाल लगाने का है जो दंडनीय अपराध है और इस मामले में उनके खिलाफ 2014 में आरोप तय किए गए थे। अदालत को दो न्यायाधीशों ने मौत की सजा सुनाई जबकि एक अन्य न्यायाधीश की राय अलग थी। इसके ब्योरे अगले 48 घंटों में सुनाए जाएंगे। फैसला सुनाए जाने से पहले अदालत ने अभियोजकों की एक याचिका खारिज कर दी जिसमें फैसले को टालने की मांग की गई थी।

इस महीने की शुरुआत में स्वास्थ्य खराब होने के कारण मुशर्रफ को दुबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।अपने अस्पताल के विस्तर से वीडियो के माध्यम से बयान जारी कर उन्होंने देशद्रोह के मामले को पूरी तरह निराधार बताया। उन्होंने कहा, ‘मैंने दस वर्षों तक अपने देश की सेवा की है। मैं अपने देश के लिए लड़ा। यह (देशद्रोह) मामला है जिसमें मेरी बात नहीं सुनी गई और मुझे प्रताड़ित किया गया।’

खबरों में बताया गया है कि उनकी कानूनी टीम उच्चतम न्यायालय में फैसले को चुनौती देगी।

# नागरिकता कानून में कुछ भी अल्पसंख्यक विरोधी नहीं : शाह

पेज 1 का बाकी

कार्यक्रम में इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। शाह ने कहा, ‘कुछ भी हो मोदी सरकार सुनिश्चित करेगी कि इन शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता हासिल हो और वे सम्मान के साथ भारतीय नागरिक बनकर जिएं।’ गृह मंत्री ने कहा कि नागरिकता (संशोधन) कानून, 2019 के कारण कोई भी भारतीय अपनी नागरिकता नहीं खोएगा और यह कानून तीनों पड़ोसी देशों में अत्याचार का शिकार बने अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया है।

उन्होंने कानून का विरोध करने वाले छात्रों से कहा कि इसे ठीक से पढ़ें और इसके अर्थ को समझें। उन्होंने कहा, ‘मैं अपने मुसलिम भाइयों-बहनों से कहना चाहता हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग भारत में रह रहे हैं, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी भारतीय नागरिकता खोने नहीं जा रहा है। कांग्रेस लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। कानून वेबसाइट पर है। इसे पढ़िए। किसी से भी अन्याय नहीं किया जाएगा।’

कानून के मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2014 तक आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को अवैध शरणार्थी नहीं, बल्कि भारतीय नागरिक माना जाएगा। शाह ने कहा कि कानून

का एकमात्र उद्देश्य उन लोगों को नागरिकता देना है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक अत्याचार का सामना कर रहे हैं। अमित शाह ने पूछा, ‘हिंदू, सिख व अन्य भारत नहीं आएंगे तो ये लोग कहां जाएंगे।’ गृह मंत्री ने कहा कि नेहरू-लियाकत समझौते के मुताबिक इन लोगों को पाकिस्तान में संरक्षण दिया जाना था, लेकिन वे ऐसा करने में विफल रहे।

## मद्रास विश्वविद्यालय में घुसी पुलिस, छात्रों का प्रदर्शन जारी

वेनई, 17 दिसंबर (भाषा)।

नागरिकता कानून में संशोधन के खिलाफ मद्रास विश्वविद्यालय के छात्रों के एक वर्ग ने मंगलवार को दूसरे दिन भी यहां स्थित मरीना परिसर में अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा, जबकि इस बीच पुलिस परिसर में प्रवेश कर गई। मरीना समुद्र तट के ठीक सामने स्थित विशाल परिसर में प्रदर्शनकारी धरने पर बैठे, जिन्होंने नागरिकता अधिनियम में संशोधन को वापस लेने की मांग की और इसके खिलाफ नारे लगाए। पुलिसकर्मी, इस बीच, विश्वविद्यालय परिसर के अंदर प्रवेश कर गए।

# नागरिकता कानून मुसलिम विरोधी नहीं : राजनाथ

न्यूयॉर्क, 17 दिसंबर (भाषा)।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां भारतीय समुदाय को आश्वासन दिया कि संशोधित नागरिकता कानून मुसलिम विरोधी नहीं है। उन्होंने कहा, ‘हमारी संस्कृति हमें नफरत करना नहीं सिखाती।’ नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 तक यहां आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के सदस्यों, जिन्हें वहां धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो, को यहां अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी।

वाशिंगटन में 18 दिसंबर 2019 को अमेरिका-भारत टू प्लस टू मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए सोमवार को अमेरिका पहुंचे सिंह ने एशिया सीसायटी नामक शिक्षण संस्थान में भारत के महावाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित एक समारोह के दौरान यहां भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित किया। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लिए गए कई फैसले गिनाए जिनमें अनुच्छेद 370 को समाप्त करना, नागरिकता संशोधन कानून, तीन तलाक कानून तथा पाकिस्तान से पत्नयने वाले आतंकवाद पर भारत की ओर से की गई कार्रवाई शामिल हैं। सिंह ने कहा, ‘नागरिकता (संशोधन) विधेयक, जो अब कानून बन गया है, मुसलिम विरोधी नहीं है।’ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक यातनाओं की वजह से यहां आने वाले वहां के अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध तथा जैन समुदायों को नागरिकता देने के उद्देश्य से विधेयक लाया गया। रक्षा मंत्री ने कहा कि सीएए में मुसलिमों को शामिल नहीं किया गया क्योंकि ये तीनों देश ‘धर्म आधारित’ तथा ‘इस्लामिक’ देश हैं और किसी इस्लामिक देश में कम से कम इस्लाम धर्म का पालन करने वालों को धार्मिक उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ता।

# ‘हाई कोर्ट जाएं याचिकाकर्ता’

के संबंध में हरेक राज्य में तथ्यों के निष्कर्ष तक पहुंचने हेतु सामग्री एकत्र करने के लिए हरेक राज्य में एक-एक समिति गठित करना उचित होगा और हम इसलिए याचिकाकर्ताओं को उन उच्च न्यायालयों में जाने का निर्देश देना उचित समझते हैं जिनके अधिकार क्षेत्र में घटनाएं हुई हैं।

पीठ ने कहा- हम आवश्यक हैं कि विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, यदि आवश्यक हुआ, केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों का पक्ष सुनने के बाद शीर्ष अदालत या हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की समिति गठित करते समय जांच के लिए तथ्य संज्ञान में लाया जाता है तो इसकी पुष्टि के बाद उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

पीठ ने याचिकाकर्ताओं द्वारा यह गंभीर मुद्दा उठाए जाने के तथ्य का भी संज्ञान लिया कि छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करते समय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की अनदेखी की गई है। पीठ ने महान्यायवादी द्वारा इस तथ्य से इनकार किए जाने के कथन को भी रिकार्ड पर लिया।

महान्यायवादी ने स्पष्ट रूप से बयान दिया कि अभी तक किसी भी छात्र को गिरफ्तार नहीं किया गया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि वे भविष्य के बारे में कोई बयान नहीं दे सकते।

# सेना ने तीन घुसपैठिए और दो पाकिस्तानी कमांडो किए ढेर

पेज 1 का बाकी

की गई। सैन्य प्रवक्ता कर्नल देवेंद्र आनंद के मुताबिक, पाकिस्तानी चौकियों की ओर से सोमवार को पूरी रात सीमा पर गोलाबारी की गई। जम्मू व कश्मीर के जिला राजौरी के केरी सेक्टर स्थित सुंदरबनी और नौशेरा में पाकिस्तानी सेना ने मोर्टार और स्वचालित राइफलों से गोलाबारी की, जो मंगलवार सुबह तक जारी रही। इस दौरान पाकिस्तानी सेना के सीमा कार्रवाई टीम (बैट) और विशेष सुरक्षा दस्ते (एसएसजी) के कई कमांडो और आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय सैनिकों की ओर से जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की ओर से आने वाले पांच घुसपैठियों को ढेर कर दिया गया। इनमें एसएसजी के दो कमांडो थे। पाकिस्तान के चार अन्य कमांडो घायल हुए हैं।

सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागे गए। साथ ही, मोर्टार और तोपखाने से भी गोलाबारी की गई। देर रात तक दोनों तरफ से भीषण गोलाबारी होती रही। इस दुस्साहस के बाद पाकिस्तानी सेना ने पुंछ के दिवार सेक्टर में भी भारी गोलाबारी शुरू कर दी। इसके बाद यहां सीमा पर भारी हलचल भी रही।

सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक, सुंदरबनी सेक्टर के अंतर्गत केरी बटुल इलाके में ललयाली चौकी पर पाकिस्तानी सेना के बैट दस्ते ने हमला किया।

फिर पाकिस्तानी कमांडो ललियाली चौकी की तरफ बढ़े, वहां मौजूद जवानों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए घुसपैठ करने वाले कमांडो और आतंकियों में से पांच को मार गिराया। इस कार्रवाई के बाद बाकी बचे घुसपैठिए वापस भाग गए।

# शहरी नक्सली भड़का रहे हैं युवाओं को

पेज 1 का बाकी

कि वह लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के साथ बातचीत के लिए मुद्दों को उठाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि ‘शहरी नक्सली’ लोग देश में समस्या पैदा करने के लिए युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी ने कहा, ‘कांग्रेस नागरिकता कानून पर झूठ बोल रही है, मुसलमानों के बीच डर का माहौल बना रही है। मैं आश्वासन देता हूं कि देश का कोई भी नागरिक इस कानून से प्रभावित नहीं होगा।’ प्रधानमंत्री ने झारखंड की रैली में कहा, ‘मैं कांग्रेस, उसके मित्रों को यह सार्वजनिक ऐलान करने की चुनौती देता हूं कि वे सभी पाकिस्तानियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए तैयार हैं।’

उन्होंने कहा, ‘मैं जानना चाहता हूं कि नया नागरिकता कानून मुसलमानों या किसी भारतीय नागरिक के अधिकारों का अतिक्रमण कैसे करता है।’ मोदी ने कहा कि हमने जो कानून बनाया है, वह धार्मिक उत्पीड़न के कारण पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को छोड़कर आने वाले लोगों के लिए है। ऐसे लोगों के लिए है जिनकी हालत दयनीय है और जो वापस नहीं जा सकते।

उन्होंने चुनावी रैली में कहा कि झारखंड की जनता ने विधानसभा चुनावों के चार चरणों में निडर होकर मतदान किया। उन्होंने जनता से भाजपा के लिए मतदान करने का आह्वान करते हुए कहा कि जब कमल खिलता है तो आदिवासियों, महिलाओं और युवाओं को फायदा होता है। मोदी ने जनसभा में कहा, ‘भाजपा पर आपके आशीर्वाद से कांग्रेस, झाम्पो, राजद और वाम दलों की रातों की नींद उड़ी हुई है। वे सच को पचा नहीं पा रहे हैं।’

# ‘उतरते समय आगे का पहिया खुला नहीं था, विमान को उतरने से रोका गया’

नई दिल्ली, 17 दिसंबर (भाष)।

गोवा हवाई अड्डे पर मंगलवार सुबह को एक बड़ा हादसा टल गया जब एक चौकस रनवे नियंत्रक ने उतर रहे स्पाइस जेट के एक विमान को उसका आगे का पहिया (नोज लैंडिंग गीयर) खुला न देखकर उसे उतरने से रोक दिया। नौसेना के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।

नौसेना के प्रवक्ता ने ट्वीट किया, ‘भारतीय वायुसेना की चौकस विमान यातायात सेवा ने एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया। रनवे नियंत्रक प्रमुख एयरमैन (एअर हैंडलर) रमेश टिग्गा को उतरने जा रहे स्पाइसजेट फ्लाइट एसजी 3568 का अगला पहिया बंद नजर आया। प्रवक्ता ने बताया कि टिग्ग ने तुरंत विमान यातायात नियंत्रण कक्ष को इसकी सूचना दी और वहां तैनात ड्यूटी एअर ट्रैफिक नियंत्रक लेफ्टिनेंट कॉमोडोर हरमीत कौर ने स्पाइसजेट विमान को लैंडिंग रोक देने को कहा। नौसेना के प्रवक्ता ने कहा, ‘विमान आपात व सुरक्षा सेवाओं की सहायता से आठ बजकर पांच मिनट पर सुरक्षित ढंग से हवाई अड्डे पर उतरा।’

# तेलंगाना मुठभेड़ मामले में शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित करने की तरह ही समिति नियुक्त करने से इनकार करते हुए पीठ ने कहा-

इन दोनों घटनाओं के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती। विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों की ओर से पेश वरिष्ठ वकीलों की फौज से पीठ ने कहा कि इसलिए आपका यह अनुरोध अस्वीकार किया जाता है। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने इसका विरोध करते हुए कहा-आपके पास हमें निहत्था करने का रास्ता है। जयसिंह ने कहा- हम सभी न्यायाधीशों का पूर्व न्यायाधीशों और पीठासीन न्यायाधीशों के साथ ही हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का एक समान सम्मान करते हैं। लेकिन यदि तथ्यों का पता लगाने के लिए शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है तो हमें अधिक भरोसा होगा।

पीठ ने इस मामले में याचिकाओं में समाचार पत्रों की खबरों पर विचार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि हम समाचार पत्र पढ़ेंगे। हम अपने न्यायिक निर्णय पर पहुंचने के लिए समाचार पत्रों को आधार नहीं बनाएंगे। बहस के दौरान जब याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने ऊंची आवाज में बहस करना शुरू किया तो पीठ ने इस पर नाराजगी जताई और कहा- हम अदालत में जोर-जोर से बोलना पसंद नहीं करेंगे। यह चीखने चिल्लाने वाला मैच नहीं है।

# सीलमपुर में हिंसा, आगजनी

पेज 1 का बाकी

संयुक्त आयुक्त आलोक कुमार ने बताया कि सीलमपुर में प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए ऑसू गैस के गोल छोड़े गए। गोली नहीं चलाई गई। स्थिति अब नियंत्रण में है। उनके मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने दो पुलिस चौकियों पर आगजनी की। इस घटना में सात स्थानीय लोग और 11 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इनमें उपायुक्त और अतिरिक्त उपायुक्त स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान दो सार्वजनिक परिवहन बसें, एक रैपिड एक्शन फोर्स की बस और कुछ मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गईं। प्रदर्शनकारियों ने यातायात पुलिसकर्मियों की दो मोटरसाइकिलों में भी आग लगी दी।

कुमार के मुताबिक दो पुलिस चौकियों को भी आग लगाकर नुकसान पहुंचाया गया। प्रदर्शन के कारण आसपास के कई मेट्रो स्टेशनों का गेट भी एहतियातन बंद कर दिया गया था, जो देर रात खोल दिया गया। दंगा फैलाने, सरकारी सेवकों को काम में बाधा डालने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है।

मंगलवार को कुछ स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं के एलान पर जाफराबाद में

दोपहर दो बजे लोग नागरिकता संशोधन कानून

के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जमा हुए। शुरुआत में यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा लेकिन बाद में पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई, जिससे हिंसा शुरू हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए एलते लाठी धांजी और फिर ऑसू गैस के गोले दागने शुरू किए।

इस दौरान, प्रदर्शनकारियों ने डीटीसी की दो क्लस्टर बसों और एक रेपिड बस में आग लगा दी। उपद्रवियों की पत्थरबाजी में शाहदरा के जिला पुलिस उपायुक्त अमित शर्मा के सिर में पत्थर लग गया। मेट्रो प्रबंधन ने वेलकम, जाफराबाद, मौजापुर-बाबरपुर, सीलमपुर, गोकुलपुरी, जोईरी विहार और शिव विहार के प्रवेश और निकास द्वार बंद कर दिए। जाफराबाद में स्थिति पर नजर रखने के लिए पुलिस ने ड्रोन का सहारा लिया। पुलिस ने कुछ ड्रोन इलाके में उड़ाए जिससे उपद्रवियों पर निगरानी रख सके।

उधर, शाम में पुरानी दिल्ली के दरियागंज से कुछ प्रदर्शनकारी मार्च की शक्त में आइटीओ पहुंचने की कोशिश में थे लेकिन पुलिस ने मार्च को दिल्ली गेट पर ही रोक दिया। संभावित अशांति को देखते हुए पुलिस ने दुकानें बंद करवा दी।

## बांग्लादेश ने नदी प्रबंधन पर बैठक स्थगित करने को कहा

नई दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा)।

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेश ने नदी प्रबंधन पर इस सप्ताह भारत के साथ होने वाली दो बैठकों को स्थगित किए जाने को कहा है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि ये बैठकें गुरुवार और शुक्रवार को होनी थीं। उन्होंने बताया कि एक संयुक्त समिति की बैठक है और दूसरी तकनीकी स्तर की बैठक है।



<b>टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड</b> पंजीकृत कार्यालय <span> </span> : 1 भी मंजिल, टॉवर ए, पेनिंगुला बिजनेस पार्क, गणपतनगर बनार मार्ग, लोवर परेले, मुम्बई-400013. DIN No U67190MH2008PLC167552
<b>कच्चा सूचना</b> [प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम ४(1) के साथ पठित नियम ४(1) पंशिक्षित IV के अनुसार] ऋण खाता सं. 9516254

जबकि अधोहस्ताक्षरी प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आरतियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदार के रूप में टीटा दस्तावेज शिफ्ट के तहा सहकर्जदार के रूप में श्री सोनिया कुमार सिंह से कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि रु. 31,48,315/- ( रुपये इकतीस लाख अड़तालीस हजार तीन सौ पन्द्रह मात्र) तथा ब्याज, दण्डात्मक ब्याज, प्रभारों, लागतों आदि के लिए टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को प्रकट कर दिया है।

ऋणकर्ता द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण विशेष रूप से ऋणकर्ताओं तथा जनसामान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कोर्ट रिसीवर ने श्री सुनील कुमार, जिलाधीश गाजियाबाद द्वारा पारित आदेश के अनुसार कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित धारा 14 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 16 दिसम्बर, 2019 को कब्जा कर लिया है और इसे 16.12.2019 को अधिकृत प्राधिकारी के सुपुर्द कर दिया है।

प्रतिभूत आरतियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिपेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 को उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है। व्यक्तिगत रूप से ऋणकर्ता तथा जमानती और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन रु. 31,48,315/- ( रुपये इकतीस लाख अड़तालीस हजार तीन सौ पन्द्रह मात्र) तथा 22 जनवरी, 2018 से उस पर ब्याज, दण्डात्मक ब्याज, प्रभारों, लागतों आदि के लिए टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अभियोग का विषय होगा।

##### अचल सम्पत्ति का विवरण

गुप हाउसिंग प्लॉट सं. 20, रेजिडेंशियल कॉलोनी, सेक्टर-4, वैशाली, गाजियाबाद, तहसील एवं विला गाजियाबाद ( उ.प्र. ) पर निर्मित "रतन ज्योति" में संलग्न मानचित्र के अनुसार निर्मित गुप एरिया 856 वर्ग फीट अर्थात 79.52 वर्ग मीटर के आवासीय प्लेट सं. 607, 6ठी मंजिल पर ( छत के अधिकार बिना) सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग जिसकी सीमाएं निम्नलिखित हैं : उत्तर : कारिडोर/स्टैचकेस, दक्षिण : कारिडोर/प्लेट सं. 610, पूर्व : खुला प्लैट सं. 606, पश्चिम : प्लैट सं. 608

तिथि : 16.12.2019 ह./- अधिकृत प्राधिकारी  
स्थान : गाजियाबाद कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

<b>टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड</b> पंजीकृत कार्यालय <span> </span> : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिंगुला बिजनेस पार्क, गणपतनगर कदम मार्ग, लोअर परेले, मुम्बई-400013 सीआरएन <span> </span> : U67190MH2008PLC187552
<b>कच्चा सूचना</b> प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 3 के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की वित्तीय आरतियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने नियमों के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में तथा अधिनियम के तहत टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएफएफएल) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते नीचे वर्णित कर्जदार (सह-कर्जदार(रें)/जमानती(यों) (सभी को अकेले या एक साथ मिलाकर "दायित्वधारी")/वैध उत्तराधिकारी(यों)/वैध प्रतिनिधि(यों) को पहले ही कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सम्बद्ध मौग सूचनाओं में उल्लिखित नीचे वर्णित विवरणों के अनुसार राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए एक मौग सूचना निर्गत की थी। कथित सूचनाओं की प्रतियाँ रिजल्टेंट पोस्ट ए.डी. द्वारा भेजी गयी है और अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है, तथा कथित दायित्वधारी(यों)/वैध उत्तराधिकारी(यों)/वैध प्रतिनिधि(यों) द्वारा यदि वे चाहें तो सामान्य कार्यालय घण्टों के दौरान सूचना भी कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी से सम्बद्ध प्रति प्राम कर सकते हैं।

उपरोक्त के सम्बन्ध में, एतद्वारा कथित दायित्वधारी(यों)/वैध उत्तराधिकारी(यों)/वैध प्रतिनिधि(यों) को सम्बद्ध सूचना(ओं) की तिथि के 60 दिनों के भीतर उनके सम्बद्ध नामों के सामूहिक लिखित राशियों एवं नीचे कालम दो में वर्णित सम्बद्ध तिथियों से भावी ब्याज का कथित दायित्वधारी(यों) द्वारा क्रियात्मक ऋण अनुबन्ध एवं अन्य दस्तावेजों/प्रलेखों के साथ पठित भुगतान तथा/अथवा यस्कुली की तिथि तक टीसीएफएफएल को भुगतान करने के लिए पुनः सूचना दी जाती है। ऋण के बकाया भुगतान हेतु प्रतिभूति के रूप में क्रमशः दायित्वधारी(यों) द्वारा निम्नलिखित प्रतिभूत आस्तित्व (यों) गिरी रखा गया है।

ऋण खाता सं.	दायित्वधारी/वैध उत्तराधिकारी/वैध प्रतिनिधि	निम्नलिखित तिथियाँ तक कुल बकाया रु.	मौग सूचना एतर्पाण की तिथि
10538479	श्री प्रेम सिंह चन्देल (कर्जदार) एवं श्रीमती हेमलता तलक रु. 20,74,199/-	19 नवम्बर, 2019	03 अक्टूबर 2019

\* भावी ब्याज, ऊपर वर्णित तिथियों पर सम्बद्ध मौग सूचनाओं की तिथि में विशेष रूप से वर्णित दर पर अतिरिक्त ब्याज, भुगतान तथा/अथवा यस्कुली की तिथि तक आकरिसमय, ब्याज, प्रभार आदि। यदि कथित दायित्वधारी उर्वरुज के अनुसार टीसीएफएफएल को भुगतान करने में असफल होंगे तो टीसीएफएफएल लागतों तथा परिणामों के प्रति कथित दायित्वधारी(यों)/वैध उत्तराधिकारी(यों)/वैध प्रतिनिधि(यों) के पूर्ण ज़िम्मेदार पर कथित अधिनियम की धारा 13(4) एवं प्रयोग नियमों के तहत उर्वरुज प्रभुभार आस्तित्व (यों)/अचल सम्पत्ति(यों) के विरुद्ध कार्यावाही करेगा। कथित दायित्वधारी/वैध उत्तराधिकारी/वैध प्रतिनिधि कथित अधिनियम के तहत उर्वरुज प्रभुभार आस्तित्व (यों)/अचल सम्पत्ति(यों) का विकल्प पट्टे पर अन्य माध्यम से टीसीएफएफएल को पूर्ण लिखित अनुभूति के बिना अन्तराल नहीं कर सकेगा। जो कोई भी व्यक्ति अधिनियम या उसके तहत नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन में सहयोग करता है वह अधिनियम के तहत प्रावधानित के अनुसार कारावास तथा अन्वय दण्ड का भी योग्य होगा।

कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

तिथि : 18.12.2019 ह./- अधिकृत प्राधिकारी  
स्थान : कानपुर

<b>टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड</b> शाखा का पता <span> </span> : 7 वां जल विद्युतविद्युत टावर, इण्डियनल एक्सप्रेसवे, नई दिल्ली-110055
<b>अचल सम्पत्ति की विक्री के लिये विक्री सूचना</b> (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत)

विशेष परिस्मत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की विक्री के लिये ई-नीलामी विक्री सूचना

<b>ऋण खाता सं. 6424707 यतिन्द्र कुमार छोकर</b> एतद्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक/सह-ऋणधारक को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल फाइनेंसियल सर्विसेस लि. (प्रतिभूत क्रेडिटर) के पास गिरी नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका टाटा कैपिटल फाइनेंसियल सर्विसेस लि. (प्रतिभूत क्रेडिटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा कर लिया गया है, को सेंटर-4, कानपुर छोकर, एच.नं. 823, सेक्टर-14, गुणगाँव, हरियाणा-122001, तुषा छोकर, एच.नं. 823, सेक्टर-14, गुणगाँव, हरियाणा-122001, से 25 जून, 2019 को रु. 1,52,66,599.33 ( रुपये एक करोड़ ब्याज लाख छियासठ हजार पाँच सौ निम्नान्वये तथा पैसे तीस मात्र) राशि की यस्कुली के लिये "ई-नेता है जहाँ" एवं "जो भी वहाँ है" आधार पर 23 जनवरी, 2020 को विक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा परोक्ष राशि का विवरण नीचे वर्णित है।			
कथित प्रतिभूत परिसम्पत्ति को यह विक्री प्रतिभूत ऋण को यस्कुली के लिए की जागीगी तथा जैसा कि 24 जून, 2019 को सभी लागतों, ब्याज आदि के साथ रु. 1,52,66,599.63/- की राशि बकाया है। एतद्वारा सूचित किया जाता है कि विक्री में सफल होनेकी अनुपस्थिति में उक्त सम्पत्ति को जहाँ लव, विद्युतविद्युत टावर, ब्लॉक-ई, इण्डियनल एक्सप्रेसवे, नई दिल्ली-110055 में उक्त 23 जनवरी, 2020 को 2.00 बजे आम. से ई-नीलामी द्वारा विक्री की जायेगी। सम्पत्ति की खरीद के लिए ईस्पडी के डिमांड ड्राफ्ट के साथ उपरोक्त तिथिवा टाटा कैपिटल फाइनेंसियल सर्विसेस लि. के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मुहरबंद ई-नीलामी उक्त 22 जनवरी, 2020 के 5.00 बजे आम. तक प्राप्त की जायेगी। सम्पत्ति की विक्री जैसा है जहाँ है तर्त तथा उक्त सम्पत्ति से जुड़ी देयताओं तथा दायें, अनुसूची में वर्णित रूप में जिस समय तक वे सुनिश्चित हैं, के साथ की जायेगी।			
<b>प्रतिभूत सम्पत्ति का विवरण</b>	<b>कच्चा का प्रकार,</b>	<b>आरक्षित मूल्य</b>	<b>धरोहर राशि रु.</b>
औद्योगिक, प्लॉट नं. 42, सेक्टर-37, पर्स सिटी, तहसील एवं विला गुडगाँव, हरियाणा-122006, एरिया माप 509.25 वर्ग मी. (विस्तारित रूप से विवरण अंतर्गत प्रेक्षक तिथि 28.3.2016 में दिया गया है।)	सांकेतिक-रचनात्मक	रु. 3,17,02,712/-	रु. 31,70,271.20/-

विक्री के लिए रखा गई सम्पत्ति का विवरण अनुसूची में है। यदि प्राधिकृत अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित विक्री, ब्याज लागत (विक्री लागत आदि) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उन्की सन्तुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो यह विक्री रोक दी जायेगी। विक्री में आम जनता को व्यक्तिगत रूप से निविदा जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऐसे किसी भी अधिकारी या व्यक्ति जिन्हें इस विक्री के लिस्बिलिटे में किसी भी प्रकार के कर्तव्य का निर्वाहन करना हो, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे विक्री को रोकने वाली सम्पत्ति में कोई हित अर्जित या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेंगे। यदि विक्री को रोकने के पूर्व टाटा कैपिटल फाइनेंसियल सर्विसेस लि. की देय राशि का ऋणधरक पूर्ण तरह से भुगतान कर देते हैं तो यह विक्री रोक दी जायेगी। यह विक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 में निर्दिष्ट शर्तों तथा अधोलिखित शर्तों के अधीन होगी: ई-नीलामी विक्री प्लॉट 10 मिटर के असीमित विस्तार के साथ 23 जनवरी, 2020 को 2.00 बजे अप. से 3.00 बजे अप. के बीच पोर्टल https://disposalhub.com के माध्यम से आयोजित की जायेगी।

- वर्तन कारणाों से प्राधिकृत अधिकारी को स्वेच्छा से विक्री को स्थगित करने/रोकने का अधिकार है।
- सम्पत्ति का निरीक्षण 9 जनवरी, 2020 को 11 बजे पूर्व से 5.00 बजे सारा तक किया जा सकता है।
- क्रेता घोषित किये जाने वाले व्यक्ति को प्राधिकृत अधिकारी के पास तत्काल पच्चीस प्रतिशत ऋण मूल्य का भुगतान करना होगा तथा उर्वरुज विवरण होने पर क्रेता को विक्री से हटाया जायेगी।
- यदि उपरोक्त रूप में आरंभिक जमा की जाती है तो शेष ऋण मूल्य का भुगतान क्रेता को सम्पत्ति की विक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर, क्रेता को छोड़कर, अथवा यदि 15वॉ दिन अवकाश या रीवॉकल होता है तो भुगतान के बाद प्रथम कार्यालय दिवस में प्राधिकृत अधिकारी के पास करना होगा तथा उपरोक्त अधिध में क्रेताओं में चुक करने पर विक्री को नई उर्वरुजणमात्र जारी करने के बाद सम्पत्ति की फिर से विक्री की जायेगी। जमा की गई राशि टाटा कैपिटल फाइनेंसियल सर्विसेस लि. के लिये जमा की जायेगी तथा चुक करने वाले क्रेता उन सम्पत्ति अथवा उस राशि के किसी भाग से निरर्थक हो जायेगे जिसके लिये वक्त में उसकी विक्री की जायेगी। प्राधिकृत अधिकारी की ईच्छा पर सम्पत्ति की फिर से विक्री की जायेगी।
- टाटा कैपिटल फाइनेंसियल सर्विसेस लि. को सम्पत्ति के प्रति देय अधिकारों की जानकारी का विवरण गुप, सम्पत्ति पर रखे गये दायें अथवा उस प्रकृति एवं मूल्य के अन्य दायें विवरणों, मूल्य उपरोक्त के अतिरिक्त कुछ शर्तों।
- विवरणों, सहायता, प्रक्रिया तथा अनिलाइन ई-नीलामी पर प्रक्षिप्तण के लिए सम्बंधित बोलौदाता सेवा प्रदाता: मै. नरसैनज उर्वरुजण सर्विसेस लिमिटेड, नाम: हमारे विक्री पॉर्टल के लिस्बिलिटे सर्विसेस लि. (सीएसडी), द्वारा ई-मेल आईडी: csd@disposalhub.com टेली. नं.: +91 124 4233, 933, मोबाईल नं.:+91 9810029926 एवं +91-97710029933 से सम्पर्क कर सकते हैं।
- ईमेल/पी: इच्छुक बोलौदाता प्राधिकृत अधिकारी के अनुसार भट्टाचार्य, ई-मेल: Ayan.Bhattacharya@TataCapital.com, तथा मोबाईल नं. 7290010751 से सम्पर्क कर सकते हैं।
- विक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया प्रतिभूत क्रेडिटर की वेबसाइट अर्थात www.tatacapital.com में दी गई लिंक देखें।

- विक्री के लिए रखा गई सम्पत्ति का विवरण अनुसूची में है। यदि प्राधिकृत अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित विक्री, ब्याज लागत (विक्री लागत आदि) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उन्की सन्तुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो यह विक्री रोक दी जायेगी। विक्री में आम जनता को व्यक्तिगत रूप से निविदा जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऐसे किसी भी अधिकारी या व्यक्ति जिन्हें इस विक्री के लिस्बिलिटे में किसी भी प्रकार के कर्तव्य का निर्वाहन करना हो, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे विक्री को रोकने वाली सम्पत्ति में कोई हित अर्जित या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेंगे। यदि विक्री को रोकने के पूर्व टाटा कैपिटल फाइनेंसियल सर्विसेस लि. की देय राशि का ऋणधरक पूर्ण तरह से भुगतान कर देते हैं तो यह विक्री रोक दी जायेगी। यह विक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 में निर्दिष्ट शर्तों तथा अधोलिखित शर्तों के अधीन होगी: ई-नीलामी विक्री प्लॉट 10 मिटर के असीमित विस्तार के साथ 23 जनवरी, 2020 को 2.00 बजे अप. से 3.00 बजे अप. के बीच पोर्टल https://disposalhub.com के माध्यम से आयोजित की जायेगी।
- वर्तन कारणाों से प्राधिकृत अधिकारी को स्वेच्छा से विक्री को स्थगित करने/रोकने का अधिकार है।
- सम्पत्ति का निरीक्षण 9 जनवरी, 2020 को 11 बजे पूर्व से 5.00 बजे सारा तक किया जा सकता है।
- क्रेता घोषित किये जाने वाले व्यक्ति को प्राधिकृत अधिकारी के पास तत्काल पच्चीस प्रतिशत ऋण मूल्य का भुगतान करना होगा तथा उर्वरुज विवरण होने पर क्रेता को विक्री से हटाया जायेगी।
- यदि उपरोक्त रूप में आरंभिक जमा की जाती है तो शेष ऋण मूल्य का भुगतान क्रेता को सम्पत्ति की विक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर, क्रेता को छोड़कर, अथवा यदि 15वॉ दिन अवकाश या रीवॉकल होता है तो भुगतान के बाद प्रथम कार्यालय दिवस में प्राधिकृत अधिकारी के पास करना होगा तथा उपरोक्त अधिध में क्रेताओं में चुक करने पर विक्री को नई उर्वरुजणमात्र जारी करने के बाद सम्पत्ति की फिर से विक्री की जायेगी। जमा की गई राशि टाटा कैपिटल फाइनेंसियल सर्विसेस लि. के लिये जमा की जायेगी तथा चुक करने वाले क्रेता उन सम्पत्ति अथवा उस राशि के किसी भाग से निरर्थक हो जायेगे जिसके लिये वक्त में उसकी विक्री की जायेगी। प्राधिकृत अधिकारी की ईच्छा पर सम्पत्ति की फिर से विक्री की जायेगी।
- टाटा कैपिटल फाइनेंसियल सर्विसेस लि. को सम्पत्ति के प्रति देय अधिकारों की जानकारी का विवरण गुप, सम्पत्ति पर रखे गये दायें अथवा उस प्रकृति एवं मूल्य के अन्य दायें विवरणों, मूल्य उपरोक्त के अतिरिक्त कुछ शर्तों।
- विवरणों, सहायता, प्रक्रिया तथा अनिलाइन ई-नीलामी पर प्रक्षिप्तण के लिए सम्बंधित बोलौदाता सेवा प्रदाता: मै. नरसैनज उर्वरुजण सर्विसेस लिमिटेड, नाम: हमारे विक्री पॉर्टल के लिस्बिलिटे सर्विसेस लि. (सीएसडी), द्वारा ई-मेल आईडी: csd@disposalhub.com टेली. नं.: +91 124 4233, 933, मोबाईल नं.:+91 9810029926 एवं +91-97710029933 से सम्पर्क कर सकते हैं।
- ईमेल/पी: इच्छुक बोलौदाता प्राधिकृत अधिकारी के अनुसार भट्टाचार्य, ई-मेल: Ayan.Bhattacharya@TataCapital.com, तथा मोबाईल नं. 7290010751 से सम्पर्क कर सकते हैं।
- विक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया प्रतिभूत क्रेडिटर की वेबसाइट अर्थात www.tatacapital.com में दी गई लिंक देखें।

<b>टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड</b> पंजीकृत कार्यालय <span> </span> : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिंगुला बिजनेस पार्क, गणपतनगर कदम मार्ग, लोअर परेले, मुम्बई-400013 सीआरएन <span> </span> : U67190MH2008PLC187552			
<b>कच्चा सूचना</b> प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 3 के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की वित्तीय आरतियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत			
जबकि अधोहस्ताक्षरी ने नियमों के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में तथा अधिनियम के तहत टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएफएफएल) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते नीचे वर्णित कर्जदार (सह-कर्जदार(रें)/जमानती(यों) (सभी को अकेले या एक साथ मिलाकर "दायित्वधारी")/वैध उत्तराधिकारी(यों)/वैध प्रतिनिधि(यों) को पहले ही कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सम्बद्ध मौग सूचनाओं में उल्लिखित नीचे वर्णित विवरणों के अनुसार राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए एक मौग सूचना निर्गत की थी। कथित सूचनाओं की प्रतियाँ रिजल्टेंट पोस्ट ए.डी. द्वारा भेजी गयी है और अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है, तथा कथित दायित्वधारी(यों)/वैध उत्तराधिकारी(यों)/वैध प्रतिनिधि(यों) द्वारा यदि वे चाहें तो सामान्य कार्यालय घण्टों के दौरान सूचना भी कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी से सम्बद्ध प्रति प्राम कर सकते हैं।			
उपरोक्त के सम्बन्ध में, एतद्वारा कथित दायित्वधारी(यों)/वैध उत्तराधिकारी(यों)/वैध प्रतिनिधि(यों) को सम्बद्ध सूचना(ओं) की तिथि के 60 दिनों के भीतर उनके सम्बद्ध नामों के सामूहिक लिखित राशियों एवं नीचे कालम दो में वर्णित सम्बद्ध तिथियों से भावी ब्याज का कथित दायित्वधारी(यों) द्वारा क्रियात्मक ऋण अनुबन्ध एवं अन्य दस्तावेजों/प्रलेखों के साथ पठित भुगतान तथा/अथवा यस्कुली की तिथि तक टीसीएफएफएल को भुगतान करने के लिए पुनः सूचना दी जाती है। ऋण के बकाया भुगतान हेतु प्रतिभूति के रूप में क्रमशः दायित्वधारी(यों) द्वारा निम्नलिखित प्रतिभूत आस्तित्व (यों) गिरी रखा गया है।			
ऋण खाता सं.	दायित्वधारी/वैध उत्तराधिकारी/वैध प्रतिनिधि	निम्नलिखित तिथियाँ तक कुल बकाया रु.	मौग सूचना एतर्पाण की तिथि
10538479	श्री प्रेम सिंह चन्देल (कर्जदार) एवं श्रीमती हेमलता तलक रु. 20,74,199/-	19 नवम्बर, 2019	03 अक्टूबर 2019

\* भावी ब्याज, ऊपर वर्णित तिथियों पर सम्बद्ध मौग सूचनाओं की तिथि में विशेष रूप से वर्णित दर पर अतिरिक्त ब्याज, भुगतान तथा/अथवा यस्कुली की तिथि तक आकरिसमय, ब्याज, प्रभार आदि। यदि कथित दायित्वधारी उर्वरुज के अनुसार टीसीएफएफएल को भुगतान करने में असफल होंगे तो टीसीएफएफएल लागतों तथा परिणामों के प्रति कथित दायित्वधारी(यों)/वैध उत्तराधिकारी(यों)/वैध प्रतिनिधि(यों) के पूर्ण ज़िम्मेदार पर कथित अधिनियम की धारा 13(4) एवं प्रयोग नियमों के तहत उर्वरुज प्रभुभार आस्तित्व (यों)/अचल सम्पत्ति(यों) के विरुद्ध कार्यावाही करेगा। कथित दायित्वधारी/वैध उत्तराधिकारी/वैध प्रतिनिधि कथित अधिनियम के तहत उर्वरुज प्रभुभार आस्तित्व (यों)/अचल सम्पत्ति(यों) का विकल्प पट्टे पर अन्य माध्यम से टीसीएफएफएल को पूर्ण लिखित अनुभूति के बिना अन्तराल नहीं कर सकेगा। जो कोई भी व्यक्ति अधिनियम या उसके तहत नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन में सहयोग करता है वह अधिनियम के तहत प्रावधानित के अनुसार कारावास तथा अन्वय दण्ड का भी योग्य होगा।

कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

तिथि : 18.12.2019 ह./- अधिकृत प्राधिकारी  
स्थान : गाजियाबाद कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

<b>इंडियन बैंक</b> <b>Indian Bank</b> पुनर्भूत कर्जा के लिए
<b>इण्ड टिल प्रॉसीसिंग सेंटर-गाजियाबाद</b> डी-37/2, सेक्टर-50, नोएडा-201301 दूरभाष <span> </span> : 0120 2502364
<b>पाराशष्ट IV</b> [नियम ४(1)]

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आरतियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में इण्डियन बैंक का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते श्री अमित आनन्द श्री अशोक कुमार आनन्द (सह-कर्जदार एवं गिरवीकर्ता) जिसका खाता हमारी राजेन्द्र नगर शाखा के साथ है, को सूचना में उल्लिखित राशि रु. 12,90,856/- ( रुपये बारह लाख नव्हे हजार आठ सौ छपन मात्र) तथा उस पर ब्याज का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए 24.08.2018 को एक मौग सूचना निर्गत की थी। कर्जदार द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार को तथा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियम के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त अपनी शक्तियों के उपयोग में 13 दिसम्बर, 2019 को नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसामान्य को सम्पत्ति के साथ संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार 10.12.2019 तक राशि रु. 15,20,116/- ( रुपये पन्ध्र लाख इक्कीस हजार एक सौ सोलह मात्र) तथा 11.12.2019 से इस पर भावी ब्याज के लिए इण्डियन बैंक के प्रभार का विषय होगा।

हम सरफाएशी अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों तथा नियमों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं (जो प्रतिभूतियों को छुड़ाने के आपके अधिकारों के लिए निर्मित है)

<b>अचल सम्पत्ति का विवरण</b>	
मकान नं. 489, एफ-ब्लॉक, इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, लोनी रोड, बंधला, गाजियाबाद ( उ.प्र. ) की निर्मित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग। प्लॉट की माप 162 वर्ग मीटर है जो श्री अशोक आनन्द के नाम पर है।	
सीमाएं निम्नलिखित हैं <span> </span> : पूर्व <span> </span> : प्लॉट सं. 490 उत्तर <span> </span> : प्लॉट सं. 474 पश्चिम <span> </span> : प्लॉट सं. 488 दक्षिण <span> </span> : 12 मीटर चौड़ी सड़क	
दिनांक <span> </span> : 13.12.2019 अधिकृत प्राधिकारी	
स्थान <span> </span> : गाजियाबाद इण्डियन बैंक, आईआरपीसी, नोएडा	

<b>इंडियन बैंक</b> <b>Indian Bank</b> पुनर्भूत कर्जा के लिए
<b>इण्ड टिल प्रॉसीसिंग सेंटर-गाजियाबाद</b> डी-37/2, सेक्टर-50, नोएडा-201301 दूरभाष <span> </span> : 0120 2502364
<b>पाराशष्ट IV</b> [नियम ४(1)]

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आरतियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में इण्डियन बैंक का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते श्री रवित आनन्द श्री अशोक कुमार आनन्द (सह-कर्जदार एवं गिरवीकर्ता) जिसका खाता हमारी राजेन्द्र नगर शाखा के साथ है, को सूचना में उल्लिखित राशि रु. 10,11,893/- ( रुपये दस लाख ग्यारह हजार आठ सौ तिरानवे मात्र) तथा उस पर ब्याज का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए 24.08.2018 को एक मौग सूचना निर्गत की थी। कर्जदार द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार को तथा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियम के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त अपनी शक्तियों के उपयोग में 13 दिसम्बर, 2019 को नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसामान्य को सम्पत्ति के साथ संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार 10.12.2019 तक राशि रु. 11,91,621/- ( रुपये ग्यारह लाख इक्कीस हजार छः सौ इक्कीस मात्र) तथा 11.12.2019 से इस पर भावी ब्याज के लिए इण्डियन बैंक के प्रभार का विषय होगा।

हम सरफाएशी अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों तथा नियमों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं (जो प्रतिभूतियों को छुड़ाने के आपके अधिकारों के लिए निर्मित है)

<b>अचल सम्पत्ति का विवरण</b>	
मकान नं. 489, एफ-ब्लॉक, इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, लोनी रोड, बंधला, गाजियाबाद ( उ.प्र. ) की निर्मित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग। प्लॉट की माप 162 वर्ग मीटर है जो श्री अशोक आनन्द के नाम पर है।	
सीमाएं निम्नलिखित हैं <span> </span> : पूर्व <span> </span> : प्लॉट सं. 490 उत्तर <span> </span> : प्लॉट सं. 474 पश्चिम <span> </span> : प्लॉट सं. 488 दक्षिण <span> </span> : 12 मीटर चौड़ी सड़क	
दिनांक <span> </span> : 13.12.2019 अधिकृत प्राधिकारी	
स्थान <span> </span> : गाजियाबाद इण्डियन बैंक, आईआरपीसी, नोएडा	

<b>पंजाब नैशनल बैंक</b> .....सरो से का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) ...the name you can BANK upon!
<b>प्रातिभूत हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत आम जनता के लिये ई-नीलामी विक्री सूचना, अचल सम्पत्ति की विक्री के लिये ई-नीलामी विक्री सूचना</b> <b>प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम ४(6) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिये ई-नीलामी विक्री सूचना</b>

एतद्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/ मार्टेजर्स/ गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडिटर के पास गिरी रखा गई/ चार्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका कच्चा पंजाब नेशनल बैंक प्रतिभूत क्रेडिटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, को नीचे वर्णित ऋणधारकों/ गारन्टरों/ मार्टेजर्स से पंजाब नेशनल बैंक, प्रतिभूत क्रे

## विदेशी कोषों के प्रवाह के बीच सूचकांक का नया रिकार्ड

मुंबई, 17 दिसंबर (भाषा)।

व्यापार युद्ध को लेकर तनाव कम होने और विदेशी कोषों के सतत प्रवाह के बीच मंगलवार को संसेक्स और निपटी अपने

नए सर्वकालिक उच्चस्तर पर बांद हुए। बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला संसेक्स दिन में कारोबार के दौरान सर्वकालिक उच्चस्तर 41,401.65 अंक की छूने के बाद अंत में 413.45 अंक या 1.01 फीसद की बढ़त के साथ अपने नए उच्चस्तर 41,352.17 अंक पर बंद हुआ।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निपटी भी 111.05 अंक या 0.92 फीसद की बढ़त के साथ 12,165 अंक के अपने नए उच्चस्तर पर बंद हुआ। अमेरिका-चीन व्यापार करार को लेकर उम्मीद के बीच धातु कंपनियों के शेयरों में बढ़त से बाजार में तेजी आई। दूरसंचार, रियल्टी और आइटी कंपनियों के शेयरों ने भी बाजार की बढ़त में योगदान दिया। संसेक्स की कंपनियों में टाटा स्टील 4.38 फीसद बढ़ा।

## हर महीने 1.1 लाख करोड़ रुपए जीएसटी संग्रह का लक्ष्य

नई दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा)।

कर संग्रह का लक्ष्य पूरा नहीं होने के आसार के बीच वित्त मंत्रालय कर वसूली मशीनीरी को और अधिक सक्रिय कर रहा है।

सूत्रों ने सोमवार को बताया कि मंत्रालय ने 2019-20 के बचे चार महीनों में हर महीने 1.1 लाख करोड़ रुपए जीएसटी संग्रह करने का लक्ष्य रखा है। सूत्रों के अनुसार राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शीर्ष कर अधिकारियों के साथ चर्चा की और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर अंशों के हिसाब करने के लिए कदम उठाने को कहा है। अधिकारियों को यह भी ध्यान रखने को कहा गया है कि वसूली अभियान के दौरान किसी करदाताओं को अनावश्यक दिक्कत या परेशानी न हो।

# जेपी इंफ्रा ऋणशोधन मामले में एनबीसीसी की बोली मंजूर

जनसत्ता संवाददाता

नोएडा, 17 दिसंबर ।

जेपी इंफ्राटेक के वित्तीय कर्जदाताओं ने कर्ज में डूबी रीयल्टी कंपनी को ऋणशोधन प्रक्रिया के तहत खरीदने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीसीसी की बोली को मंजूरी दे दी है। वित्तीय कर्जदाताओं में बैंक और मकान खरीदार शामिल हैं। सूत्रों ने कहा कि एनबीसीसी की समाधान योजना को कर्जदाताओं की समिति ने 97.36 फीसद मतदान से मंजूरी दे दी है।

यह जेपी इंफ्राटेक के लिए खरीदार तलाशने को लेकर बोली प्रक्रिया का तीसरा दौर है। जेपी इंफ्राटेक कंपनी ऋण शोधन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में अगस्त, 2017 में गई। मामले के सफल समाधान से 20,000 मकान खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी। ये मकान खरीदार कई साल से जेपी इंफ्राटेक की नोएडा और ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में शुरू की गई विभिन्न आवासीय परियोजनाओं में फंसे हैं। एनबीसीसी ने इन लंबित परियोजनाओं को अगले साढ़े तीन साल में पूरा करने का प्रस्ताव किया है।

दोनों बोलीदाताओं एनबीसीसी और मुंबई की सुरक्षा रीयल्टी की बोलियों के लिए मतदान एक साथ हुआ और यह सोमवार की देर रात संपन्न हुआ। कर्जदाताओं की समिति में 13 बैंक और 23,000 से अधिक मकान खरीदारों के पास मतदान के अधिकार हैं। खरीदारों के पास जहां 58 फीसद वोट हैं वहीं संस्थागत कर्जदाताओं के पास 42 फीसद। बोली की मंजूरी के लिए 66 फीसद

## निर्भया व एक अन्य मामले की सुनवाई से सीजेआइ अलग

जनसत्ता ब्यूरो/एजेंसी
नई दिल्ली, 17 दिसंबर।

प्रधान न्यायाधीश एएच बोबडे ने दिसंबर, 2012 में हुए निर्भया बलात्कार और हत्याकांड में दोषियों को मौत की सजा बरकरार रखने के शीर्ष अदालत के 2017 के फैसले के खिलाफ एक मुजरिम अश्वय कुमार सिंह की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई

## सीजेएम कोर्ट में गोलीबारी में एक की मौत, दो पुलिसकर्मी घायल

लखनऊ/बिजनौर, 17 दिसंबर (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में गोलीबारी हुई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दो पुलिसकर्मियों सहित तीन लोग घायल हो गए।

पुलिस अधीक्षक संजीव त्यागी ने बताया कि हत्या मामले के दो आरोपियों को सीजेएम की अदालत में पेशी पर लाया गया था कि इस दौरान तीन शार्प शूटरों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। त्यागी ने बताया कि एक आरोपी को गोली लगने से अदालत कक्ष में ही मौत हो गई जबकि दूसरा आरोपी और दो पुलिसकर्मी घायल

● खरीदारों के पास जहां 58 फीसद वोट हैं वहीं संस्थागत कर्जदाताओं के पास 42 फीसद। बोली की मंजूरी के लिए 66 फीसद मतदान की जरूरत होती है। सूत्रों के अनुसार ज्यादातर मकान खरीदार और कर्जदाताओं ने एनबीसीसी के पक्ष में मतदान किए।

मतदान की जरूरत होती है। सूत्रों के अनुसार ज्यादातर मकान खरीदार और कर्जदाताओं ने एनबीसीसी के पक्ष में मतदान किए। जेपी इंफ्राटेक के अंतरिम समाधान पेशेवर (आइआरपी) अनुज जैन ने मकान खरीदारों के 13,000 करोड़ रुपए से अधिक के दावे और बैंकों के करीब 9,800 करोड़ रुपए के दावे को स्वीकार किया है। ताजा बोली में एनबीसीसी ने जमीन अदला-बदली समझौते के तहत 1,526 एकड़ भूमि बैंकों को पेशकश की गई है। एनबीसीसी ने यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क संपत्ति बैंकों को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव किया है। लेकिन उससे पहले वह पथकर राजस्व को लेकर करीब 2,500 करोड़ रुपये कर्ज जैसी ताकिक निर्माण व्यय का वित्त पोषण ऋण हो सके। मकान खरीदारों के लिए एनबीसीसी ने साढ़े तीन साल में करीब 20,000 प्लैट का निर्माण पूरा करने का प्रस्ताव किया है। वहीं सुरक्षा ने तीन साल का समय दिया था। राष्ट्रीय कंपनी न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के आइडीबीआइ बैंक की अगुआई वाले समूह के आवेदन को स्वीकार करने के बाद संकेत में फंसी जय प्रकाश एसोसिएट्स की अनुषंगी जेपी इंफ्राटेक अगस्त 2017 में ऋण शोधन प्रक्रिया में गई।

का गठन करने या उसका अध्यक्ष बनने पर रोक के लिए दायर याचिका की सुनवाई से भी खुद को अलग कर लिया। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कान्त के साथ मामलों की सुनवाई कर रहे प्रधान न्यायाधीश एएफ बोबडे ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे और यह जहदित याचिका किसी भी तरह के समक्ष सूचीबद्ध होगी।

हो गए। उन्होंने बताया कि सीजेएम सुरक्षित बच गए। हमलावरों का पीछा कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार लगभग छह माह पहले थाना नजीबाबाद में प्रार्पटी डीलर हाजी एहसान और उसके भांजे की ऑफिस में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

पुलिस के अनुसार लगभग छह माह पहले थाना नजीबाबाद में प्रार्पटी डीलर हाजी एहसान और उसके भांजे की ऑफिस में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि अभियुक्त जब्दार को गंभीर हालत में मेरठ रेफर किया गया है। इस घटना में दो पुलिसकर्मी घायल

में आत्मसमर्पण कर दिया था। पुलिस ने बताया कि शाहनवाज और उसके साथी सह अभियुक्त जब्दार को तिहाड़ जेल से यहां सीजेएम योगेश कुमार की अदालत में पेश किया जा रहा था कि इसी दौरान तीन हमलावर अदालत में घुस गए और उन्होंने शाहनवाज की गोली मारकर हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि अभियुक्त जब्दार को गंभीर हालत में मेरठ रेफर किया गया है। इस घटना में दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं।

### व्यापार/राष्ट्र

<b>equitas</b>	<b>एक्विटास स्मॉल फाइनांस बैंक लि.</b>
कॉर्पोरेट कार्यालय: नं. 769, सैन्सर प्लाजा, 4था तल, फेज-II, अन्ना सलाई, चेन्नई, टीएन-600 002	
<b>कच्चा सूचना</b> (नियम 8 (1) के अंतर्गत - अवल सप्पति के लिये)	
<b>जैसा कि</b> , वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत है, एक्विटास स्मॉल फाइनांस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 7.8.2019 जारी कर ऋणखलास सं. SEIBSR2003817 में ऊपर वर्णित ऋणधारकों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 8,71,823/- ( रुपये आठ लाख इक्करह हजार आठ सौ तैंसैं मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।	
चूँकि ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 12 दिसम्बर, 2019 को अधोस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।	
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय न करें. 8,71,823/- ( रुपये आठ लाख इक्करह हजार आठ सौ तैंसैं मात्र) तथा उस पर आगे की ब्याज तथा अन्य चार्ज के लिये वे, एक्विटास स्मॉल फाइनांस बैंक लिमिटेड के चार्ज के अधीन होंगे।	
<b>ऋणधारकों का नाम</b>	<b>प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण</b>
1. श्री अभित राना	ग्राम चतरगढ़, तहसील एवं जिला सिरसा में खेत नं. 147, खसरा नं. 61712 (8-0) में स्थित गैर-कृषि भूमि के रूप में आवासीय सम्पत्ति का सभी भाग, जमाबंदी वर्ष 2012-13 के अनुसार उनका शेयर 5 मरला, क्षेत्रफल मात्र 151.25 वर्ग यार्ड्स, उस पर वर्तमान एवं भविष्य के सभी संपूर्ण स्ट्रक्चर के साथ। उत्तर: खाली प्लॉट, दक्षिण: पत्नी, पूर्व: खाली प्लॉट, पश्चिम: रावेश का मकान। सिरसा के पंजीकरण उप जिला तथा सिरसा के पंजीकरण जिला में स्थित।
2. श्री श्रीवती सिंह राना	
3. श्रीमती राज कुमार राना	
L.No. SEIBSR2003817	
तिथि: 17.12.2019	हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: सिरसा	एक्विटास स्मॉल फाइनांस बैंक लि.

<b>टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड</b>	<b>कच्चा सूचना</b> (अवल सप्पति के लिये)
7वां तल, विडंबिकरत टावर, इण्डियनवेल एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055	
<b>जैसा कि</b> , वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत है, टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 14 अक्टूबर, 2019 जारी कर ऋणधारकों को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।	
ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।	
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित तिथि से उस पर ब्याज तथा दंड ब्याज, चार्जज, लागत आदि के साथ नीचे वर्णित राशि के लिये टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होंगे।	

ऋण खाता सं.	देनदार/साविधकार/ उतराधिकार/ साविधिक प्रतिनिधि (यो) का नाम	राशि एवं मांग सूचना की तिथि	कच्चा की तिथि	प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/अवल सम्पत्तियों का विवरण
202634222 एवं 20414156	1. ऑरिएण्टल एक्स्प्रेस/जे.के. हारा उसके पार्टनर उदित खुल्लर तथा प्रतीक खुल्लर, 2. प्रतीक खुल्लर, पुत्र नरिन्दर खुल्लर 3. उदित खुल्लर, पुत्र नरिन्दर खुल्लर, 4. नरिन्दर कुमार खुल्लर हारा उसके साविधिक उतराधिकार, 5. मुगु खुल्लर, पत्नी नरिन्दर कुमार खुल्लर	14 अक्टू. 2019 को र. 1,92,98,356.93 /- ( रुपये एक करोड़ ब्याने लाख अठानवे हजार तीन सौ छठ्ठस तथा पैसे तिड़ानवे मात्र)	16 दिसम्बर, 2019	डॉलरलएफ सिटी फेज-II के नाम से विदित आवासीय कॉलोनी, ग्राम शाहपुर, मध्य भाग, तहसील एवं जिला मुजफ्फर, हरियाणा-122022 में स्थित सम्पत्ति प्लॉट नं. 52, एरिया माप 300 वर्ग यार्ड्स पर निर्मित सम्पन्न वेस्टेन्ट एंड भूल, कर्नाट एरिया माप 2600 वर्ग फीट "उक्त प्लॉट" जिसका विशेष रूप से विवरण निम्नी प्रलेख तिथि 15.4.2015 में दिया गया है। चौबीसो उत्तर: दोर, दक्षिण: प्लॉट नं. 51/13, पूर्व: मध्य भाग प्लॉट नं. 53, पश्चिम: मध्य भाग, प्लॉट नं. 51
<b>स्थान: दिल्ली</b>	<b>प्राधिकृत अधिकारी</b>			
<b>तिथि: 16 दिसम्बर, 2019</b>	<b>टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड</b>			

<b>दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार</b>	<b>ई-नीलामी विक्री सूचना</b>			
<b>कार्यालय: कार्यपालक अभियंता (एसडीइल्यू) IV एस.टी.पी. कोण्डली, दिल्ली-110096</b>				
<b>प्रेस एनआईटी सं. 11(2019-20)</b>				
<b>क्रम सं.</b>	<b>कार्य का विवरण</b>	<b>अनुमानित लागत</b>	<b>ई-प्राण सल्लयून के माध्यम से निविदा प्राप्ति की तिथि</b>	<b>ई-प्राण सल्लयून के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि, समय</b>
1.	सौनिया विहार पाड के फरेलु अपग्रेडि सौवेज का शोधन 2019_DJB_185649_1	बसु दर	13.12.2019	30.12.2019 के 3.00 बजे अप. तक।
<b>इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://delhi.govprocurement.com पर देखें।</b>				
<b>पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019-20/658</b>	<b>हस्ता./- कार्यपालक अभियंता (एसडीइल्यू) IV</b>			

<b>कार्यालय: रिकवरी अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली</b>	<b>ई-नीलामी विक्री सूचना</b>	
4था तल, जौनार तार बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001		
आर.सं. नं. 26/2016		
<b>कथित रिकवरी प्रमाण पत्र में भेरे आदेश तिथि 26.11.2019 के अनुसार 29.01.2020 को सार्वजनिक ई नीलामी विक्री</b>		
<b>यह विक्री वेबसाईट https://drt.auctiontiger.net के माध्यम से ऑन लाइन ई-नीलामी होगी। नीलामी की तिथि एवं समय<span> </span>: 29.01.2020 को 3 बजे अप. से 4 बजे अप. (4 बजे अप. के बाद यदि जरूरी हुआ, 5 मिनट की अवधि के विस्तार के साथ।)</b>		
<b>संपत्ति का विवरण</b>	<b>आंशिक मूल्य</b>	<b>ईएमडी</b>
<b>फ्लैट नं. बी-705, मण्डेश्वरी सहकारी आवास रु. 49,69,687.50 ( रुपये उनचास लाख सप्तिह लिं. प्लॉट नं. डी-35P/2, फ्लैट-48, उनहार हजार छः सौ सतासी एवं पचास पैसे केसर अपार्टमेंट्स, नोएडा-201301, ड.प्र. में।</b> मात्र)		रु. 4,96,968.75 ( रु. चार लाख छिगानवे हजार नौ सौ इडसट एवं पचहत्तर पैसे मात्र)

<b>नीलामी विक्री वेबसाईट पोर्टल: https://drt.auctiontiger.net पर "ऑन लाईन ई-नीलामी" होगा।</b>	
2. ईएमडी का भुगतान रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली खाता आर.सं. नं. 26/2016 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर द्वारा किया जाएगा जिसके साथ पहचान के स्व- स्वामित्व प्रमाण (वेदर आई-कार्ड/ इडहोमिंग लाइसेंस/ पासपोर्ट) जिसमें पहचान पत्र पत्राचार का पता शामिल हो तथा पैन कार्ड की स्पष्ट स्कानवित प्रति अधिकतम 27.01.2019 के 5.00 बजे अप. तक रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-I, दिल्ली के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद प्राप्त की गई अध्या ईएमडी के मूल प्रमाण को स्वीकार नहीं किया जाएगा।	
3. ईएमडी या ईएमडी के एनईएफटी आरटीजीएस द्वारा जमा की गई मूल प्रमाण तथा प्रेषक के विवरणों जैसे पते, ई-मेल आईडी तथा मोबाईल नंबर आदि से युक्त लिफाके के ऊपर "आरसी नं. 26/2016" शीर्षकित किया जाना चाहिए।	
4. संपत्ति की विक्री "जैसा है जहां है आधार" पर की जा रही है।	
5. बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व विस्तृत निर्माण एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://www.dtauctiontiger.net देखें एवं/अथवा श्री एमनित कुमार, मुख्य प्रबंधक, श्री सुमित कुमार, अधिकारी, केना बैंक एआरएम-II साखा, संसद मार्ग, नई दिल्ली, लैंडलाइन नम्बर 25323891/23723121, मो.नं. 9773670093, 9643475460, ई-मेल: ib-c-30338@canarabank.com से सम्पर्क करें।	
6. संपत्ति का सफल बोली के पतेल पर पंजीकरण प्राप्त होगा तथा अधिम में लातिन आईडी तथा पारसवाई प्राप्त करना होगा जो ई-प्रॉक्सीमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, बी-704, वारा स्ट्रीट-II, ऑरिएट क्लब के सामने, परिसर ब्रिज, गुजरात कॉलेज के निम्न, अमरकट-380006 (गुजरात), समर्क व्यक्ति: श्री नितीशा झा, समर्क सं: 9265562821, 7082880393, 0796120051, ईमेल आईडी: delhi@auctiontiger.net, manoj@auctiontiger.net से प्राप्त करना अनिवार्य है।	
7. इच्छुक बोलीदाता, ई-प्रॉक्सीमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, बी-704, वारा स्ट्रीट-II, ऑरिएट क्लब के सामने, परिसर ब्रिज, गुजरात कॉलेज के निकट, अमरकटवाड-380006 (गुजरात), समर्क व्यक्ति: श्री नितीशा झा, समर्क सं. 9265562821, 7082880393, 0796120051, ईमेल आईडी: delhi@auctiontiger.net, manoj@auctiontiger.net से ई-नीलामी प्रक्रिया का परिशिष्टान प्राप्त कर सकते हैं।	
8. केवल ऐसे बोलीदाता अनिलानु ई-नीलामी में भाग लेने के लिए अधिकृत होंगे जिनके पास वैध वूजर आईडी एवं पारसवाई तथा डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर या एनईएफटी आरटीजीएस के माध्यम से ईएमडी के भुगतान का निश्चय प्रमाण होगा।	
9. जो इच्छुक बोलीदाता 27.01.2020 के 5 बजे अप. तक आंशिक रूप से ऊपर अपना प्रस्ताव जमा करते हैं वे ई-नीलामी में भाग लेने के योग्य होंगे जो 29.01.2020 को 3 बजे अप. से 4 बजे अप. के बीच आयोजित की जाएगी। यदि बोली अंतिम 5 मिनट में रखी जाती है तो अधिम समय सत्र: 5 मिनट आगे बढ़ जाएगी।	
10. बोलीदाता रु. 50,000/- (रुपय पचास हजार मात्र) के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर द्वारा शेयर 75% बोली के साथ 1000/- तक 2% धारा 1000 से अधिक की सकल राशि पर 1% को दर से पारडेज शुल्क का रजिस्ट्रार, डीआरटी-I, दिल्ली के पक्ष में देय डीडी/पे आर्डर द्वारा भुगतान करना होगा (उक्त धारा शेयर 75% राशि के भुगतान की स्थिति में यह उक्त राश से रिकवरी अधिकारी के पास भेजी जाना चाहिए।	
13. अपसल उद्यम बोलीदाता ई-नीलामी के तत्काल बाद रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-I, दिल्ली से प्रस्ताव रूप से अपना ईएमडी प्राप्त कर सकते हैं।	
14. रिकवरी अधिकारी को बिना कारण बताये किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने, यदि अनुपयुक्त पाई जाती है, या किसी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।	
<b>(संजु नही) रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-I, दिल्ली</b>	

[ नियम 8 (1) ]

**कच्चा सूचना** (अवल सप्पति के लिये)
जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (हिनो) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत है, एक्विटास स्मॉल फाइनांस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 2.9.2019 जारी कर ऋणधारकों को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। चूँकि ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 13 दिसम्बर, 2019 को अधोस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय न करें. 19,97594/- ( रुपये आठ लाख इक्करह हजार आठ सौ तैंसैं मात्र) तथा उस पर आगे की ब्याज तथा अन्य चार्ज के लिये वे, एक्विटास स्मॉल फाइनांस बैंक लिमिटेड के चार्ज के अधीन होंगे।

**अवल सप्पति का विवरण**

अ. नं. 839, नू शिवापुर, गली नं. 3, आगरासत कार्यालय खुर्द में सामने, पी चेंड टी खुर्द, जिला बुन्देलखर में 84 वर्ग फुट के दरिया में स्थित भूमि एवं चार सारो भाग जमा किया (उप-निर्देश 10 के कार्यालय पत्र संख्या 2017/2018 के लिये बुक नं. 1, विल्ट नं. 9712, वन 287 से 332 में अधिक विवरण सं. 379 तिथि 9.1.2018 नवींरी.

उत्तर: पारसी वर्मा का मकान

पश्चिम: योगेन्द्र शर्मा का प्लॉट।

तिथि: 17.12.2019

स्थान: खुर्द

तिथि: 13.12.2019

<b>कच्चा सूचना</b> (अवल सप्पति के लिये)	
<b>जैसा कि</b> , वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत है, एक्विटास स्मॉल फाइनांस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 7.8.2019 जारी कर ऋणधारकों को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। चूँकि ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय न करें. 8,71,823/- ( रुपये आठ लाख इक्करह हजार आठ सौ तैंसैं मात्र) तथा उस पर आगे की ब्याज तथा अन्य चार्ज के लिये वे, एक्विटास स्मॉल फाइनांस बैंक लिमिटेड के चार्ज के अधीन होंगे।	
<b>ऋणधारकों का नाम</b>	<b>प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण</b>
1. श्री अभित राना	ग्राम चतरगढ़, तहसील एवं जिला सिरसा में खेत नं. 147, खसरा नं. 61712 (8-0) में स्थित गैर-कृषि भूमि के रूप में आवासीय सम्पत्ति का सभी भाग, जमाबंदी वर्ष 2012-13 के अनुसार उनका शेयर 5 मरला, क्षेत्रफल मात्र 151.25 वर्ग यार्ड्स, उस पर वर्तमान एवं भविष्य के सभी संपूर्ण स्ट्रक्चर के साथ। उत्तर: खाली प्लॉट, दक्षिण: पत्नी, पूर्व: खाली प्लॉट, पश्चिम: रावेश का मकान। सिरसा के पंजीकरण उप जिला तथा सिरसा के पंजीकरण जिला में स्थित।
2. श्री श्रीवती सिंह राना	
3. श्रीमती राज कुमार राना	
L.No. SEIBSR2003817	
तिथि: 17.12.2019	हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: सिरसा	एक्विटास स्मॉल फाइनांस बैंक लि.

<b>केन्द्रीय मण्डलानु निगम</b>	
(भारत सरकार का उपकरण)	
निर्णयित कार्यालय 4 / 4, सीटी इन्डियनवेल एक्सटेंशन, अमरकट कांचिनियम, लीडजवाड, नई दिल्ली-110016, अर्धे - अर्धे की हिनो मन्डलानु	

ई-टेंडर बॉम्बडम सूचना (एफआईटी सं. सीडब्ल्यूसी/एचपी/आईसीईएस/2019-20) हेतु सुधिपत्र

इतिमन कार्याभित्ति परियोजना लि (आरओसीएन) ने इंडियाई टेंडर को पिछी के लिए प्रस्ताव हेतु अनुमति है। बिड प्रस्तुत करने की आंतिम तिथि 08.01.2020 आरएनएन 03.00 बजे एक बज्ा दो गई है। निम्नानु जानकारी के लिए [www.cwcprocure.com](http://www.cwcprocure.com) अथवा [www.cwacacn@nic.in](mailto:www.cwacacn@nic.in) पर जातकईन करें।

<b>प्रपन्नक सार्वजनिक घोषणा</b>	
[भारतीय विद्याला और ऋण शोध अहमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण ऋण ऋण अहमता समाधान प्रक्रिया) विनिर्माणकारी] कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए 6 के अधीन	



# झारखंड में प्रियंका आज मांगेंगी कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट

जनसता ब्यूरो

नई दिल्ली, 17 दिसंबर।

झारखंड विधानसभा चुनाव में बेहतर परिणामों की उम्मीद कर रही कांग्रेस ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की पांच जनसभाओं के बाद अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को भी चुनाव प्रचार में उतार दिया है। प्रियंका बुधवार को आदिवासी बहुल पाकुर व बरहेत विधानसभा क्षेत्रों में अलग-अलग चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उनके साथ होंगे। झारखंड में चुनाव प्रचार का प्रबंधन संभाल रहे कांग्रेस नेताओं की मारें तो सूबे के आदिवासी बहुल इलाकों में झारखंड युक्ति मोर्चा (झामुओ) का अच्छा खासा प्रभाव है जबकि पाकुर सीट कांग्रेस के ही पास है। वहां से आलमगौर

आलम पिछले विधानसभा में चुनाव जीते थे। इसबार झामओ और कांग्रेस एक ही गठबंधन का हिस्सा हैं और संथालपरगना के इस इलाके की 16 सीटों पर होने जा रहे चुनाव में कांग्रेस चार सीट पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की जनसभाएं इस तरह से आयोजित की गई हैं कि बाकी क्षेत्रों पर भी उसका असर हो। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी झारखंड में अब तक पांच जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। उन्होंने गोड्डा में हुई जनसभा में देश भर में महिलाओं से हो रही बलात्कार की घटनाओं को लेकर जो बयान हाल ही में दिया था उसको लेकर सड़क से संसद तक हंगामा हुआ और भाजपा की ओर से माफी भी मांगी गई जिसे राहुल ने साफ ठुकरा दिया। कांग्रेस प्रबंधकों का दावा है कि राहुल की जनसभाओं में भी अच्छी भीड़ जुटी और प्रियंका गांधी की

जनसभा से भी उन्हें काफी उम्मीदें हैं।

कांग्रेस के सचिव प्रणव झा ने कहा कि अब तक हुए विभिन्न चरणों के चुनाव में कांग्रेस गठबंधन की स्थिति बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जनसभाओं में जुटी भीड़ से साबित हो गया कि कांग्रेस को लोगों का भारी समर्थन हासिल है। अब प्रियंका गांधी की चुनावी सभाओं से भी बेहद फायदा होने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ प्रियंका की सभाओं के आयोजन को लेकर पूछने पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों की कर्ज माफी, धन खरीद का अधिकतम मूल्य सबसे ज्यादा निर्धारित किए जाने आदि फैसलों का झारखंड में भी व्यापक असर है और जाहिर तौर पर उनकी मौजूदगी एक प्रकार से झारखंड के मतदाताओं के लिए एक प्रकार का आश्वासन भी होगी।

## दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

कार्यालय: कार्यालय अधिव्यता (परिचय)-I  
ओ.एच.टी. बेरीवाला बाग, सुभाष नगर, नई दिल्ली-110064  
ग्रैंस निवृत्त सूचना सं. 70/डब्ल्यू-1 (2019-20)

क्रम सं.	कार्य का विवरण	निवृत्त राशि	ई-अनुदान संख्या/कार्य का नाम/सं निवृत्त व्यक्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	परिचय के अंतर्गत कार्य नं.-18एए, एसी 30, जनकपुरी में डी-2 ब्लॉक, जीवन पाक में उप-विभाजित प्लाटी में नये वाटर लाइन का प्रारंभिक तह विद्यमान। निवृत्त आईडी: 2019.DJB.185615.2	र.	30.10.17/8- 26.12.2019 के 3.00 बजे अप. तक

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाइट <https://govtprocurement.delhi.gov.in> पर देखें।  
पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी  
विज्ञापन सं. जे.एस.सी. 2019-20/665

## टाटा कैपिटल फाईनांसियल सर्विसेस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 11 बी मंजिल, टॉवर ए, पेनीसुला बिजनेस पार्क, गणतंत्रता कदम मार्ग, लोवर फेल, मुम्बई-400 013.

**संशोधन**  
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 17.12.2019 को इसी समूह यात्रा पर में "अवल संपत्ति की विक्री के लिए विक्री सूचना" शीर्षक से ऋणी राधा गुप्ता के प्रकाशित विज्ञापन में त्रुटिपूर्ण कंपनी का नाम टाटा कैपिटल फाईनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के स्थान पर टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनांस लिमिटेड प्रकाशित हो गया है, जिसे टाटा कैपिटल फाईनांसियल सर्विसेस लिमिटेड पत्रा जावें। शेष विवरण यथावत रहेगा।  
ह/-  
प्राधिकृत अधिकारी  
टाटा कैपिटल फाईनांसियल सर्विसेस लिमिटेड

## ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

(राज्य सरकार का उपक्रम)  
कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट नं. 3, लोवर-अ, इस्टोवियनन एरिया, गुरुग्राम - 122001

**सूचना**  
एलएवारा सूचित किया जाता है कि बैंक की निम्नलिखित प्रतिभूतियों के शेयर सर्टिफिकेट खो गए/गुप्त हो गए हैं तथा इन शेयर धारकों ने सुप्रीम कोर्ट शेयर सर्टिफिकेट जारी करने के लिए बैंक को आवेदन किया है।  
कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट नं. 3, लोवर-अ, इस्टोवियनन एरिया, गुरुग्राम - 122001

क्र.सं.	क्र.सं.	शेयर धारक का नाम	सर्टिफिकेट सं.	विशिष्ट सं.	शेयर की संख्या
3862	00530531	लाल वर सिंह	335273	161527101 -161527200	100
3863	00277346	सर्वजित कौर बहल	526220	180621801 -180621900	100
3864	00150277	सुभाष जैन	328245	160624301 -160624400	100

स्थान: गुरुग्राम  
दिनांक: 17.12.2019

# अल्पसंख्यक दर्जे के मुद्दे पर दायर याचिका खारिज

जनसता ब्यूरो

नई दिल्ली, 17 दिसंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने मुसलिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने संबंधी केंद्र की 26 साल पुरानी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि समूचे भारत की आबादी के परिप्रेक्ष्य में धर्म पर विचार किया जाना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश एएफ बोवड, न्यायमूर्ति वीआर गवई और न्यायमूर्ति सुर्यकांत के तीन सदस्यीय पीठ ने राज्य में आबादी के आधार पर किसी समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए दिशानिर्देश के वास्ते भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

पीठ ने उपाध्याय की याचिका खारिज करते हुए कहा- समूचे भारत के आधार पर धर्म पर विचार करना चाहिए। इसमें क्या परेशानी है अगर कश्मीर में मुसलिम बहुमत है? लेकिन देश के अन्य हिस्सों में अल्पसंख्यक हैं। उपाध्याय ने अपनी याचिका में अदालत से अनुरोध किया था कि किसी भी धार्मिक समुदाय को किसी राज्य विशेष में उनकी आबादी के आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया जाए। उन्होंने दावा किया था कि अरब राज्यों में हिंदू

अल्पसंख्यक हैं लेकिन उन्हें वहां अल्पसंख्यकों के लाभों से वंचित किया जा रहा है।

पीठ ने कहा- भाषाएं तो राज्य के आधार पर सीमित हैं। धर्म की तो राज्य सीमाएं नहीं हैं। हमें इस मामले में अखिल भारतीय दृष्टिकोण अपनाना होगा। लक्षद्वीप में मुसलिम तो हिंदू कानून का पालन करते हैं। पीठ ने अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल के इस कथन का भी संज्ञान लिया कि शीर्ष अदालत के कई फैसले हैं जिनमें कहा गया है कि किसी भी धार्मिक समूह के अल्पसंख्यक होने का निर्धारण उसकी अखिल भारतीय आबादी के आधार पर किया जा सकता है। अटार्नी जनरल इस मामले में अदालत की मदद कर रहे थे।

इस याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई के दौरान उपाध्याय की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मोहन पराशरप से पीठ ने ऐसे फैसलों के बारे में जानना चाहा जिनमें कहा गया है कि राज्य की आबादी के आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा देने के संदर्भ में विचार किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर निर्णय के लिए दिशानिर्देश कैसे बनाए जा सकते हैं। जजों ने टिप्पणी की- हम नहीं समझते कि हमें इस पर विचार करना चाहिए। राज्यों के सुजन के लिए भाषाओं को आधार बनाया गया है लेकिन धर्म के मामले में ऐसा नहीं है। अतः राज्य की आबादी के आधार पर किसी समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जा सकता है।

## सर्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाइंट, मेसर्स म्यूट फाईनांस लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालय: तल 2, म्यूट चेम्बर, बैनगी रोड, कोच्चि - 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाष: +91 484-2396478, 2394712, फ़ैक्स: +91 484-2396506, emails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण सूचना में अस्फल ऋणियों के गिरवी रखे सामे के गहनों (30.09.2018) की अवधि तक NPA खाता) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।  
नीलामी की तिथि: 23.12.2019

**Faridabad-Neelam Floyer:** MAL-1773, MUL-897, 850, 876, 888, 891, 964, 967, 990, 1001, 1008, 1012, 1084, 1114, 1125, 1149, 1150, 1167, 1185, 1192, 1218, 1231, 1238, 1260, 1282, 1295, 1296, Faridabad-Nehru Ground: MHP-11, MUL-50, 472, 2289, 2933, 2945, 3021, 3096, 3097, 3104, 3108, 3133, 3135, 3230, 3307, 3435, 3437, 3446, 3549, 3563, 3602, 3605, 3654, 3658, MWS-11, 16, 19, 33, 90, 107, 168, 224, 265, 315, 329, 418, 462, 484, 579, 582, 585, 588, 607, 615, 616, 619, 631, 635, 764, 800, 828, 834, 835, 844, 890, 954, 976, 1017, 1018, 1041, 1062, 1079, 1088, 1108, 1112, 1116, 1153, 1156, 1191, 1225, 1234, 1249, 1267, 1279, 1289, 1364, 1431, 1501, 1521, 1527, 1548, 1567, 1614, 1622, 1633, 1675, 1679, 1734, 1748, 1776, 1796, 1806, 1864, 1968, 1926, 1930, 1951, 1968, 1997, 1998, 1999, 2003, 2012, 2013, 2073, 2075, 2076, 2080, 2100, 2102, 2109, 2134, 2135, 2137, 2138, 2147, 2158, 2198, 2249, 2253, 2254, 2276, 2297, 2308, 2338, 2340, 2341, 2354, 2374, 2393, 2398, 2487, 2503, 2528, 2541, 2609, 2687, 2795, 2803, 2836, 2910, 2922, 2966, 3145, Faridabad-Sector-15: MUL-511, 514, 590, 597, 615, 616, 630, 648, 687, 739, 745, 750, 862, 865, 922, 946, 1008, Faridabad-Sector-28: MAL-1357, MUL-1430, 1431, 1479, 1520, 1521, 1529, 1530, 1567, 1572, 1590, 1713, 1735, 1750, 1779, 1781, 1782, 1784, 1785, 1817, MWS-53, 54, 57, 77, 131, 145, 172, 205, 226, 233, 236, 241, 242, 280, 285, 319, 333, 341, 349, 352, 356, 372, 459, 480, 486, 489, 556, 588, 637, 643, 677, 727, 748, 766, 767, 832, 840, 843, 851, 877, 884, 895, 898, 923, 962, 1013, 1067, 1097, 1112, 1164, 1227, 1319, 1364, 1441, 1501, 1584, 1809, 1982, Faridabad-NIT: MUL-1210, 1231, 1272, 1401, 1468, 1532, 1552, 1574, 1588, 1600, 1644, 1657, 1780, 1791, 1795, 1797, 1886, 2003, 2050, 2053, 2106, 2114, 2121, 2202, 2206, 2222, MWS-54, 61, 126, 407, 490, Faridabad-Sector-16: MSL-13238, MUL-874, 1079, 1083, 1100, 1132, 1152, 1161, 1162, 1205, 1222, 1223, 1256, 1282, 1512, 1355, 1363, 1366, 1367, 1415, 1488, 1499, 1501, 1562, 1517, 1531, 1565, 1590, 1597, 1603, 1631, 1634, 1667, 1668, 1712, 1742, 1751, 1756, 1761, 1812, 1816, 1825, 1827, 1842, 1861, 1919, 1948, 1998, 2032, 2035, 2047, 2069, 2078, 2099, 2105, 2106, 2107, 2154, 2161, 2162, 2198, 2370, 2679, Faridabad-Sector-21C: MUL-232, 834, 780, 847, 866, 867, 869, 856, 993, 994, 1004, 1009, 1022, 1023, 1071, 1100, 1107, 1162, 1170, 1175, 1214, 1260, 1264, 1269, 1280, 1291, 1303, 1322, 1389, 1400, 1426, 1596, 1604, Faridabad-(HA): MSL-10627, 10634, MUL-863, 941, 942, 956, 1021, 1067, 1109, 1147, 1191, 1194, 1229, 1235, 1356, 1360, 1367, 1386, 1411, 1436, 1455, 1465, 1495, 1496, 1521, 1530, 1552, 1579, 1580, 1608, 1609, 1616, 1611, 1622, 1623, 1646, MWS-63, 116, 187, 191, 303, Faridabad-Sector-17-(HA): MUL-549, 582, 584, 602, 603, 651, 663, 676, 682, 697, 708, 815, 824, 832, 922, 926, Ballabhgar-(HA): MSL-12698, MUL-1031, 1044, 1058, 1141, 1152, 1178, 1216, 1257, 1273, 1282, 1337, 1375, 1415, 1491, 1540, 1642, 1653, 1663, 1686, 1712, 1720, 1727, 1770, 1917, 1919, 1944, 1961, 1987, 1996, 1999, 2077, 2096, 2124, MWS-22, 58, 266, Neelam Floyer-Sector 20: MUL-1202, 1253, 1279, 1299, 1348, 1354, 1367, 1534, 1562, 1590, 1656, 1661, 1723, 1764, 1772, 1787, 1789, 1812, 1821, 1882, 1906, 1920, 1926, 1927, 1967, 2035, 2047, 2093, 2107, 2112, 2134, 2167, 2174, 2188, MWS-11, 16, 19, 33, 90, 107, 168, 224, 265, 315, 329, 418, 462, 484, 579, 582, 585, 588, 607, 615, 616, 619, 631, 635, 764, 800, 828, 834, 835, 844, 890, 954, 976, 1017, 1018, 1041, 1062, 1079, 1088, 1108, 1112, 1116, 1153, 1156, 1191, 1225, 1234, 1249, 1267, 1279, 1289, 1364, 1431, 1501, 1521, 1527, 1548, 1567, 1614, 1622, 1633, 1675, 1679, 1734, 1748, 1776, 1796, 1806, 1864, 1968, 1926, 1930, 1951, 1968, 1997, 1998, 1999, 2003, 2012, 2013, 2073, 2075, 2076, 2080, 2100, 2102, 2109, 2134, 2135, 2137, 2138, 2147, 2158, 2198, 2249, 2253, 2254, 2276, 2297, 2308, 2338, 2340, 2341, 2354, 2374, 2393, 2398, 2487, 2503, 2528, 2541, 2609, 2687, 2795, 2803, 2836, 2910, 2922, 2966, 3145, Faridabad-Sector-15: MUL-511, 514, 590, 597, 615, 616, 630, 648, 687, 739, 745, 750, 862, 865, 922, 946, 1008, Faridabad-Sector-28: MAL-1357, MUL-1430, 1431, 1479, 1520, 1521, 1529, 1530, 1567, 1572, 1590, 1713, 1735, 1750, 1779, 1781, 1782, 1784, 1785, 1817, MWS-53, 54, 57, 77, 131, 145, 172, 205, 226, 233, 236, 241, 242, 280, 285, 319, 333, 341, 349, 352, 356, 372, 459, 480, 486, 489, 556, 588, 637, 643, 677, 727, 748, 766, 767, 832, 840, 843, 851, 877, 884, 895, 898, 923, 962, 1013, 1067, 1097, 1112, 1164, 1227, 1319, 1364, 1441, 1501, 1584, 1809, 1982, Faridabad-NIT: MUL-1210, 1231, 1272, 1401, 1468, 1532, 1552, 1574, 1588, 1600, 1644, 1657, 1780, 1791, 1795, 1797, 1886, 2003, 2050, 2053, 2106, 2114, 2121, 2202, 2206, 2222, MWS-54, 61, 126, 407, 490, Faridabad-Sector-16: MSL-13238, MUL-874, 1079, 1083, 1100, 1132, 1152, 1161, 1162, 1205, 1222, 1223, 1256, 1282, 1512, 1355, 1363, 1366, 1367, 1415, 1488, 1499, 1501, 1562, 1517, 1531, 1565, 1590, 1597, 1603, 1631, 1634, 1667, 1668, 1712, 1742, 1751, 1756, 1761, 1812, 1816, 1825, 1827, 1842, 1861, 1919, 1948, 1998, 2032, 2035, 2047, 2069, 2078, 2099, 2105, 2106, 2107, 2154, 2161, 2162, 2198, 2370, 2679, Faridabad-Sector-21C: MUL-232, 834, 780, 847, 866, 867, 869, 856, 993, 994, 1004, 1009, 1022, 1023, 1071, 1100, 1107, 1162, 1170, 1175, 1214, 1260, 1264, 1269, 1280, 1291, 1303, 1322, 1389, 1400, 1426, 1596, 1604, Faridabad-(HA): MSL-10627, 10634, MUL-863, 941, 942, 956, 1021, 1067, 1109, 1147, 1191, 1194, 1229, 1235, 1356, 1360, 1367, 1386, 1411, 1436, 1455, 1465, 1495, 1496, 1521, 1530, 1552, 1579, 1580, 1608, 1609, 1616, 1611, 1622, 1623, 1646, MWS-63, 116, 187, 191, 303, Faridabad-Sector-17-(HA): MUL-549, 582, 584, 602, 603, 651, 663, 676, 682, 697, 708, 815, 824, 832, 922, 926, Ballabhgar-(HA): MSL-12698, MUL-1031, 1044, 1058, 1141, 1152, 1178, 1216, 1257, 1273, 1282, 1337, 1375, 1415, 1491, 1540, 1642, 1653, 1663, 1686, 1712, 1720, 1727, 1770, 1917, 1919, 1944, 1961, 1987, 1996, 1999, 2077, 2096, 2124, MWS-22, 58, 266, Neelam Floyer-Sector 20: MUL-1202, 1253, 1279, 1299, 1348, 1354, 1367, 1534, 1562, 1590, 1656, 1661, 1723, 1764, 1772, 1787, 1789, 1812, 1821, 1882, 1906, 1920, 1926, 1927, 1967, 2035, 2047, 2093, 2107, 2112, 2134, 2167, 2174, 2188, MWS-11, 16, 19, 33, 90, 107, 168, 224, 265, 315, 329, 418, 462, 484, 579, 582, 585, 588, 607, 615, 616, 619, 631, 635, 764, 800, 828, 834, 835, 844, 890, 954, 976, 1017, 1018, 1041, 1062, 1079, 1088, 1108, 1112, 1116, 1153, 1156, 1191, 1225, 1234, 1249, 1267, 1279, 1289, 1364, 1431, 1501, 1521, 1527, 1548, 1567, 1614, 1622, 1633, 1675, 1679, 1734, 1748, 1776, 1796, 1806, 1864, 1968, 1926, 1930, 1951, 1968, 1997, 1998, 1999, 2003, 2012, 2013, 2073, 2075, 2076, 2080, 2100, 2102, 2109, 2134, 2135, 2137, 2138, 2147, 2158, 2198, 2249, 2253, 2254, 2276, 2297, 2308, 2338, 2340, 2341, 2354, 2374, 2393, 2398, 2487, 2503, 2528, 2541, 2609, 2687, 2795, 2803, 2836, 2910, 2922, 2966, 3145, Faridabad-Sector-15: MUL-511, 514, 590, 597, 615, 616, 630, 648, 687, 739, 745, 750, 862, 865, 922, 946, 1008, Faridabad-Sector-28: MAL-1357, MUL-1430, 1431, 1479, 1520, 1521, 1529, 1530, 1567, 1572, 1590, 1713, 1735, 1750, 1779, 1781, 1782, 1784, 1785, 1817, MWS-53, 54, 57, 77, 131, 145, 172, 205, 226, 233, 236, 241, 242, 280, 285, 319, 333, 341, 349, 352, 356, 372, 459, 480, 486, 489, 556, 588, 637, 643, 677, 727, 748, 766, 767, 832, 840, 843, 851, 877, 884, 895, 898, 923, 962, 1013, 1067, 1097, 1112, 1164, 1227, 1319, 1364, 1441, 1501, 1584, 1809, 1982, Faridabad-NIT: MUL-1210, 1231, 1272, 1401, 1468, 1532, 1552, 1574, 1588, 1600, 1644, 1657, 1780, 1791, 1795, 1797, 1886, 2003, 2050, 2053, 2106, 2114, 2121, 2202, 2206, 2222, MWS-54, 61, 126, 407, 490, Faridabad-Sector-16: MSL-13238, MUL-874, 1079, 1083, 1100, 1132, 1152, 1161, 1162, 1205, 1222, 1223, 1256, 1282, 1512, 1355, 1363, 1366, 1367, 1415, 1488, 1499, 1501, 1562, 1517, 1531, 1565, 1590, 1597, 1603, 1631, 1634, 1667, 1668, 1712, 1742, 1751, 1756, 1761, 1812, 1816, 1825, 1827, 1842, 1861, 1919, 1948, 1998, 2032, 2035, 2047, 2069, 2078, 2099, 2105, 2106, 2107, 2154, 2161, 2162, 2198, 2370, 2679, Faridabad-Sector-21C: MUL-232, 834, 780, 847, 866, 867, 869, 856, 993, 994, 1004, 1009, 1022, 1023, 1071, 1100, 1107, 1162, 1170, 1175, 1214, 1260, 1264, 1269, 1280, 1291, 1303, 1322, 1389, 1400, 1426, 1596, 1604, Faridabad-(HA): MSL-10627, 10634, MUL-863, 941, 94





# स्त्री-पुरुष असमानता में भारत 112वें स्थान पर स्वास्थ्य, आर्थिक भागीदारी में स्थिति ज्यादा खराब

नई दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा)।

महिलाओं की स्वास्थ्य व उत्तरजीविता और आर्थिक भागीदारी क्षेत्र में स्थिति खराब होने के बीच स्त्री-पुरुष असमानता पर तैयार रिपोर्ट में भारत एक साल पहले के मुकाबले चार पायदान फिसल कर 112वें स्थान पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य और आर्थिक भागीदारी इन दो क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी के मामले में भारत सबसे नीचे स्थान पाने वाले पांच देशों में शामिल है। विश्व आर्थिक मंच की महिला और पुरुषों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते फासले से संबंधित इस वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह बात कही गई है। भारत पिछले साल इस सूची में 108वें पायदान पर था। विश्व आर्थिक मंच की स्त्री-पुरुष अंतर रिपोर्ट में भारत का स्थान 106, श्रीलंका (102), नेपाल

(101), ब्राजील (92), इंडोनेशिया (85) और बांग्लादेश (50) से भी नीचे है। स्त्री-पुरुष के बीच सबसे ज्यादा समानता आइसलैंड में है। स्त्री-पुरुष के बीच अंतर सूचकांक में स्थिति सबसे खराब है। उसे 153वां स्थान मिला है जबकि इराक को 152वें और पाकिस्तान को 151वें पायदान पर रखा गया है। विश्व आर्थिक मंच की इस रिपोर्ट के मुताबिक स्त्री-पुरुष असमानता को चार मुख्य कारकों के आधार पर तय किया गया है। इनमें महिलाओं को उपलब्ध आर्थिक अवसर, राजनीतिक सशक्तीकरण, शैक्षणिक उपलब्धियां और स्वास्थ्य व जीवन प्रत्याशा शामिल हैं। विश्व आर्थिक मंच ने कहा, '2019 में स्त्री-पुरुष के बीच विभिन्न क्षेत्रों में जो अंतर है, उसे पाटने में 99.5 साल खराब (106), श्रीलंका (102), नेपाल

सुधार देखा गया है। इस समय अनुमान लगाया था कि महिला पुरुषों के बीच असमानता को दूर करने में 108 साल लगेगे।' इस प्रकार, राजनीतिक असमानता को खत्म करने में पिछले वर्ष 107 साल के मुकाबले अब 95 साल लगेगे। हालांकि, आर्थिक अवसर के मामले में स्थिति खराब हुई है। आर्थिक अवसरों के मामले में स्त्री-पुरुष के बीच व्याप्त अंतर को कम करने में 257 साल लगेगे। पिछले साल इसमें 202 साल लगने का अनुमान जताया गया था। विश्व बैंक ने अपनी पहली स्त्री-पुरुष अंतर रिपोर्ट 2006 में पेश की थी। उस समय भारत 98वें पायदान पर था। आज भारत की रैंकिंग उससे भी कम है। तब से लेकर, रैंकिंग के लिए उपयोग होने वाले चार में से तीन कारकों में भारत की स्थिति खराब हुई है।

# विश्व भर में 2019 में 49 पत्रकारों की हत्या हुई

पेरिस, 17 दिसंबर (एएफपी)।

विश्वभर में 2019 में 49 पत्रकारों की हत्या की गई। यह आंकड़ा पिछले 16 साल में सबसे कम है लेकिन लोकांतरिक देशों में पत्रकारों की हत्या की घटनाएं चिंता का विषय बन गई हैं। पेरिस स्थित निगरानी संगठन 'आरएसएफ' ने बताया कि इनमें से अधिकतर पत्रकार यमन, सीरिया और अफगानिस्तान में संघर्ष की रिपोर्टिंग के दौरान मारे गए जो दिखाता है कि पत्रकारिता एक खतरनाक पेशा बना हुआ है। संगठन ने कहा कि पिछले दो दशक में औसतन हर साल 80 पत्रकारों की जान गई है। इसके प्रमुख क्रिस्टोफ डेलोर ने कहा

कि शांतिप्रिय देशों में पत्रकारों की हत्या की घटनाएं खतरे की घंटी भी है, क्योंकि केवल मेक्सिको में ही दस पत्रकार मारे गए हैं। उन्होंने कहा, 'लातिन अमेरिका में कुल 14 पत्रकार मारे गए जो पश्चिम एशिया जितना ही खतरनाक स्थान बन गया है।' डेलोर ने कहा कि संघर्षप्रस्त इलाकों में आंकड़ों में आई कमी खुशी की बात है लेकिन 'लोकतांत्रिक देशों में अधिकतर पत्रकारों को उनके काम के लिए निशाना बनाया जा रहा है, जो कि लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है।' 'आरएसएफ' के अनुसार भले ही पत्रकारों की जान कम जा रही है लेकिन अधिकतर पत्रकार सलाखों के पीछे हैं। 2019 में करीब 389 पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया, जो कि पिछले

साल की तुलना में 12 फीसद अधिक है। इनमें से आधे, चीन, मिस्र और सऊदी अरब में कैद हैं। 'आरएसएफ' के अनुसार विश्व भर में 57 पत्रकारों को बंदी भी बना कर रखा हुआ है। इनमें से अधिकतर सीरिया, यमन, इराक और यूक्रेन में बंदी बनाए गए हैं।

# सुरक्षा परिषद कश्मीर मुद्दे पर नहीं करेगी चर्चा

संयुक्त राष्ट्र/नई दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा)।

माना जाता है कि चीन ने फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मंगलवार को जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर चर्चा कराए जाने का आग्रह किया है, लेकिन राजनयिक सूत्रों ने कहा कि मुद्दे पर परिषद में चर्चा नहीं होगी। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान के मित्र

चीन ने जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में मंगलवार को चर्चा कराए जाने का आग्रह किया है। मामलों पर मंगलवार को दोपहर बाद बंद कमेरे में परामर्श के दौरान 'अन्य मामलों' के तहत सुरक्षा परिषद में चर्चा होने की पहले उम्मीद थी। हालांकि अब माना जाता है कि मंगलवार को चर्चा के लिए निर्धारित यह मामला बाद में हुए

घटनाक्रमों के चलते अब चर्चा के लिए नहीं आएगा। फ्रांस के राजनयिक सूत्रों ने कहा कि कश्मीर पर सुरक्षा परिषद में मंगलवार को चर्चा नहीं होगी। इस संबंध में एक सूत्र ने कहा, 'हमारी स्थिति बेहद स्पष्ट रही है। कश्मीर मुद्दे पर द्विपक्षीय चर्चा होनी चाहिए। हमने हाल में संयुक्त राष्ट्र सहित कई बार यह रेखांकित किया है।'

क्र.सं.	शाखा का नाम	खाते का नाम	कंपनियों का नाम और पता	बंदक सम्पत्ति का विवरण	19/2019 नोटिस की तिथि/गणना तिथि के अनुसार बन्धक यथि	सांकेतिक कच्चे की तिथि	प्राधिकृत अधिकारी का नाम
1.	जेबरी (7981)	श्री संजय कुमार पुत्र स्वामी श्री बालेश्वर	श्रीमती प्रकाशी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री बालेश्वर श्री सोनू पुत्र स्वर्गीय श्री बालेश्वर श्री बिट्टू पुत्र स्वर्गीय श्री बालेश्वर (स्वर्गीय श्री संजय कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री बालेश्वर) के सभी कानूनी उत्तराधिकारी) पता: ग्राम दुल्हेडा बौहान, परमना वीराला, तह. सरधना, मेरठ, यूपी - 280110	प्लॉट नं. 25 क्षेत्रफल 75.62 वर्गमीटर मीटर (90.40 वर्ग गज), गी-1, मुकदमापुर प्लेटेड, परमना वीराला, तहसील सरधना, जिला- मेरठ सावित्री स्वामिनी श्रीमती प्रकाशी देवी पत्नी स्व. श्री बालेश्वर (स्वर्गीय का भाई), श्री बिट्टू पुत्र स्व. श्री बालेश्वर (स्वर्गीय का भाई) स्वर्गीय श्री संजय कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री बालेश्वर (स्वर्गीय) / बंकाकलता / मालिका के तमाम कानूनी उत्तराधिकारी सोनिया-पूर्व 37 फीट-लॉट नंबर 24 परिसर: 87 फीट-लॉट नंबर 26 उत्तर- 22 फीट- अन्य की भूमि दक्षिण: 22 फीट-उत्तरा 25 फीट चौड़ा	08.05.2019	₹. 17,02,886.86 दिनांक 01.04.2019 से ब्याज व अन्य खर्च	श्री संजीव शर्मा
2.	जेबरी (7981)	श्री विजय कुमार पाल पुत्र श्री श्याम लाल	श्री विजय कुमार पाल पुत्र श्री श्याम लाल पता 130/4, पॉकेट-सी, श्रद्धापुरी, फेस-2, कंकर खेड़ा, मेरठ यूपी 250110, 250.110 मो.ब. 9634944186, 7249927425	एक ई-हक्कूरा प्रलेट कंचल पट्टली मजिल पर, असर नंबर सी-130/8 क्षेत्रफल 33.86 वर्ग मीटर, स्थित पॉकेट-सी, फेस-2, अदापुरी, कंकर खेड़ा, मेरठ यूपी 250110, तापति श्री विजय कुमार पाल पुत्र श्री श्याम लाल के नाम सोमवार-पूर्व, प्लॉट नंबर 130/5 पहिसर: प्लेट नंबर 131/5 उत्तर-लला 6 मीटर चौड़ा दक्षिण प्लेट नंबर 130/5	05.09.2019	₹. 10,02,221/- दिनांक 01.07.2018 से ब्याज व अन्य खर्च	श्री संजीव शर्मा

दिनांक:- 13.12.2019 स्थान:- जेबरी प्राधिकृत अधिकारी

**pnb Housing Finance Limited**

पंजीकृत कार्यालय : 9वीं मंजिल, अन्वरिश भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001  
 दूरभाष : 011-23357171, 23357172, 23705414 वेबसाइट : www.pnbhousing.com  
 शाखा पता : म.नं. 36, ब्लॉक : बी-1, भूतल, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, दूरभाष : 011-25546073/74/75 70/74, ई-मेल : janakpuri@pnbhousing.com, वेबसाइट : www.pnbhousing.com

कच्चा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

अधिकृत अधिकारी ने विशेष आरक्षण के प्रतिबन्धितकृत पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के नियम 8(1) के अधिनियम में तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शर्तियों के उपयोग में पीपल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते प्रत्येक खाते के सम्बन्धित अधिकृतियों पर कब्जा सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सम्बन्धित कर्जदारों से प्रत्येक खाते के सम्बन्धित अधिकृतियों का पुनर्निर्माण करने के लिए कब्जे हुए एक महीने सूचना निर्मित की थी। कर्जदारों के पुनर्निर्माण में असफल रहने के कारण पतनकार कर्जदारों को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरों के नाते प्रत्येक खाते के लिए उपलब्ध सम-सीमा के विषय में कर्जदारों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है। विशेष रूप से कर्जदारों तथा जनसामान्य को पतनकार सम्पत्तियों से किसी प्रकार का संयोजन न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का संयोजन ब्रह्म अनुबन्ध के अनुसार कथित राशि तथा उस पर ब्याज के लिए पीपल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा। प्रतिभूति आरक्षणों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध सम-सीमा के विषय में कर्जदारों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र.सं.	क्रेता का नाम	कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती का नाम	मौज सूचना की तिथि	बकाया राशि	कच्चा करने की तिथि	मिचलिकृत सम्पत्ति का विवरण
1.	HOU/JAN/0815/237978	श्री आशीष शर्मा	22.08.2019	₹. 83,19,578.26	12.12.2019 (सांकेतिक)	प्लॉट नं. 2557, भूतल, सेक्टर ए, ग्रीन फोर्ड कॉलोनी, फरीदाबाद, हरियाणा-121001

स्थान : जनकपुरी, दिनांक : 17.12.2019 अधिकृत प्राधिकारी, पीपल्स हाउसिंग फाइनेंस लि.

**Corporation Bank**  
 (A Premier Public Sector Bank)

क्षेत्रीय कार्यालय : दिल्ली उत्तरी, दूसरी मंजिल, फेज रोड-1, नई दिल्ली-110005, दूरभाष सं. 011-28754615, 28754642 ई-मेल आईडी : DLIREC@CORPBANK.CO.IN वेबसाइट : WWW.CORPBANK.COM

अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6 के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की विशेष आरक्षणों तथा प्रवर्तन के प्रतिबन्धितकृत एवं पुनर्निर्माण के तहत एक आरक्षणों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(री) एवं जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति लेनदार के पास नीचे वर्णित बंधक/प्रभारित अचल सम्पत्ति जिसका मौलिक कच्चा कॉर्पोरेशन बैंक (प्रतिभूति लेनदार) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया गया है, की बिक्री निम्नलिखित कर्जदार(री) एवं जमानती(यों) से कॉर्पोरेशन बैंक के निम्नलिखित बंधकों की वसूली हेतु निम्नलिखित तिथियों पर "जहाँ है वहाँ है", "जो है जैसे है" तथा "जो कुछ भी है वहाँ है" के आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि भी नीचे वर्णित है :

बैंक का नाम तथा पता	कर्जदार/जमानती/यों के नाम	बकाया राशि-
गाजियाबाद रामपुरी शाखा, दूरभाष नं. 0120-2643915, 2641568	कर्जदार : निशा एन्टरप्राइजेज इसके प्रोपराइटर श्रीमती शालिनी गुप्ता द्वारा प्रतिनिधानित, एल-11, विजय चौक, निकट कुमार साड़ी घर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 (साथ ही : मकान नं. एल-11/12, दूसरी मंजिल, विजय चौक, लक्ष्मी नगर, निकट कुमार साड़ी घर दिल्ली-110092) जमानती : श्री नीरज गुप्ता, मकान नं. एल-11, विजय चौक, निकट कुमार साड़ी घर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092	₹. 25,30,458.00 + इस पर ब्याज एवं अन्य प्रभार

सम्पत्ति सं. 1 : स. जे-6-ए, फ्लोर नं. 6/12, ग्राम खुरेजी खास, जे ब्लॉक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 के भूतल पर ग्राहवेट सं. जे-2 पर निर्मित फ्लैट का सम्पूर्ण भाग। सीमाएं : पूर्व : 15 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम : खाली भूमि, उत्तर : 15 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण : प्लॉट सं. 7ए ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 21.01.2020 को 11.45 बजे पूर्वाह्न से 1.15 बजे अपराह्न तक 10 मिनट के असीमित स्वतः विस्तार सहित। आरक्षित मूल्य ₹. 23,15,000/- जमा की जाने वाली धरोहर राशि : ₹. 2,31,500/- विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु कृपया [https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/nisha\\_enterprises.pdf](https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/nisha_enterprises.pdf)

कर्जदार तथा जमानती/यों के नाम

कर्जदार : 1. श्री रवीन्द्रनाथ चक्रवर्ती पुत्र श्री सुकुमार चक्रवर्ती, आर-359, सेक्टर-21, नोएडा-201301 2. श्रीमती रूमा चक्रवर्ती पत्नी रवीन्द्रनाथ चक्रवर्ती, आर-359, सेक्टर-21, नोएडा-201301

बकाया राशि- ₹. 13,11,481.00 + इस पर ब्याज एवं अन्य प्रभार

सम्पत्ति सं. 2 : एचआईजी फ्लैट सं. सी-503, प्लॉट सं. 508, एकांटिका अपार्टमेंट्स, सेक्टर-50, नोएडा, उत्तर प्रदेश ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 21.01.2020 को 11.45 बजे पूर्वाह्न से 1.15 बजे अपराह्न तक 10 मिनट के असीमित स्वतः विस्तार सहित। आरक्षित मूल्य ₹. 75,00,000/- जमा की जाने वाली धरोहर राशि : ₹. 7,50,000/- विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु कृपया [https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/rabindranath\\_chakraborty.pdf](https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/rabindranath_chakraborty.pdf)

कर्जदार तथा जमानती/यों के नाम

कर्जदार : 1. श्री दिग्विजय सिंह, फ्लैट सं. जी 1, प्लॉट सं. 390, सेक्टर 5, वैशाली, गाजियाबाद, 2. श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह पुत्र श्री दशरथ सिंह, म.नं. डी-20, गली नं. 3, ईस्ट विनोद नगर, सामने नेगी ज्वेलर्स, दिल्ली-110091, 3. श्री केदार नारायण चौधरी पुत्र श्री तेज नारायण चौधरी, 22, गली नं. 3, कुन्दन नगर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092

बकाया राशि- ₹. 4,36,782.37 + इस पर ब्याज एवं अन्य प्रभार

सम्पत्ति सं. 3 : आरसीए फ्लैट सं. जी-1/390, सेक्टर-5, वैशाली, गाजियाबाद ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 21.01.2020 को 11.45 बजे पूर्वाह्न से 1.15 बजे अपराह्न तक 10 मिनट के असीमित स्वतः विस्तार सहित। आरक्षित मूल्य ₹. 24,00,000/- जमा की जाने वाली धरोहर राशि : ₹. 2,40,000/- विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु कृपया [https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/digvijay\\_singh.pdf](https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/digvijay_singh.pdf)

कर्जदार तथा जमानती/यों के नाम

कर्जदार : मेहसाँ दीपन पेर सेल्लर, प्रो. श्री सतीश कुमार जैन, 9, मेलागाम मार्केट, चण्डीया बाजार, नई दिल्ली-110006 साथ ही मेहसाँ दीपन पेर सेल्लर, प्रो. श्री सतीश कुमार जैन, बिके-25, वेस्ट शालीमार बाजार, नई दिल्ली-110088 जमानती : श्रीमती मधु जैन पत्नी श्री सतीश कुमार जैन, बिके-25, वेस्ट शालीमार बाजार, नई दिल्ली-110088

बकाया राशि- ₹. 2,66,36,344.28 + इस पर ब्याज एवं अन्य प्रभार

सम्पत्ति सं. 3 : शालीमार बाग (पश्चिम), दिल्ली-110088 पर स्थित सम्पत्ति सं. 25, ब्लॉक-बीके का भाग, क्षेत्रफल माप 166 वर्ग मीटर पर निर्मित तीन वेड कम, एक ड्राइंगरूम-सह-ड्राइनिंग रूम, एक किचन, दो लैट्रिन एवं कमरों से जुड़ा अलग से बाथरूम से निर्मित सम्पूर्ण प्रथम तल (छह के अधिकार रहित एवं मेजनाइन फ्लोर के अधिकार सहित) ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 21.01.2020 को 11.45 बजे पूर्वाह्न से 1.15 बजे अपराह्न तक 10 मिनट के असीमित स्वतः विस्तार सहित। आरक्षित मूल्य ₹. 2,40,50,000/- जमा की जाने वाली धरोहर राशि : ₹. 24,05,000/- विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु कृपया [https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/deepti\\_paper\\_sales\\_1.pdf](https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/deepti_paper_sales_1.pdf)

तिथि : 17.12.2019 अधिकृत प्राधिकारी कांपोशन बैंक स्थान : नई दिल्ली

This is a public announcement for information purposes only and is not a prospectus announcement. This does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe for securities. Not for publication or distribution, directly or indirectly outside India.

**PRINCE PIPING SYSTEMS**

**PRINCE PIPES AND FITTINGS LIMITED**

Our Company was incorporated as Prince Pipes and Fittings Private Limited on November 13, 1987 at Mumbai, Maharashtra as a private limited company under the Companies Act, 1956. Thereafter, pursuant to Section 43A(1A) of the Companies Act, 1956, our Company became a deemed public limited company with effect from July 1, 1998. Further, pursuant to Section 43A(2A) of the Companies Act, 1956, our Company converted back into a private company on May 18, 2001. Subsequently upon conversion into a public limited company pursuant to a special resolution of our Shareholders dated August 7, 2017, the name of our Company was changed to Prince Pipes and Fittings Limited, and a fresh certificate of incorporation was issued by the Registrar of Companies, Goa, Daman and Diu ("RoC") on August 11, 2017. For further details in relation to changes in the name and registered office of our Company, see the section titled "History and Certain Corporate Matters" on page 174 of the red herring prospectus dated December 11, 2019 ("RHP").

Registered Office: Plot No 1, Honda Industrial Estate, Phase II, Honda Sattari, Honda, Goa 403 530, India.  
 Corporate Office: 8th Floor, The Ruby, Senapati Bagan Marg (Tali Pipe Road), Dadar West, Mumbai 400 028, Maharashtra, India.  
 Contact Person: Pravin Jogani, Company Secretary and Compliance Officer; Telephone: +91 22 66022222, Facsimile: +91 22 66022220; E-mail: investor@princepipes.com; Website: www.princepipes.com  
 Corporate Identity Number: U26932GA1987PLC000287

**PROMOTERS OF OUR COMPANY: JAYANT SHAMJI CHHEDA, TARLA JAYANT CHHEDA, PARAG JAYANT CHHEDA, VIPUL JAYANT CHHEDA AND HEENA PARAG CHHEDA**

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO [x] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH OF PRINCE PIPES AND FITTINGS LIMITED (OUR "COMPANY" OR THE "ISSUER" OR THE "ISSUER" AND SUCH EQUITY SHARES, THE "EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [x] PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [x] PER EQUITY SHARE (THE "OFFER PRICE"), AGGREGATING UP TO ₹ 5,000 MILLION (THE "OFFER"), COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO [x] EQUITY SHARES BY OUR COMPANY AGGREGATING UP TO ₹ 2,500 MILLION (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO [x] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 2,500 MILLION, INCLUDING UP TO [x] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 200 MILLION BY JAYANT SHAMJI CHHEDA, UP TO [x] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 1,400 MILLION BY TARLA JAYANT CHHEDA, UP TO [x] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 500 MILLION BY PARAG JAYANT CHHEDA AND UP TO [x] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 400 MILLION BY VIPUL JAYANT CHHEDA (TOGETHER, THE "PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS" AND SUCH OFFERS THE "OFFER FOR SALE"), THE OFFER CONSTITUTES [x] % OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

OUR COMPANY HAS, IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS ("BRLMS"), UNDERTAKEN A PRIVATE PLACEMENT OF 596,500 COMPULSORILY CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES, WHICH HAVE BEEN CONVERTED INTO 5,965,000 EQUITY SHARES FOR CASH CONSIDERATION AGGREGATING UP TO ₹ 1,061.77 MILLION ("PRE-IPO PLACEMENT"). THE SIZE OF THE FRESH ISSUE OF UP TO ₹ 3,561.77 MILLION HAS BEEN REDUCED BY ₹ 1,061.77 MILLION PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT AND ACCORDINGLY THE FRESH ISSUE IS UP TO ₹ 2,500.00 MILLION.

QIB Portion: Not more than 50% of the Offer  
 Retail Portion: Not less than 35% of the Offer  
 Non-institutional Portion: Not less than 15% of the Offer

Price Band: ₹ 177 to ₹ 178 per Equity Share of face value of ₹ 10 each.

The Floor Price is 17.70 times the face value of the Equity Shares and the Cap Price is 17.80 times the face value of the Equity Shares. Bids can be made for a minimum of 84 Equity Shares and in multiples of 84 Equity Shares thereafter.

**ASBA \* | Simple, Safe, Smart way of Application!!!**

\*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account. For further details, check section on ASBA below. Mandatory in public issues. No cheque will be accepted.

**UPI** UPI-Now available in ASBA for Retail Individual Bidders ("RIBs")\*\*  
 Applicants to ensure PAN is updated in Bank Account being Blocked by ASBA Bank.

\*ASBA has to be availed by all the investors except Anchor Investors. UPI may be availed by Retail Individual Bidders. For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA Form and abridged prospectus and also please refer to the section "Offer Procedure" beginning on page 380 of the RHP. The process is also available on the website of AIIB and Stock Exchanges in the General Information Document. ASBA Forms can be downloaded from the websites of BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE"), and together with BSE the "Stock Exchanges" and can be obtained from the list of banks that is displayed on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. \*\*List of banks supporting UPI is also available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. For the list of UPI Apps and Banks live on IPO, please refer to the link: www.sebi.gov.in. HDFC Bank Limited has been appointed as Sponsor Bank for the Offer. In accordance with the requirements of the SEBI Circular dated November 1, 2018. For issue related grievance investors may contact: JM Financial Limited - Prachee Dhuri (+91 22 6630 3262) (ppti\_ipo@jmf.com); Edelweiss Financial Services Limited - Yasraj Shetty (+91 22 4342 8202) (yasraj\_shetty@edelweissfint.com); Edelweiss Securities Limited - Madhur Tawde (+91 22 6626 4903) (Madhur\_Tawde@edelweissfint.com). Link Intime India Private Limited - Shanti Gopalkrishnan (+91 22 4918 6200) (princepipes\_ipo@linkintime.co.in). For UPI related queries, investors can contact NPCI at the toll free number: 18001201740 and Mail Id: ipo.upi@npci.org.in.

**Risks to Investors:**

- The two Book Running Lead Managers associated with the Offer have handled 27 public issues in the past three years out of which 5 closed below the issue price on listing date.
- The average cost of acquisition of per Equity Share for our Promoter Selling Shareholders is ₹0.10 for Jayant Shamji Chheda, ₹0.62 for Tarla Jayant Chheda, and ₹0.12 for Parag Jayant Chheda and ₹0.12 for Vipul Jayant Chheda, and the Offer Price at the upper end of the Price Band is significantly high at ₹178 per Equity Share.

**BID/OFFER PROGRAMME**

**BID/OFFER OPENS ON WEDNESDAY, DECEMBER 18, 2019**

**BID/OFFER CLOSES ON FRIDAY, DECEMBER 20, 2019**

ADDENDUM-CUM-CORRIGENDUM — NOTICE TO INVESTORS

In reference to the RHP filed with the RoC, the SEBI and the Stock Exchanges, investors should note the following:

(a) Our Company has received an intimation dated December 17, 2019 from two of our Promoter Selling Shareholders, Parag Jayant Chheda and Vipul Jayant Chheda ("Sellers") stating that they have entered into a share purchase agreement dated December 16, 2019 ("SPA") with Oman India Joint Investment Fund II, a trust registered as a Category II-AIF, acting through its investment manager, Oman India Joint Investment Fund-Management Company Private Limited ("Purchaser") in relation to transfer of 2,809,018 Equity Shares by the Sellers on December 18, 2019 ("Effective Date"), for cash, at a price of ₹178 per Equity Share, aggregating to approximately ₹500.00 million. Pursuant to the SPA, each of the Sellers has agreed to transfer 1,404,509 Equity Shares to the Purchaser (the "Transfer") on the Effective Date. Please note that these Equity Shares do not form part of the Equity Shares proposed to be offered by Sellers, as a part of the Offer for Sale in the Offer. Further, please note that the Equity Shares that will be transferred pursuant to the Transfer, being the pre-Offer equity share capital held by persons other than the Promoters, shall be subject to lock-in, in accordance with Regulation 17 of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018.

(b) Further, our Company has received a no objection certificate dated December 13, 2019 from the Chief Fire Officer, Haridwar, Uttarakhand, in relation to our plant in Haridwar. Accordingly, the table under '4. Haridwar' on page 350 of the RHP should be read along with the following as S. No. 8:

S. No.	Details of License	Date of expiry
8.	NOC issued by the Chief Fire Officer, Haridwar, Uttarakhand.	December 13, 2020

(c) Please note that details in footnote number 5 on page 70 of the RHP, should be read as follows: "Our Company has granted 900,028 options to its eligible employees, in accordance with ESOP 2017 and applicable law, of which 654,092 options are in force as on December 9, 2019. This figure does not factor in the Equity Shares that may be issued pursuant to exercise of such options, once they are vested, or options that may have been forfeited, lapsed or cancelled. For further details, see section titled "Capital Structure" on page 81."

(d) The maximum bid by a Non-Institutional Bidders on page 377 of the RHP shall be read as follows: "Such number of Equity Shares not exceeding the size of the Offer (excluding the QIB portion), subject to applicable limits."

(e) With respect to point 1 under "VI. Litigation included in complaints" on page 346 of the RHP, after the words "₹ 5.31 million" the following shall be inserted: "and approximately ₹ 42.75 million, pursuant to these matters"

The above notice is to be read in conjunction with the RHP, Offer related advertisements, Bid cum Application Forms, and the abridged prospectus, and the RHP stands updated to the extent set out above. All capitalized terms used in this addendum-cum-corrigendum shall, unless the context otherwise requires, have the same meanings as ascribed to such terms in the RHP.

Place: Mumbai  
 Date: December 17, 2019

For PRINCE PIPES AND FITTINGS LIMITED  
 On behalf of the Board of Directors  
 Sd/-  
 Company Secretary & Compliance Officer

Prince Pipes and Fittings Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its equity shares ("Equity Shares") and has filed the RHP with the Registrar of Companies, Goa, Daman and Diu. The RHP is available or will be made available on the websites of the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") at www.sebi.gov.in, BSE Limited at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com as well as on the respective websites of the book running lead managers, i.e., JM Financial Limited at www.jmf.com and Edelweiss Financial Services Limited at www.edelweissfint.com. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see the section titled "Risk Factors" on page 17 of the RHP. Potential investors should not rely on the draft red herring prospectus filed with SEBI for any investment decision. The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), or the laws of any state of the United States and may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. The Equity Shares are being offered and sold only outside the United States pursuant to Regulation S under the U.S. Securities Act and pursuant to the applicable laws of the jurisdictions where those offers and sales are made.

CONCEPT

## खबर कोना



भारत- वेस्ट इंडीज के बीच होने वाले दूसरे एक दिवसीय मैच से पहले विशाखापत्तनम में मंगलवार को अभ्यास के दौरान कुलदीप यादव।

## राइनोज विंग बाउट लीग के सेमीफाइनल में

नई दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा)।

इग्राशेव तैमूर की जीत के साथ ही नार्थइस्ट राइनोज ने मंगलवार को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेले गए विंग बाउट इंडियन मुक्केबाजी लीग (आइबीएल) मैच में पंजाब पैथर्स को 4-3 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। इस जीत के साथ राइनोज के 19 अंक हो गए हैं और वह सेमीफाइनल में पैथर्स से ही भिड़ेगा। पैथर्स और बॉम्बे बुलेट्स ने लीग चरण का अंत 18-18 अंकों के साथ किया। लेकिन जनों द्वारा ज्यादा अंक दिए जाने के कारण पैथर्स को तीसरा स्थान मिला। इसका मतलब है कि सेमीफाइनल में बॉम्बे को गुजरात जाएंगे से भिड़ना होगा जिसने लीग चरण का अंत 22 अंकों के साथ किया।

## मोहन बागान के अध्यक्ष गीतानाथ गांगुली का निधन

कोलकाता, 17 दिसंबर (भाषा)।

मोहन बागान के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति गीतानाथ गांगुली का दिल का दौरा पड़ने से मंगलवार को निधन हो गया। क्लब के सूत्रों ने यह जानकारी दी। प्रतिष्ठित वकील रहे 83 साल के गांगुली को इस महीने सड़क दुर्घटना में पैर में चोट लगी थी जब उनकी कार को पीछे से किसी अन्य वाहन ने टक्कर मार दी थी। इसके बाद गांगुली का आपरेशन किया गया था लेकिन वह इससे कभी नहीं उबर सके। क्लब के अधिकारी ने कहा, 'सुबह उनके सीने में दर्द हुआ और अस्पताल जाने के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली।'

## विश्व कप से पहले वापसी की संभावना तलाश रहे डिविलियर्स : डुल्लेसी

जोहानिसबर्ग, 17 दिसंबर (भाषा)।

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फाफ डुल्लेसी ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका के आक्रामक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप से पहले वापसी की संभावना तलाश रहे हैं। डुल्लेसी ने कहा कि अगले साल अक्टूबर में होने वाले टी20 विश्व कप से पहले डिविलियर्स से पिछले तीन महीने से बात चल रही है। उन्होंने कहा, 'लोग चाहते हैं कि एबी खेलें और मैं भी यही चाहता हूँ।' उन्होंने कहा, 'पिछले दो तीन महीने से उनसे बात चल रही है। टी20 क्रिकेट में ज्यादा समय घर से बाहर नहीं रहना होता। पूर्णकालिक क्रिकेटर होने पर आपको काफी समय बाहर बिताना होता है। इस बारे में बातचीत हुई है और अगली टी20 श्रृंखला तक चलती रहेगी।'

## युवराज ने कहा, टी20 टीम विश्व कप से चार महीने पहले तैयार हो

नई दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय टीम के पूर्व स्टार खिलाड़ी युवराज सिंह और आफ स्पिनर हरभजन सिंह ने मंगलवार को कहा कि टी20 विश्व कप के लिए विराट कोहली की अगुवाई वाली भारतीय टीम टूर्नामेंट से चार महीने पहले तैयार हो जानी चाहिए। युवराज ने एक चैनल के कार्यक्रम में कहा, 'मुझे लगता है कि टीम को विश्व कप से चार महीने पहले तैयार हो जाना चाहिए। मेरा मतलब है

आपको पता होना चाहिए कि टीम के साथ कौन से 16 या 14 खिलाड़ी जाएंगे। मुझे लगता है हमें विश्व कप से पहले तैयार रहना चाहिए।' भारतीय टीम विश्व कप की तैयारियों के मद्देनजर कई युवा खिलाड़ियों को आजमा रही है। भारत को 2011 में एकदिवसीय विश्व चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले युवराज ने

इस मौके पर हरफनमौला शिवम दुबे का समर्थन करते हुए कहा कि वे बायें हाथ के ऐसे बल्लेबाज हैं जो गेंदबाजी भी कर सकते हैं। उनका टीम में रहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि शिवम दुबे के साथ फिटनेस की समस्या है। युवराज के साथी हरभजन सिंह ने भी ऐसे ही विचार जाहिर किए। उन्होंने कहा, 'टीम पहले से संयोजित होनी चाहिए और खिलाड़ियों को पता होना चाहिए कि वे विश्व कप में खेलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के मन में टीम में जगह को लेकर आशंका हो।' उन्होंने कहा, 'खिलाड़ियों को टीम में अपनी भूमिका के बारे में पता होना चाहिए। भूमिका के बारे में स्पष्टता होने से टीम के प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।'

## बोले हरभजन

टीम पहले से संयोजित होनी चाहिए और खिलाड़ियों को पता होना चाहिए कि वे विश्व कप में खेलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के मन में टीम में जगह को लेकर आशंका हो।' उन्होंने कहा, 'खिलाड़ियों को टीम में अपनी भूमिका के बारे में पता होना चाहिए। भूमिका के बारे में स्पष्टता होने से टीम के प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।'



## गेंदबाजी में सुधार से वापसी पर निगाहें

टीम इंडिया को गेंदबाजी संयोजन दुरुस्त करना होगा

दोपहर 01:30 बजे से शुरू होगा मैच

विशाखापत्तनम, 17 दिसंबर (भाषा)।

वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत दर्ज कर श्रृंखला में वापसी की कोशिशों में जुटी भारतीय टीम को आज दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अपने गेंदबाजी संयोजन में सुधार करना होगा। हालांकि विराट कोहली या रोहित शर्मा को रोकना वेस्ट इंडीज के लिए आसान नहीं होगा।

भारतीय गेंदबाजी पहले मैच में खराब नहीं थी, लेकिन 287 रन बनाने के बावजूद जीत नहीं पाई। एसीए वीडियोए स्टेडियम पर 320 रन का स्कोर अच्छा माना जा रहा है लिहाजा पांचवें गेंदबाजी विकल्प को उतारा जा सकता है। पिछले मैच में शिमरोन हेटमायरे और शाइ होप के शतकों की मदद से वेस्ट इंडीज ने लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया था।

स्पिनर रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव पिछले मैच में नाकाम रहे जिन्होंने दस दस ओवरों में 58 और 45 रन दे डाले और उन्हें विकेट भी नहीं मिले। शिवम दुबे ने 7.5 ओवरों में 68 रन दिए।

भारत के पास रिजर्व खिलाड़ियों में सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल हैं लेकिन रोहित और केएल राहुल के शानदार फार्म को देखते हुए उनके खेलने की संभावना कम ही है। मनीष पांडे मध्यक्रम के बल्लेबाज हैं जो छोटे नंबर पर केदार जाधव की ही जगह ले सकते हैं। जाधव ने हालांकि चेन्नई में 33 गेंद में 40 रन बनाए।

विशेषज्ञ पांचवें गेंदबाज के रूप में विकल्प तेज गेंदबाज शार्दूल ठाकुर या लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल हैं। इनमें से एक को चुनने पर दोनों हरफनमौलाओं दुबे या रविंद्र जडेजा में से एक को बाहर किया जा सकता है। दुबे पिछले मैच में आठवें नंबर पर उतरे थे।

वेस्ट इंडीज की टीम 1960 के दशक के महान खिलाड़ी बासिल बूचर के सम्मान में बांह पर काली पट्टी बांधकर खेलेगी। 86 साल के बूचर का सोमवार को निधन हो गया था।



दूसरे एकदिवसीय मैच से पहले मंगलवार को प्रैक्टिस के दौरान ऋषभ पंत

भारत : विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, ऋषभ पंत, शिवम दुबे, केदार जाधव, रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, दीपक चाहर, मोहम्मद शमी और शार्दूल ठाकुर।  
वेस्ट इंडीज : कीरोन पोलार्ड (कप्तान), सुनील अंबरीश, शाइ होप, खैरी पियरे, रोस्टन चेस, अल्जारी जोसेफ, शेल्डन कोटरेल, ब्रैंडन किंग, निकोलस पूरन, शिमरान हेटमायर, एविन लुईस, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, कीमो पाल और हेडन वाल्शा जूनियर।

## कपिल, गायकवाड़ को आचरण अधिकारी के समक्ष पेश होने का नोटिस

नई दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा)।

बीसीसीआइ के आचरण अधिकारी डी.के. जैन ने कपिल देव और अंशुमान गायकवाड़ को हितों के टकराव के आरोप में मुंबई में उनके समक्ष पेश होने को कहा है। हालांकि ये दोनों खिलाड़ी क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) से पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं।

सीएसी में कपिल और गायकवाड़ के अलावा महिला टीम की पूर्व कप्तान शांता रंगास्वामी शामिल थी जिन्होंने सितंबर में जैन से हितों के टकराव का नोटिस मिलने पर इस्तीफा दे दिया था। यह नोटिस मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एमपीसीए) के आजीवन सदस्य संजीव गुप्ता की शिकायत पर जारी किया गया था। सीएसी का अब कोई अस्तित्व नहीं है लेकिन इन दोनों पूर्व खिलाड़ियों को 27 और 28 दिसंबर को जैन के सामने पेश होने का नोटिस मिला है।

## दिल्ली 215 पर आउट, आंध्र को भी दिए झटके

आंगोल, 17 दिसंबर (भाषा)।

श्रीष क्रम के बल्लेबाजों की नाकामी के कारण दिल्ली की टीम रणजी ट्रॉफी ग्रुप ए क्रिकेट मैच में मंगलवार को यहां पहली पारी में 215 रन पर आउट हो गई लेकिन उसने आंध्र की सलामी जोड़ी को पर्वेलियन भेजकर पहले दिन का सुखद अंत किया। पवन सुयाल और नवदीप सैनी ने पांच ओवर के अंदर ही आंध्र के दोनों सलामी बल्लेबाजों डीवी प्रशांत (शून्य) और सीआर गणेश्वर (नौ) को आउट कर दिया। आंध्र ने स्टंप उखड़ने तक दो विकेट पर 16 रन बनाए थे। जी मनीष तीन रन पर खेल रहे हैं जबकि कप्तान हनुमा विहारी को खाता खोलना है।

दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर तीन विकेट 69 रन पर गंवा दिए। सलामी बल्लेबाज अनुज रावत (29) और तीसरे नंबर पर उतरे हितेन दलाल (19) अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा पाए। कप्तान नितीश राणा (51) और कुंवर बिधुड़ी (22) ने चौथे विकेट के लिए 60 रन जोड़े जो दिल्ली की तरफ से सबसे बड़ी साझेदारी थी।

## कर्नाटक ने दृष्टिहीन महिला क्रिकेट में दिल्ली को हराया

नई दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा)।

दीपिका की शानदार पारी के दम पर कर्नाटक ने मंगलवार को दिल्ली को सात विकेट से हराकर दृष्टिहीन महिला राष्ट्रीय टी-20 टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। कर्नाटक की टीम ने 117 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 17 रन पर ही दो विकेट गंवा दिए थे लेकिन दीपिका ने वर्षों के साथ तीसरे विकेट के लिए 75 रन की साझेदारी कर मैच का पासा पलट दिया। दीपिका ने 42 और वर्षों ने 37 रन बनाए। इससे पहले दिल्ली की टीम ने नौ विकेट पर 116 रन बनाए थे।

एक अन्य मैच में ओडिशा ने केरल को 180 रन से हराकर बड़ी जीत दर्ज की। खिलाव की प्रबल दावेदार ओडिशा की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन विकेट पर 279 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। उसकी तरफ से बसंती हांस्दा ने 82 और मुनी पुर्ती ने 50 रन बनाए। इसके जवाब में केरल की टीम 20 ओवरों में आठ विकेट पर 99 रन ही बना सकी।

एलिस पेरी साल की सर्वश्रेष्ठ एकदिवसीय खिलाड़ी चुनी गई

आइसीसी टीम

वहीं वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर चुना गया एलिसा हीली को

## स्मृति मंधाना को वनडे और टी20 टीम में मिली जगह

दुबई, 17 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) की साल की एकदिवसीय और टी20 टीम में शामिल किया गया है। एकदिवसीय टीम में मंधाना के साथ झूलन गोस्वामी, पूनम यादव और शिखा पांडे को भी जगह मिली है जबकि टी20 टीम में उनके साथ हरफनमौला दीप्ति शर्मा हैं।

23 साल की मंधाना ने 51 एकदिवसीय और 66 टी20 अंतरराष्ट्रीय के अलावा दो टैस्ट मैच में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने एकदिवसीय और टी20 में 3476 रन बनाए हैं। इस साल की शुरुआत में श्रीलंका के खिलाफ रेकार्ड 148 रन की पारी खेलने वाली आस्ट्रेलिया



एकदिवसीय टीम में मंधाना के साथ झूलन गोस्वामी, पूनम यादव और शिखा पांडे को भी जगह मिली है जबकि टी20 टीम में उनके साथ हरफनमौला दीप्ति शर्मा हैं।



23 साल की मंधाना ने 51 एकदिवसीय और 66 टी20 अंतरराष्ट्रीय के अलावा दो टैस्ट मैच में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। उन्होंने एकदिवसीय और टी20 में 3476 रन बनाए हैं।

की एलिसा हीली को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर चुना गया।

आस्ट्रेलिया की एलिसा पेरी को साल की सर्वश्रेष्ठ एकदिवसीय खिलाड़ी चुनी गई है। इस हरफनमौला खिलाड़ी के नाम 2019 में 73.50 की औसत से 441 रन बनाने के अलावा 13.52 की औसत से 21 विकेट भी है।

आस्ट्रेलिया की ही मेग लेनिंग को एकदिवसीय और टी 20 दोनों टीमों का कप्तान चुना गया है। पेरी को इसके साथ ही सभी प्रारूप को मिलाकर दिए जाने वाले रशेल हेहोर्ड-प्लेट पुरस्कार (साल का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर) के लिए चुना गया। वर्ष के उभरती हुई क्रिकेटर का पुरस्कार थाईलैंड की चानिडा सुथिरयुंग को दिया गया। 26 साल की इस तेज गेंदबाज ने इस साल आइसीसी महिला टी20 विश्व कप क्वालीफायर में 12 विकेट लिए थे।

## साल के सर्वश्रेष्ठ जूनियर फ्रीस्टाइल पहलवान बने दीपक पूनिया

नई दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा)।

विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता दीपक पूनिया को यूनाईटेड विश्व कुश्ती (यूडब्ल्यूडब्ल्यू) ने साल का सर्वश्रेष्ठ जूनियर फ्रीस्टाइल पहलवान चुना है। पूनिया ने पिछले सत्र में शानदार प्रदर्शन किया और इस दौरान सफलतापूर्वक जूनियर से सीनियर सर्किट में जगह बनाने में सफल रहे।

पूनिया सत्र में शानदार प्रदर्शन करते हुए 18 साल में जूनियर विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बने। इसके बाद उन्होंने सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदार्पण करते हुए रजत पदक जीता। पूनिया ने कहा, 'मैं बेहद खुश हूँ। दुनिया भर के

पहलवानों के बीच से चुना जाना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। अपने प्रदर्शन में सुधार करने और अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए यह मेरे लिए प्रेरणा का बड़ा स्रोत है।' भारतीय पहलवान नूर सुल्तान में विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय था। चोट के कारण पूनिया फाइनल में ईरान के हसन याजदानी के खिलाफ मैच पर नहीं उतर पाए थे।



दीपक नूर सुल्तान में विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय था।

## बीडब्लूएफ रैंकिंग

## लक्ष्य सेन नौ स्थान के फायदे से करिअर के सर्वश्रेष्ठ 32वें स्थान पर

नई दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन विश्व बैडमिंटन महासंघ (बीडब्लूएफ) की मंगलवार को जारी नवीनतम रैंकिंग में पुरुष एकल वर्ग में करिअर के सर्वश्रेष्ठ 32वें स्थान पर पहुंच गए हैं। लक्ष्य ने रविवार को बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय चैलेंज का खिताब जीता था जो पिछले साल टूर्नामेंटों में उनका पांचवां खिताब है।

भारत के 18 साल के लक्ष्य ने टाका में फाइनल में मलेशिया के लियोंग जुन हाओ को 22-20 21-18 से हराकर खिताब जीता। लक्ष्य ने साल का अपना पहला खिताब सितंबर में बेल्जियम इंटरनेशनल टूर्नामेंट के रूप में जीता। इसके बाद उन्होंने अक्टूबर में डच ओपन सुपर 100 और सारलोरलक्स सुपर 100 का खिताब जीतने के बाद नवंबर में स्काटिश ओपन का खिताब भी अपने नाम किया।

पुरुष एकल में बी साई प्रणीत और किदांबी श्रीकांत क्रमशः 11वें और 12वें स्थान पर बरकरार हैं। पारूपल्ली कश्यप 23वें स्थान पर



बने हुए हैं जबकि उनके बाद एचएस प्रणय (26वें), सीरभ वर्मा (28वें), समीर वर्मा (33वें) और शुभंकर डे (44वें) का नंबर आता है। महिला एकल खिलाड़ियों में ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और साइना नेहवाल क्रमशः छठे और 11वें स्थान पर बरकरार हैं। पुरुष युगल में कोई भारतीय जोड़ी शीर्ष 10 में नहीं है। सात्विकसाईंया रंकीरेड्डी और चिराम शेट्टी की जोड़ी 12वें स्थान पर है।

## भारत ने थाईलैंड को हराया, फाइनल में स्वीडन से भिड़ेगा

मुंबई, 17 दिसंबर (भाषा)।

कृतिना देवी के आखिरी क्षणों में किए गए गोल से भारत ने मंगलवार को आखिरी राउंड रोबिन लीग मैच में थाईलैंड को 1-0 से हराकर तीन दशकों के अंदर-17 महिला फुटबल टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई जहां उनका सामना गुरुवार को स्वीडन से होगा।

मैच का एकमात्र गोल कृतिना ने 90+1 मिनट में किया। उन्होंने तब विरोधी टीम की गोलकीपर पावरिसा होमियामियेन की गलती का फायदा उठाया। थाईलैंड को उनकी यह गलती महंगी पड़ी क्योंकि मैच ड्रा होने पर उनकी टीम फाइनल में पहुंच जाती। कृतिना के लंबे शाट का थाई गोलकीपर सही अनुमान नहीं लगा पाई और गेंद गोल के अंदर चली गई।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 31, हवाई शुल्क : इंग्लिश-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।

दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा-201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोन: (0120) 2470700/2470740, ई-मेल: edit.jansatta@expressindia.com, फैक्स: (0120) 2470753, 2470754, बोर्ड अध्यक्ष: विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादक: मुकुंद भारद्वाज, \*पीआरटी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेदार। कापीराइट: दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।